LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT

कांग्रेसः ढाक के तीन पात

खास बातचीत रिया चक्रवर्ती

स्थानीय कोटे का शिगूफा

9 सितंबर, 2020 40 रुपए

इंडिया टुडे

अर्थव्यवस्था

विकट संकट

क्या हो इलाज

RNI NO. 45823/86 REGISTERED NO. FARIDABAD/46/2020-22; DL(ND)-11/6042/2018-20; U(O)-31/2018-20

www.indiatodayhindi.in

OC

VISIT…

INDIA TODAY

BREAKING NEWS

JUST A TAP AWAY

DOWNLOAD THE APP NOW

AVAILABLE ON

आज तक

देश का नं. 1 हिंदी न्यूज़ ऐप

जुड़े रहिए हर खबर से,
कहीं भी, कभी भी

अभी डाउनलोड करें

aajtak.in/app

उपलब्ध है

ZEE LABORATORIES

करोड़ो लोगो का आज़माया

झुर्रियां | काले घेरे | छाईंया

MYFAIR

रूप संवारे, त्वचा निखारे

- क्रीम
- साबुन
- फेस वाश
- सन स्क्रीन

सम्पूर्ण कॉस्मेटिक रेंज
हर प्रमुख दवा विक्रेता के यहां उपलब्ध
9896134500

A Product of
ZEE LABORATORIES LTD.

Online Shopping:
www.myfair.in

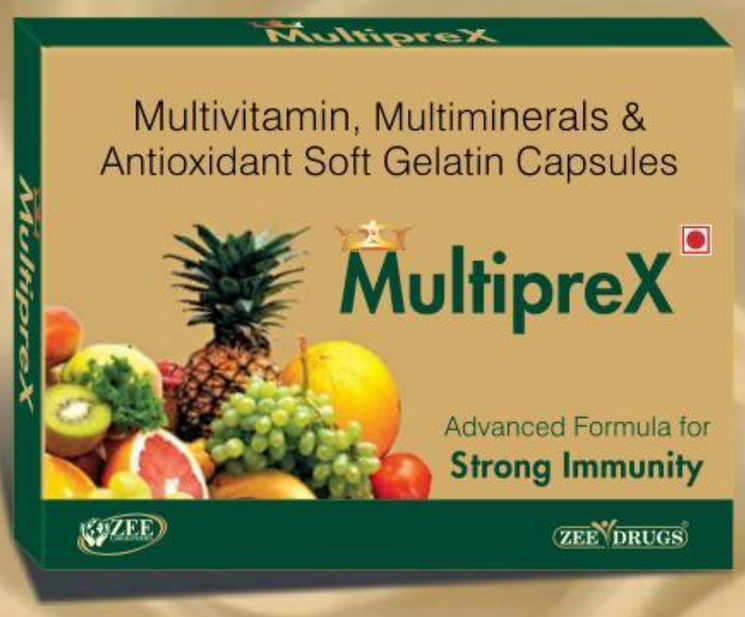

रोजाना सेवन करे
9896134500
हर प्रमुख दवा विक्रेता के यहां उपलब्ध

रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाए

MultipreX™

कैप्सूल, सिरप, ओरल ड्राप्स, पाउडर

Natural Immunity Booster

प्रतिरक्षा में सुधार, विटामिन और मिनरल की कमी को पूरा कर रोगों से बचाए

प्रधान संपादक की कलम से

इन गर्मियों में देश कोविड-19 महामारी से मुकाबिल हुआ तो सरकार को जिंदगी और आजीविका में से चुनने का कठिन फैसला करना था. जाहिर है, उसने जिंदगी बचाना ही चुना क्योंकि 31 मई तक चार चरणों में सबसे सख्त, अप्रत्याशित लॉकडाउन लगाया गया, जिसके फायदों पर अब भी बहस जारी है. आश्चर्यजनक रूप से विकासशील देशों की तुलना में धनी देश अपनी अर्थव्यवस्थाओं पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं.

दुर्भाग्य से, अब लॉकडाउन बीमारी से महंगा बचाव जैसा साबित हुआ है. देश में अब तक महामारी 60,000 लोगों की जान ले चुकी है और तकरीबन 30 लाख लोग संक्रमण के शिकार हो चुके हैं. यह आंकड़ा दुनिया में अमेरिका और ब्राजील के बाद तीसरे नंबर का है. अलबत्ता लॉकडाउन ने अर्थव्यवस्था की चूलें हिला दीं. सभी संकेत यही हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था मंदी की ओर बढ़ चली है, जो दो तिमाही या छह महीने की लगातार नकारात्मक आर्थिक वृद्धि के साथ आमदनी, बिक्री और रोजगार घटने से कही जाती है. इससे हालात और बदतर हुए कि मौजूदा वित्त वर्ष के शुरू होने के पहले ही आठ में से सात तिमाहियों में अर्थव्यवस्था में गिरावट दर्ज हो रही थी—2018 के जनवरी-मार्च में 8.2 फीसद से घटकर 2020 जनवरी-मार्च में महज 3.1 फीसद रह गई थी. 6 अगस्त को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि देश की वास्तविक जीडीपी वृद्धि के ''सिकुड़न के दायरे में रहने का अनुमान है,'' और वित्त वर्ष 2020-21 में वृद्धि भी नकारात्मक रहेगी. 26 अगस्त को जारी आरबीआइ की वार्षिक रिपोर्ट का भी अनुमान है कि महामारी और सख्त लॉकडाउन से खपत को गहरा झटका लगेगा.

लॉकडाउन, वैश्विक व्यापार में गिरावट और निवेश के घटने जैसे तिहरे झटके का मतलब है कि हमारा सामना चार दशकों में पहली दफा आर्थिक 'नकारात्मक वृद्धि' से है. पिछली बार यह तेल के झटके से आए भुगतान संतुलन संकट और लगातार दो साल खराब मॉनसून की वजह से 1979-80 में आया था. इस साल तो आजादी के बाद सबसे बुरी मंदी दिख सकती है. आरबीआइ की रिपोर्ट कोई आंकड़ा नहीं देती है, मगर आइएमएफ के जून 2020 के लिए विश्व आर्थिक नजरिए में अनुमान है कि भारत की वित्त वर्ष 2020-21 में सालाना वृद्धि दर नकारात्मक -4.5 पर पहुंच जाएगी. अर्थशास्त्रियों में आम राय है कि मौजूदा वित्त वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही में अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर -13 और -23 के बीच है.

देश की अर्थव्यवस्था अपनी वृद्धि के चारों इंजनों—घरेलू खपत, सरकारी खर्च, निजी निवेश और निर्यात—के बैठ जाने से धराशायी हो गई है. घरेलू खपत मई-जून में हल्की उभार के बाद फिर सिकुड़ गई; सरकारी खर्च इन्फ्रास्ट्रक्चर के मद में आवंटन के बावजूद राज्यों के खर्च में कटौती से प्रभावित हुआ; निजी निवेश इसलिए घटा कि उद्योग का मनोबल टूटा हुआ है और एमएसएमई क्षेत्र को कर्ज अदायगी में मोरेटेरियम जैसी राहत देने के बावजूद कंपनियां उत्पादन बढ़ाने की जगह नकदी बचा रही हैं. निर्यात जुलाई में लगातार पांचवे महीने भी सिकुड़ा रहा क्योंकि लॉकडाउन से रत्न-जेवरात, चमड़ा, कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक सामान और मसाले के निर्यात पर बुरा असर पड़ा. इकलौती उम्मीद की किरण अच्छे मॉनसून की वजह से कृषि में दिख रही है. लेकिन अकेला इंजन अर्थव्यवस्था को गर्त से निकालने के लिए नाकाफी है क्योंकि कृषि जीडीपी में 15 फीसद का योगदान देती है.

आर्थिक मुसीबत कई मोर्चों पर महसूस की जा रही है—नौकरियों के खत्म होने, वेतन कटौती और मांग तथा लॉकडाउन से पस्त आपूर्ति शृंखला की वजह से बढ़ी महंगाई. इस मई में घोषित सरकार के 20 लाख करोड़ रु. के पैकेज का खास फर्क नहीं दिखा. बेकाबू कोविड-19 अब पहले और दूसरे दर्जे के शहरों में कहर बरपा रहा है, जिससे राज्य और सख्त लॉकडाउन को मजबूर हो रहे हैं. देश अब महामारी पर काबू पाने, खासकर प्रवासी मजदूरों के रोजगार बहाल करने, आपूर्ति शृंखला को दुरुस्त करने, अर्थव्यवस्था और जिंदगी को सामान्य बनाने की महती चुनौती से जूझ रहा है. फिर झगड़ालू चीन से भारतीय अर्थव्यवस्था को बचाने की दूसरी चुनौती है, जो हमारे पूर्वी लद्दाख की सीमा पर फौज ले आया है.

हमारी आवरण कथा 'विकट संकट' पड़ताल करती है कि संकट कब तक रहेगा और क्या उपाय हैं. इसे एग्जीक्यूटिव एडिटर एम.जी. अरुण और डिप्टी एडिटर श्वेता पुंज के साथ सीनियर एडिटर अनिलेश एस. महाजन ने कलमबंद किया है. हमने अपनी आर्थिक इमरजेंसी के इलाज के लिए बोर्ड ऑफ इंडिया टुडे इकोनॉमिस्ट (बाइट) से सलाह ली.

हमारे बाइट की आम राय है कि सरकार का 'अदृश्य हाथ' अब अधिक दिखना चाहिए और नीतियों पर पुनर्विचार की जरूरत है. सरकार न सिर्फ मुफ्त राशन के साथ प्रत्यक्ष आय हस्तांतरण में तेजी लाए, बड़े प्रोत्साहन पैकेज, एमएसएमई की मदद, मांग में इजाफे के उपाय और ऐसा माहौल बनाए, जिससे निजी निवेश लौटे. उसे बिजली, दूरसंचार, इन्फ्रास्ट्रक्चर वित्त पोषण में सुधार की जरूरत है. तटीय आर्थिक क्षेत्र के बारे में नीति बनाने की जरूरत है.

अर्थव्यवस्था में उठान का रुझान नहीं दिखता है तो खतरा है कि हम कर्ज बम पर बैठे होंगे. बैंकों का डूबत कर्ज (एनपीए) करीब दोगुना हो जा सकता है (फिलहाल 9-10 लाख करोड़ रु. होने का अनुमान है). इससे बैंकों के कामकाज और कर्ज देने की क्षमता कम होगी और संकट गहरा हो जाएगा. सरकार के हाथ तंग हैं इसलिए उसे प्रशासकीय खर्च घटाने पर सोचना चाहिए. केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर खर्च 2008-09 में 67,463 करोड़ रु. से 187 फीसद बढ़कर 2018-19 में 1.94 लाख करोड़ रु. हो गया. घटाने का फायदा लालफीताशाही पर कैंची के रूप में भी होगा, जो हमारे जानदार उद्यमियों की राहें रोकता है. सार्वजनिक उपक्रमों के आक्रामक विनिवेश कार्यक्रम से भी सरकार का खजाना बढ़ेगा.

वक्त बहुत मायने रखता है. सरकार अगर महामारी पर काबू पाने और मंदी के छंटने का इंतजार करती है तो काफी देर हो सकती है. यह इकलौती वजह ही काम में जुट जाने की प्रेरणा होनी चाहिए.

तब्लीगी जमात की हकीकत
भगवान के घर सुनसान
22 अप्रैल, 2020
40 रुपए
इंडिया टुडे
अर्थव्यवस्था
उबरने की चुनौती
कोरोना से जूझ रहे भारत को फिर से सक्रिय बनाने के लिए मोदी सरकार को क्या करना चाहिए
www.indiatodayhindi.in
22 अप्रैल, 2020 का आवरण

(अरुण पुरी)

इंडिया टुडे

www.indiatodayhindi.in

प्रधान संपादक: अरुण पुरी
ग्रुप एडिटोरियल डायरेक्टर: राज चेंगप्पा
एडिटर: अंशुमान तिवारी
सीनियर एडिटर: मोहम्मद वक़ास
एसोसिएट एडिटर: शिवकेश मिश्र, शुभम शंखधर
असिस्टेंट एडिटर: मनीष दीक्षित, सुजीत ठाकुर
विशेष संवाददाता: संध्या द्विवेदी
राज्य ब्यूरो: आशीष मिश्र (लखनऊ), अमिताभ श्रीवास्तव (पटना), रोहित परिहार (जयपुर), एम.जी. अरुण (मुंबई), राहुल नरोन्हा (भोपाल), अमरनाथ के. मेनन (हैदराबाद)
ग्रुप क्रिएटिव एडिटर: नीलांजन दास
एसोसिएट आर्ट डायरेक्टर: चंद्रमोहन ज्योति
चीफ डिजाइनर: असित रॉय
ग्रुप फोटो एडिटर: बंदीप सिंह
फोटो डिपार्टमेंट: विक्रम शर्मा, सुबीर हलदर, चंद्रदीप कुमार, शैलेश रावल (अहमदाबाद), मंदार देवधर (मुंबई)
चीफ फोटो रिसर्चर: प्रभाकर तिवारी
प्रिंसिपल फोटो रिसर्चर: सलोनी वैद
सीनियर फोटो रिसर्चर: शुभ्रोजीत ब्रह्मा
प्रोडक्शन चीफ: अभिनव पुगला
पब्लिशिंग डायरेक्टर: मनोज शर्मा
एसोसिएट पब्लिशर: अनिल फर्नांडीस
इंपैक्ट टीम: सीनियर जनरल मैनेजर: जीतेंद्र लाड (वेस्ट)
जनरल मैनेजर: मयूर रस्तोगी (नॉर्थ), उपेंद्र सिंह (बेंगलूरू), कौशिकी गांगुली (ईस्ट)
ग्रुप चीफ मार्केटिंग ऑफिसर: विवेक मल्होत्रा
सेल्स एवं ऑपरेशन
सीनियर जनरल मैनेजर: दीपक भट्ट (नेशनल सेल्स)
जनरल मैनेजर: विपिन बग्गा: (ऑपरेशंस)
डिप्टी जनरल मैनेजर: राजीव गांधी (नॉर्थ)
रीजनल सेल्स मैनेजर: सैयद आसिफ सलीम (वेस्ट)
डिप्टी रीजनल सेल्स मैनेजर: एस. परमशिवम (साउथ)
सीनियर सेल्स मैनेजर: पीयूष रंजन दास (ईस्ट)

INDIA TODAY GROUP

वर्ष: 34; अंक: 43; 3-9 सितंबर, 2020; प्रत्येक शनिवार को प्रकाशित

- **संपादकीय कॉर्पोरेट कार्यालय:** लिविंग मीडिया इंडिया लिमिटेड, इंडिया टुडे ग्रुप मीडियाप्लेक्स, एफसी-8, सेक्टर 16-ए, फिल्म सिटी, नोएडा-201301, फोन: 0120-4807100;
- **ग्राहकी चंदा भेजें:** इंडिया टुडे (हिंदी), पो. बॉक्स 114, नई दिल्ली-110001
- **ग्राहक सेवा:** कस्टमर केयर, इंडिया टुडे ग्रुप, सी-9, सेक्टर-10, नोएडा (उत्तर प्रदेश)-201301, टोल फ्री फोन नं. 1800 1800 100 (बीएसएनएल/एमटीएनएल लाइनों से) फोन: दिल्ली, फरीदाबाद से (95120) 2479900; शेष भारत से (0120) 2479900. (सोम से शुक्र-सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक), फैक्स: (0120) 4078080. ई-मेल: wecare@intoday.com
- **सर्कुलेशन कार्यालय:** लिविंग मीडिया इंडिया लिमिटेड, सी-9, सेक्टर-10, नोएडा (उत्तर प्रदेश)-201301
- **इंपैक्ट कार्यालय:** 1201, 12वां तल, टावर 2ए, वन इंडियाबुल्स सेंटर, (जुपिटर मिल्स) एस.बी. मार्ग, लोअर परेल (पश्चिम)-मुंबई-400013. फोन: 022-66063355 फैक्स: 022-66063226
- **क्षेत्रीय विज्ञापन कार्यालय:** ए1-ए2, एनके सेंटर, विनुज्य निकुंज, उद्योग विहार, फेज-5, गुड़गांव, हरियाणा, फोन: 0124-4948400;
- 201-204 रिचमंड टावर्स, द्वितीय मंजिल, 12 रिचमंड रोड, बंगलुरू-560 025 फोन: 2212448, 226233, टेलेक्स: 0845-2217 INTO IN. फैक्स: 080-2218335.
- रजिस्टर्ड कार्यालय: के-9, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली-110001

- लिविंग मीडिया इंडिया लि. विश्व भर में सर्वाधिकार सुरक्षित. किसी भी रूप में सामग्री की नकल प्रतिबंधित. इंडिया टुडे अनिमंत्रित प्रकाशन सामग्री को लौटाने की जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करता.
- सभी विवादों का निबटारा दिल्ली/नई दिल्ली की सीमा में आने वाली सक्षम अदालतों और फोरमों में किया जाएगा.

- **लिविंग मीडिया इंडिया लि. के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक मनोज शर्मा द्वारा के-9, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली-110 001 से प्रकाशित और थॉमसन प्रेस इंडिया लि., 18-35, माइलस्टोन, दिल्ली-मथुरा रोड, फरीदाबाद-121 007 (हरियाणा) में मुद्रित. संपादक: राज चेंगप्पा**

भीतर

सुर्खियां
जम्मू-कश्मीर: वादी में सियासत की वापसी
पेज 6

फुरसत
सवाल+जवाब/चेतन भगत: शब्दों की बुनियाद कत्ल
पेज 50

26 मंदी के गर्त में माली हालत

कोविड संक्रमण के प्रकोप से बुरी तरह पस्त देश की अर्थव्यवस्था मंदी की ओर लुढ़कती जा रही है. आखिर सरकार और उद्योग जगत के पास उसमें फौरन जान फूंकने के क्या हैं उपाय?

फोटो इलस्ट्रेशन: बंदीप सिंह

विशेष बातचीत

16 "मेरा सच मुझे ताकत देता है"

रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत के साथ अपने संबंध, उनके मानसिक संघर्ष और अपने खिलाफ लगे आरोपों पर खुलकर बातचीत की.

नाट्य संस्थान

48 पर हमें खेलना है

ऑनलाइन पढ़ाई कम से कम नाट्य विधा के छात्रों को बिल्कुल रास नहीं आ रही. प्रैक्टिकल कक्षाएं करवाने से कम पर वे राजी नहीं.

उत्तर प्रदेश

44 संकट में ही निकला समाधान

यूपी सरकार ने एमएसएमई पर दिया विशेष ध्यान. नतीजा: महामारी के दौरान कारोबार के साथ ही रोजगार के अवसर भी बढ़े.

आवरण: **नीलांजन दास**

INDIA TODAY GROUP

पाठकों को सलाह दी जाती है कि पत्रिका में प्रकाशित किसी भी वस्तु, सेवा या व्यक्ति के विज्ञापन और प्रचार से संबंधित सामग्री से वचनबद्धता कायम करने, पैसा भेजने या खर्च करने से पहले उचित जांच-पड़ताल कर लें. विज्ञापनदाताओं के किसी भी दावे का उत्तरदायित्व इंडिया टुडे ग्रुप का नहीं है. ऐसे किसी भी तरह के दावों को विज्ञापनदाता अगर नहीं पूरा करता है तो इंडिया टुडे ग्रुप के प्रकाशनों के मुद्रक, प्रकाशक, एडिटर-इन-चीफ और एडिटर इसके लिए जिम्मेदार नहीं होंगे.

BALCO MEDICAL CENTRE

Providing uninteruppted & safe CANCER CARE

- Thermal screening of all visitors
- Usage of more than adequate PPEs
- Enhanced hand hygiene practices
- Social distancing
- Ultra-sanitized facility and ambulance
- Tele & video consultation

WORLD-CLASS CANCER CARE

- Radiation Oncology
- Nuclear Medicine
- Surgical Oncology
- Chemotherapy, Immunotherapy & Targeted Therapy
- Haematology & Blood-related Disorders
- Advanced Laboratory & Diagnostics
- Pain & Palliative Care

Vedanta Medical Research Foundation
BALCO Medical Centre

Sector 36, Atal Nagar,
PO: Upparwara
Raipur-493661 (Chhattisgarh)

+91 8282823333
+91 8282824444

www.balcomedicalcentre.com

FIRST PRIVATE HOSPITAL IN C.G. APPROVED BY NABL FOR COVID TESTING

सुर्खियां: कोविड के दौर में क्रिकेट
पेज 10

स्वच्छता सर्वेक्षण-2020: इंदौर के आगे किसकी बिसात
पेज 12

सुर्खियां

विश्व-भारती हिंसा: फसाद की एक और दीवार
पेज 14

एक मकसद
4 अगस्त 2019 को गुपकर घोषणा के बाद प्रेस से मुखातिब जम्मू-कश्मीर के विभिन्न दलों के नेता

आबिद भट

जम्मू-कश्मीर

वादी में सियासत की वापसी

मोअज्जम मोहम्मद

घाटी ने अपनी खामोशी आखिर तोड़ ही दी. कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने, मुख्यधारा की राजनैतिक पार्टियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई (तीन पूर्व मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी सहित) और सियासी गतिविधियों पर शिकंजा कसने के एक साल बाद 22 अगस्त को इनमें से छह पार्टियों ने एक बार फिर 4 अगस्त 2019 की 'गुपकर घोषणा' के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की तस्दीक की. जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म किए जाने के एक दिन पहले इस घोषणा पर दस्तखत किए गए थे, तब राज्य का राजनैतिक दर्जा घटाए जाने के कयास लगाए जा रहे थे और इन पार्टियों ने साथ आकर इसे रोकने का संकल्प लिया था. दस्तखत करने वाली पार्टियों में नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी), पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी), कांग्रेस, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, सीपीआइ(एम) और अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस शामिल थीं. संयुक्त वक्तव्य में उन्होंने कहा था कि अब से तमाम राजनैतिक गतिविधियां ''जेऐंडके का 4 अगस्त 2019 को मौजूद दर्जा लौटाने के पवित्र लक्ष्य की खातिर और उसकी दिशा में'' होंगी.

पिछले साल 5 अगस्त की घटनाओं से कुछ दिन पहले सैनिकों की जबरदस्त लामबंदी कर दी गई, एक के बाद एक एडवायजरी और फरमान जारी किए गए, सालाना अमरनाथ यात्रा बीच में रद्द कर दी गई और जेऐंडके से सैलानियों को रुखसत कर दिया गया. इससे लोगों में फिक्र का माहौल तारी हो गया और जबरदस्त अफवाहें फैलने लगी थीं. इसने 4 अगस्त को सियासी पार्टियों को आनन-फानन इकट्ठा होने के लिए मजबूर कर दिया. बैठक गुपकर रोड के भारी सुरक्षा से घिरे इलाके में (जहां दो और पूर्व मुख्यमंत्रियों उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती के घर

साकार होगा अपने घर का सपना

सिर पर एक छत हमेशा मायने रखती है. अपना घर, लोगों का हमेशा से ही एक सपना रहा है. घर की चार दीवारें किसी इंसान के लिए हमेशा से सबसे सुरक्षित जगह मानी जाती रही हैं. दुनियाभर की सरकारों ने भी इस बात को स्वीकारा जब उन्होंने अपने नागरिकों से कहा कि वे घर के भीतर ही सबसे सुरक्षित रहेंगे और केवल आवश्यक चीजों के लिए ही घर से बाहर कदम रखें. कोविड-19 के दौर ने हमें घर की अहमियत को बेहतर समझने का मौका दिया है.

महामारी ने सिर्फ एक घर के महत्व को साबित करने से कहीं अधिक किया है. इसने घरों को सिर्फ घर नहीं रहने दिया, खासकर शहरी इलाकों में. घर केवल वह जगह नहीं रह गया हैं जहां पूरा परिवार दिनभर के काम की थकान उतारने के लिए आराम करता था, यह एक लीविंग प्लेस बन गया है. अब इसके एक–एक वर्ग फुट जगह की अलग उपयोगिता और हर कोने का बेहतर इस्तेमाल हो रहा है. निजता, आराम और निजी स्थान के महत्व को पुनः स्वीकारा और समझा जा रहा है. पूरे दिन परिवार के साथ बिताए गए अच्छे समय ने लोगों को हर सदस्य के लिए स्पेस की जरूरत को समझने और उसका सम्मान करने में सक्षम बनाया है. घर में जगह की जरूरत को पुर्नपरिभाषित करने और उसके लिए फिर से तैयारी करने को लेकर लोग अब गंभीरता से सोचने लगे हैं. रियल एस्टेट बाजार बुरी स्थिति में है. निर्माणाधीन प्रोजेक्टस के साथ–साथ बहुत से 'रेडी टू मूव' इन्वेंट्री की भरमार हैं. घर की कीमते भी आकर्षक हो गई हैं. यह महामारी आपके लिए एक ऐसे घर की पहचान करने और उसमें शिफ्ट करने का एक बड़ा अवसर हो सकता है जो आपके लिए उपयुक्त है. घर खरीदने के लिए पैसा भी आसानी से उपलब्ध है. ब्याज दर ऐतिहासिक निम्नस्तर पर हैं और डिजिटल तकनीक में उन्नति आपको अपने वर्तमान घर के सुरक्षित दायरे से, ऑनलाइन ऋण के लिए आवेदन करने की अनुमति देती है.

चुनने के लिए बहुत सारे विकल्प मौजूद हैं, रेडी टू मूव प्रॉपर्टी उपलब्ध है, बिल्डरों से भारी छूट मिल रही है और ब्याज की दरें भी बहुत आकर्षक हैं. घर खरीदने का सपना पूरा करने के लिए इससे आदर्श स्थितियां दूसरी क्या होगीं. कोई ऐसा मौका हाथ से कैसे जाने दे सकता है भला!

कोविड–19 के इस फेज मे भी कुछ सकारात्मक बातें नजर आती हैं. त्यौहार के मौसम के लिए एक नया घर लेने और उसमें शिफ्ट करने का यह एक अच्छा अवसर लेकर भी तो आया है.

भी हैं) एनसी अध्यक्ष और श्रीनगर के सांसद फारूक अब्दुल्ला के घर पर हुई. इससे जो संकल्प निकलकर आया, उसे 'गुपकर घोषणा' कहा गया. अब 22 अगस्त के संकल्प ने उस प्रतिबद्धता की तस्दीक की और कहा ''कि हम गुपकर घोषणा की बातों से बंधे हैं... और अनुच्छेद 370 और 35ए, जेऐंडके के संविधान और राज्य की बहाली की खातिर पुरजोर संघर्ष करने के लिए प्रतिबद्ध हैं... कोई भी विभाजन हमें नामंजूर है''.

इस संकल्प ने सरकार के साथ कई बाहर के लोगों को भी हैरत में डाल दिया. इसे जारी करने से एक दिन पहले फारूक ने, जो अब 82 वर्ष के हैं, रिहा होने के बाद अपने पहले टीवी इंटरव्यू (*इंडिया टुडे* सहित) दिए. वे बेहद सख्त जन सुरक्षा कानून के तहत नजरबंदी से मार्च में रिहा हुए थे. मगर अब भी किसी को भनक तक नहीं थी कि क्या होने वाला है. पर्दे के पीछे एनसी के नेता और अनंतनाग से सांसद न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) हसनैन मसूदी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के मुखिया सज्जाद लोन संकल्प का मसौदा तैयार करने के जुटे थे. दोनों श्रीनगर के एक ही इलाके में रहते हैं और उनकी बैठकों पर शायद किसी का ध्यान नहीं गया. पूरी कवायद को बेहद गोपनीय रखा गया और केवल पार्टियों के शीर्ष नेताओं को इसकी जानकारी थी. इनमें पीडीपी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती भी थीं, जो अब भी नजरबंद हैं.

जेऐंडके हाइकोर्ट के पूर्व जज मसूदी कहते हैं कि घोषणा पर दस्तखत करने वाली सभी शुरुआती पार्टियां फिर प्रतिबद्धता जाहिर करने के लिए एकदम तैयार थीं. वे कहते हैं, ''हमारी उर्दू जबान, हमारा संविधान और झंडा सब चले गए. हम चाहते हैं कि भारत सरकार ने 5 अगस्त को जो किया, उसे पलटे. अगर किसी मामले में बदलाव की जरूरत है तो हम हमेशा उस पर बात कर सकते हैं. मगर एकतरफा ढंग से हमें बांट देना और म्यूनिसिपैलिटी में बदल देना हमें नामंजूर है.''

अलबत्ता कुछ लोग मानते हैं कि जन दबाव और नई दिल्ली के कठोर रवैए का मुकाबला करने के लिए संयुक्त रणनीति में नए सिरे से जान फूंकी गई है. वहीं, कम से कम कुछ नेता हैं जो अपनी हाल की नजरबंदी या कैद के बाद केंद्र के मंसूबों के मुताबिक चलने को तैयार हैं. बताया जाता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में उमर अब्दुल्ला के नजदीकी कुछ नेता अपने भविष्य को लेकर कम उत्साहित रह गए हैं. पीडीपी में भी यही हालत है. 2018 में भाजपा के साथ अपना गठबंधन खत्म करने के बाद वह पहले ही दोफाड़ हो चुकी है. केंद्र ने एक के बाद एक जो ध्रुवीकरण करने वाले फैसले लिए, उन्होंने ''सुलह और मेलमिलाप'' को रोक रखा था. इन फैसलों में डोमिसाइल या अधिवास कानून, परिसीमन की कवायद और सशस्त्र बलों के इस्तेमाल के लिए ''सामरिक क्षेत्रों'' की अधिसूचना शामिल थे. इस ''हमले'' को मुस्लिम-बहुसंख्यक इलाकों की जनसांख्यिकी बदलने के कदम के तौर पर देखा गया.

एनसी और पीडीपी सरीखी मुख्यधारा की पार्टियों ने अपनी राजनीति स्वायत्तता के इर्द-गिर्द बुनी है और इससे दूर हटने पर कश्मीर की सियासत में उनकी प्रासंगिकता को लेकर सवाल खड़े हो जाएंगे. *व्हाट हैपंड टू गवर्नेंस इन कश्मीर?* के लेखक प्रो. एजाज अशरफ वानी कहते हैं, ''यह सामूहिक कदम उनके भविष्य और वजूद की खातिर है. उस फैसले ने राज्य का दर्जा ही नहीं बदला बल्कि मुख्यधारा की राजनीति का परिदृश्य भी बदल दिया. सवाल यह है: वे जो चाहते हैं उसे हासिल करने के लिए क्या एकजुट लड़ाई को कायम रख सकते हैं?'' यही नहीं, क्या वे सत्ता से बाहर रहकर ऐसा करना गवारा कर सकते हैं?

तो राजनैतिक प्रतिरोध का रोडमैप क्या है? फिलहाल पार्टियां एकराय हैं कि जेऐंडके पुनर्गठन कानून के जरिए किया गया कोई भी बदलाव उन्हें मंजूर नहीं है. परिसीमन आयोग को ठुकराना इसी का हिस्सा था. मई में तीन सांसदों, बड़े अब्दुल्ला, मसूदी और अकबर लोन (सभी एनसी) को मई में परिसीमन आयोग में नामजद किया गया था, मगर उन्होंने इसका हिस्सा बनने से इनकार कर दिया. जेऐंडके अधिवास कानून सुलह की राह का एक और रोड़ा है. पार्टियां पहले ही इस पर अपनी असहमति दर्ज कर चुकी हैं. भीतरी तौर पर उनका कहना है कि वे नागरिकता अधिकारों पर नई दिल्ली के साथ बातचीत करने को तैयार हैं. मगर ऐसा तभी हो सकता है जब संवैधानिक बदलावों को पलटा जाए और राज्य विधानसभा को लोगों की नुमाइंदगी की उसकी वाजिब भूमिका निभाने दी जाए. गुमनाम रहने के आग्रह के साथ एक शीर्ष राजनैतिक नेता कहते हैं, ''पिछले साल के फैसले को चुनौती देने के लिए हम अपने तरकश में मौजूद हर सियासी हथियार के साथ आगे बढ़ेंगे. इस वक्त तो जेल भी एक सियासी हथियार है.''

आने वाले हफ्तों में कुछ और राजनैतिक तथा गैर-राजनैतिक धड़े गुपकर समूह के साथ एकजुटता जाहिर कर सकते हैं. इसके लिए, सितंबर के दूसरे हफ्ते में शुरू होने वाले संसद के मॉनसून सत्र से पहले एक बैठक होने की संभावना है, बशर्ते सरकार होने दे. घोषणा की पहले से जानकारी रखने वाले एक नेता कहते हैं, ''सभाओं पर पाबंदी हटा लिए जाने के बाद हम रणनीति बनाएंगे. फिलहाल हम लोगों से कहना चाहते हैं कि हम अपनी संवैधानिक गारंटियां, अपनी जमीन और नौकरी के अधिकार बहाल करवाने के लिए प्रतिबद्ध हैं.''

नए सर्वसम्मत धड़े की वजह से जेऐंडके पार्टी सरीखे नवजात राजनैतिक दलों की सियासी जगह सिकुड़ जाएगी. अफवाहें हैं कि अपनी पार्टी को केंद्र की भाजपा का समर्थन हासिल है. भाजपा के अलावा यह अकेली सियासी पार्टी है जिसने गुपकर घोषणा का समर्थन नहीं किया है. पूर्व अफसरशाह शाह फैसल की बनाई राजनैतिक पार्टी जेऐंडके पीपल्स मूवमेंट ने पिछले साल गुपकर घोषणा पर दस्तखत किए थे और उसका कहना है कि वह घोषणा का समर्थन करती है. (फैसल ने इसी महीने राजनीति छोड़ दी.)

इस बीच, भाजपा जेऐंडके में अपनी पटकथा के मुताबिक चलने पर अडिग दिखती है. पार्टी उपाध्यक्ष और राज्य प्रभारी अविनाश राय खन्ना कहते हैं कि अनुच्छेद 370 बहाल करने का सवाल ही नहीं उठता. वे कहते हैं, ''केवल राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा. इस संकल्प का कोई असर नहीं होगा क्योंकि लोग उन्हें सुन ही नहीं रहे हैं. उन्होंने 370 हटाए जाने के पहले भी धमकियां दी थीं... ये (परिवार संचालित) पार्टियां केवल अपने हितों को लेकर चिंतित हैं.'' वे कहते हैं कि केंद्र ने विकास के एजेंडे से लोगों का भरोसा जीता है और यह इन पार्टियों के लिए अच्छा शकुन नहीं है. वे 'गांव की तरफ वापसी' सरीखे केंद्रीय कार्यक्रमों, केंद्रीय मंत्रियों के दौरों और नए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की लोगों के साथ बैठकों का जिक्र करते हैं और इन्हें घाटी में अमन-चैन की वापसी का सबूत बताते हैं.■

संयुक्त घोषणा में सभी दलों ने अनुच्छेद 370 और 35ए की बहाली की प्रतिबद्धता दोहराई पर इसे उनके प्रासंगिक रहने के प्रयास के तौर पर भी देखा जा रहा है

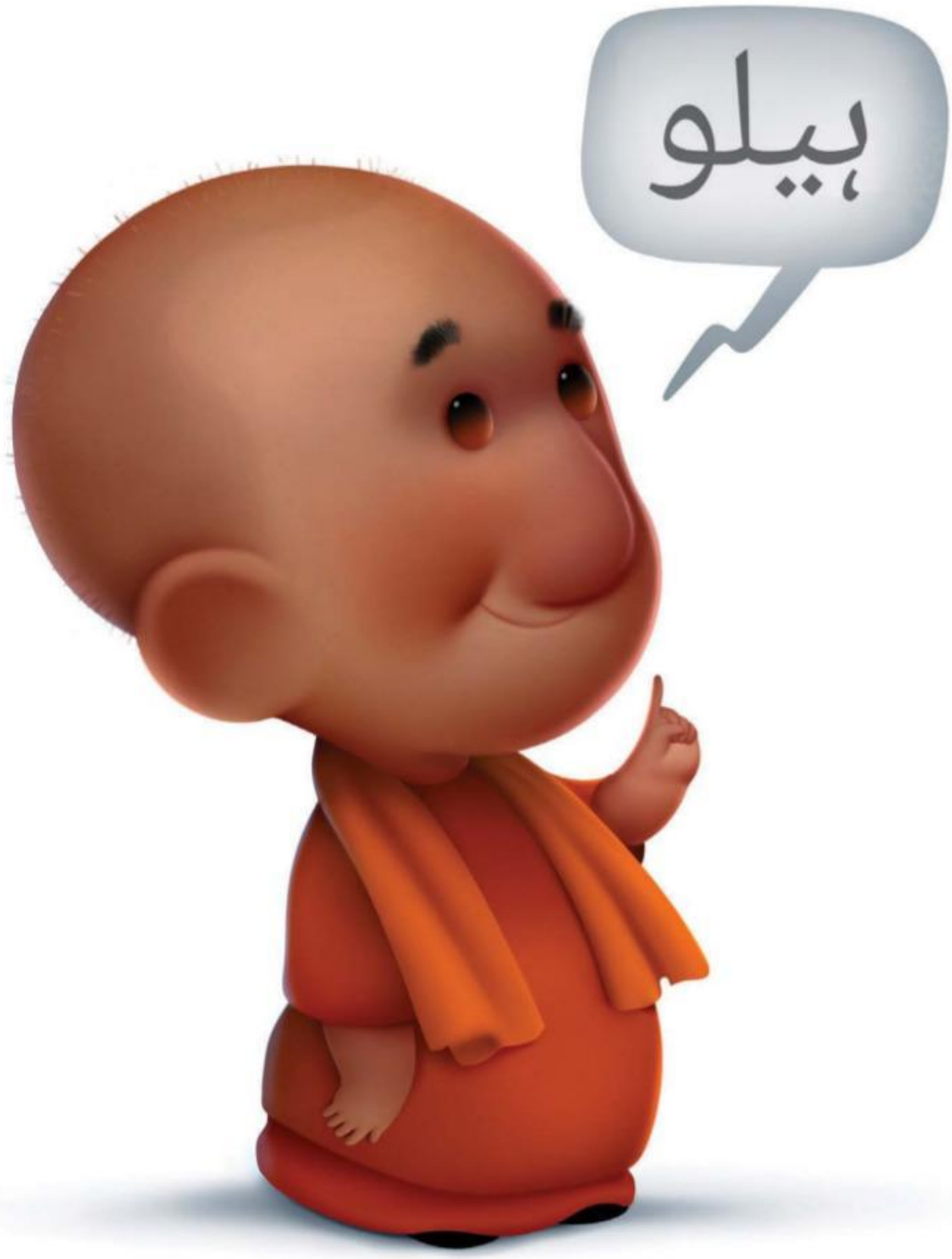

इलस्ट्रेशन: सिद्धांत जुमडे

समाचार सार

योगी का 'शेर'

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने भाषणों में धाराप्रवाह संस्कृत श्लोक और चौपाइयों के इस्तेमाल के लिए जाने जाते हैं. शायद इसी वजह से 22 अगस्त को विधानसभा में उनके भाषण पर कइयों की भौंहे उठ गईं. यह बताते हुए कि उनके कार्यकाल में अपराध की दर कम हो गई है, उन्होंने मंसूर उस्मानी के एक शेर के जरिए सपा और बसपा के विरोध पर तंज कसा. शेर था: *चमन को सींचने में पत्तियां कुछ झड़ गई होंगी/ यही इल्जाम है हम पर चमन से बेवफाई का/ मसल डाला जिन्होंने कलियों को खुद अपने हाथों से/ वे दावा कर रहे हैं अब चमन की रहनुमाई का.* भई वल्लाह!

वेलडन अब्बा

एएनआइ

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री **वाइ.एस. जगनमोहन रेड्डी** अपने इतवारों को बहुत संजीदगी से लेते हैं. एक धर्मपरायण ईसाई की तरह वे अपना वक्त परिवार के साथ प्रार्थना में बिताते हैं. लेकिन जब से पिछले साल 30 मई को उन्होंने कुर्सी संभाली है, राजकाज ने उनका टाइम टेबल बिगाड़ दिया है. पर रास्ते खोज लेने को हमेशा तत्पर मुख्यमंत्री को 25 अगस्त को बड़ी बेटी हर्षा के साथ बेंगलूरू में वक्त मिल ही गया जब लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से स्नातक बिटिया पेरिस में इनसीड के एग्जीक्यूटिव एमबीए में दाखिले के लिए जा रही थी. गौरतलब है कि छोटी बेटी वर्षा ने पिछले साल अमेरिका में इंडियाना स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ नोत्रे दाम में स्नातक में दाखिला लिया है.

यह बेटे का बदला तो न था?

महाराष्ट्र के उप-मुख्यमंत्री **अजित पवार** कोविड-19 प्रोटोकॉल के मामले में जरा भी ढील नहीं बरतते. मंत्रालय में उनके दफ्तर में आगंतुकों को जरूरी छह फुट की दूरी पर रखा जाता है. मिलने आई चचेरी बहन सुप्रिया सुले को भी इससे छूट नहीं मिली. यह कहीं बेटे पार्थ को सुले के पिता और कुलपुरुष शरद पवार के सरेआम फटकारने का बदला तो नहीं था? नहीं. अजित वाकई एहतियात बरत रहे हैं. पुणे के एक कार्यक्रम में साउंड बाइट देने से पहले उन्होंने टीवी कैमरों के माइक्रोफोन पर सैनिटाइजर छिड़का था.

एएनआइ

आ गया 'मॉनसून'

चुनाव की आहट के साथ ही बिहार में आया राम गया राम का मौसम शुरू हो गया है. पिछले हफ्ते लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेजप्रताप के रंजिशजदा ससुर **चंद्रिका राय** (तस्वीर में दाएं) समेत राजद के तीन विधायक जद (यू) में शामिल हो गए. सत्ता पक्ष में जा खड़े होने वाले वे 11वें शख्स हैं. पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी भी राजद-नीत महागठबंधन से छिटक गए हैं. राजद के पाले में अब तक सिर्फ जद (यू) के विधायक श्याम रजक ही आए हैं. लेकिन पटना के सियासी गलियारों में दिल की आवाज सुनने वाले बहुत-से नेताओं के बारे में कानाफूसियां चल रही हैं.

—**संदीप उन्नीथन**, साथ में **आशीष मिश्र, अमरनाथ के. मेनन, किरण डी. तारे** और **अमिताभ श्रीवास्तव**

कोविड के दौर में क्रिकेट

इंडियन प्रीमियर लीग (आइपीएल) का 13वां संस्करण 19 सितंबर से यूएई में शुरू होने वाला है. खबर लिखे जाने तक टूर्नामेंट का आधिकारिक कार्यक्रम जारी नहीं किया गया है लेकिन कयास हैं कि पहला मैच चार बार के चैंपियन मुंबई इंडियंस और तीन बार के खिताब विजेता चेन्नै सुपरकिंग्स के बीच होगा. 53 दिनों के इस टूर्नामेंट में दुबई, शारजाह अबू धाबी में मैच होंगे, और इसका फाइनल 10 नवंबर को होगा. इस पैमाने के खेल आयोजन के लिए लॉजिस्टिक्स का प्रबंध करना मुश्किल काम है और खासकर विदेशों में आयोजन ने इस महामारी के दौर में चुनौती को कई गुना बढ़ा दिया है. हैरत नहीं कि सारा ध्यान उस कथित जैव-सुरक्षित बुलबुले पर है जो कोविड के जोखिम को कम करने के लिए बनाया जा रहा है. 'बुलबुले' से मतलब इन तीनों शहरों के तीन मैच स्थलों और दो ट्रेनिंग स्थलों में बनाए जा रहे उस कड़े कंटेनमेंट जोन से है जो होटलों, स्टेडियम और खिलाड़ियों, कर्मचारियों और आयोजकों को ढोने वाले परिवहन के साधनों के चारों ओर बनाया जाएगा. तमाम किस्म के प्रतिबंधों के बावजूद सैकड़ों खिलाड़ी, कोच, सपोर्ट स्टाफ, अंपायर, ग्राउंड स्टाफ और सुरक्षाकर्मी और मीडियाकर्मी होंगे जिन्हें कंटेनमेंट जोन में जाने देने से पहले क्वारंटीन करना होगा और उनकी कोविड जांच करनी होगी, जहां उन्हें पूरे आइपीएल के आयोजन के दौरान रहना होगा.

बुलबुले बनाने वाले

यूके की सुरक्षा कंपनी रेस्ट्रेटा आइपीएल के लिए जैव-सुरक्षित बुलबुला बनाने और उसके प्रबंधन का काम देखेगी. इस कंपनी ने इससे पहले 2012 के लंदन ओलंपिक के समय सुरक्षा सेवाएं प्रदान की थीं और हाल में इसने इंग्लैंड में वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान के खिलाफ खेली गई टेस्ट सीरीज में भी जैव-सुरक्षा की व्यवस्था का इंतजाम किया था. यह निविदा हासिल करने में रेस्ट्रेटा ने कथित रूप से टाटा मेडिकल ऐंड डायगनोस्टिक्स को पीछे छोड़ा क्योंकि उसके पास अनुभव अधिक था और बोली की कीमत कम.

मैदान पर उतरे खिलाड़ी

23 अगस्त को सभी आठ आइपीएल टीमें दुबई पहुंच चुकी हैं. खिलाड़ियों और उनके सपोर्ट स्टाफ को उस 'बुलबुले' में तभी जाने दिया जाएगा जब वे हफ्ते भर का क्वारंटीन पूरा कर लेंगे. इस दौरान पहले, तीसरे और छठे दिन उनकी कोविड जांच होगी. एक बार अंदर आने के बाद, उन्हें इस बुलबुले—जिसमें उनका होटल, परिवहन सुविधाएं और स्टेडियमों के कुछ हिस्से शामिल होंगे—से 80 से अधिक दिन तक यानी आइपीएल पूरा होने तक बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी.

53 दिन
तक तो सिर्फ टूर्नामेंट होने का ही अनुमान है, खिलाड़ियों और स्टाफ को इससे ज्यादा समय तक क्वारंटीन रहना होगा

3 शहर
टूर्नामेंट दुबई, आबू धाबी और शारजाह में खेला जाएगा जिससे चुनौतियां और गहरी हो जाएंगी

ग्राफिक्स- तन्मय चक्रबर्ती

सभी फोटोः एएनआइ

बिना महामारी के भी आइपीएल का आयोजन विदेशी धरती पर करना लॉजिस्टिक के लिहाज से बड़ी चुनौती होती है. यहां चेन्नै सुपरकिंग्स (बाएं) और डेल्ही कैपिटल्स के खिलाड़ी यूएई रवाना होते हुए तथा एक आइपीएल प्रतिभागी मुंबई से फुल पीपीई सूट में जाता हुआ

189 खिलाड़ी

आठ टीमों में से प्रत्येक में 21 से 25 खिलाड़ी हैं. अब इसमें सपोर्ट स्टाफ, ग्राउंड्सपर्सन, मीडियाकर्मी और अन्य लोगों को मिला लिया जाए तो लॉकडाउन में रहने वालों की संख्या बहुत ज्यादा होगी

खोज और पता

इस जैव-बुलबुले की मुख्य विशेषता यह तय करना होगा कि प्रतिभागी-खिलाड़ी, कोच, ग्राउंड स्टाफ, अंपायर, मीडियाकर्मी और अन्य कंटेनमेंट जोन न तोड़ें. अंदाजा लगाया जा रहा है कि सभी प्रतिभागियों के जीपीएस वाले पहचान-पत्र/ ब्रेसलेट दिए जाएंगे और उनकी गतिविधियों की चौबीसों घंटे निगरानी की जाएगी. इस व्यवस्था की अहमियत के बारे में बताते हुए रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के कप्तान विराट कोहली ने टीम मीटिंग में बताया कि अगर एक भी खिलाड़ी ने सुरक्षा घेरे को तोड़ा तो इससे न हर किसी की सुरक्षा पर खतरा होगा बल्कि इससे उस टीम के साथियों को नीचा भी देखना पड़ेगा.

सटोरियों की सांसत

इस जैव-बुलबुले का एक अच्छा असर यह भी होगा कि इससे सटोरियों और दलालों के लिए अपनी चालें चलने के मौके सीमित हो जाएंगे. टीम के होटल आम लोगों के लिए सील रहेंगे, ऐसे में सटोरियों को कम से कम आमने-सामने खिलाड़ियों से साठगांठ का मौका नहीं मिल पाएगा. हालांकि, खिलाड़ियों के सोशल मीडिया अकांउट्स पर निगाह रखना और उनकी सुरक्षा एक अलग ही चुनौती होगी ताकि उन्हें कोई ललचाता हुआ प्रस्ताव ऑनलाइन न भेजा जा सके.

स्वच्छता सर्वेक्षण-2020

इंदौर के आगे किसकी बिसात

राहुल नरोन्हा

भारत के सबसे साफ शहर के रूप में इंदौर की पहचान पर अब किसी बहस की गुंजाइश नहीं है. बीते 20 अगस्त को मध्य प्रदेश की यह व्यावसायिक राजधानी 10 लाख से ऊपर की आबादी वाले शहरों के बीच आयोजित होने वाले केंद्र सरकार के वार्षिक स्वच्छ सर्वेक्षण में लगातार चौथी बार पहले स्थान पर रहा. इस उपलब्धि से इस वार्षिक सर्वेक्षण की क्रियाविधि के बारे में लोगों की अंट-शंट धारणाओं को भी विराम मिल गया है और कट्टर शंकालुओं को भी मानना पड़ेगा कि यह सम्मान पाने के लिए इंदौर ने कुछ तो ठीक काम किया होगा.

चिरपरिचित धूल, गंदगी, अराजकता और आवारा जानवरों से भरे मध्य भारत के किसी भी सामान्य शहर से साफ सुथरी सड़कों, बढ़िया अपशिष्ट संग्रहण और प्रबंधन योजना वाले मौजूदा इंदौर में कायांतरण के पीछे कई कारकों का मिलाजुला प्रभाव रहा है, जिसे यहां के उत्साही नगर निगम कार्मिकों और जागरूक नागरिकों ने मिलकर संभव बनाया.

इंदौर की सफलता की इस रणनीति को समझने के लिए पांच साल पीछे जाना होगा. 2016 में जब पहले स्वच्छ सर्वेक्षण के बाद शहरों की रैंकिंग घोषित हुई थी, तो इंदौर देश में 25वें स्थान पर था. शीर्ष सम्मान मैसूरू को मिला था. लेकिन उसी वर्ष इंदौर भारत का दूसरा ऐसा जिला बन गया, जिसे खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया था. इस उपलब्धि ने तत्कालीन नगर निगम आयुक्त मनीष सिंह और महापौर मालिनी गौड़ को प्रेरित किया कि वे शहर को बेहतर बनाने का बीड़ा उठाएं.

मनीष सिंह ने स्वच्छता के लिए जिम्मेदार संस्था इंदौर नगर निगम में पुरस्कार और दंड नीति लागू की. उन्होंने उस समय के 3,500 स्वच्छता कर्मचारियों में लगभग 2,000 कार्मिक और भर्ती किए जबकि कामचोरों की सेवाएं समाप्त कर दीं. अब इंदौर के कलेक्टर की कुर्सी पर विराजित मनीष सिंह कहते हैं, ''मैंने सड़कों पर स्वच्छता सुनिश्चित करने की दिशा में घर-घर से कचरे के संग्रह की पहचान सबसे महत्वपूर्ण कदम के रूप में की, क्योंकि अगर नागरिक निर्धारित स्थानों पर कचरा फेंकें तो भी समय पर उठान न होने पर वहां कचरे का ढेर हो जाता है.'' उनके कार्यकाल में ही इंदौर नगर निगम ने उद्गम पर ही अपशिष्ट का अलगाव भी शुरू किया, जिसे थोड़े आरंभिक प्रतिरोध के बाद जनता ने भी अपना लिया.

जैसे ही नगर निगम के प्रयासों के परिणाम दिखाई देने लगे, इंदौर का उत्साही नागरिक समाज इसके समर्थन में आ गया और सामाजिक समूहों ने स्वच्छता पहल में नगर निगम की सहायता करनी शुरू कर दी. नगर निगम ने घर-घर से कचरा संग्रहण की निगरानी के लिए गैर-सरकारी संगठनों को जोड़ा. गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने न केवल यह सुनिश्चित किया कि कचरा नगर निगम के ट्रकों से बाहर न गिरे, बल्कि उन्होंने शहर में कहीं भी दिख रहे कचरे के ढेरों के बारे में भी बताना शुरू किया. इन संगठनों ने इंदौर नगर निगम को उसकी तीन 'आर' रणनीति—रिड्यूस, रियूज, रिसाइकल (कमी, पुनर्प्रयोग और पुनर्चक्रण)' को लागू करने में भी मदद की.

अब तो मध्य प्रदेश सरकार अपने यहां निवेशकों को आकर्षित करने के लिए इंदौर के स्वच्छता के इस दर्जे को एक खासियत के रूप में प्रचारित करती है.

घर-घर से कचरे के संग्रहण को सफल बनाने के लिए 180 करोड़ रु. का पूंजीगत व्यय किया गया. दो वर्षों में ही इंदौर नगर निगम के सफाई और कचरा संग्रह वाहनों का बेड़ा 100 से 600 का हो गया. इंदौर नगर निगम के अनुसार, हर दिन 1,115 मीट्रिक टन कचरा उत्पन्न करने वाले इंदौर के सभी 85 वार्डों में आवासीय और वाणिज्यिक स्थानों समेत सभी जगह घर-घर से कचरा संग्रहण होता है.

2017 में इंदौर स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंच गया. उसके बाद से भारत के सबसे स्वच्छ शहर को अपने इस बेशकीमती टैग पर पकड़ बनाए रखने की चुनौती थी. 2018 की शुरुआत में इंदौर नगर निगम के आयुक्त के रूप में मनीष सिंह की जगह आशीष सिंह आए. उन्होंने अपने पूर्ववर्ती की शुरू की गई सफल रणनीतियों को जारी रखा, जिससे इंदौर के परिणाम लगातार बेहतर बने रहे. उन्होंने न केवल 2,500 स्वच्छता कर्मचारियों की और भर्ती करके इंदौर को साफ रखने वाले स्वच्छता कार्यबल को 8,000 तक पहुंचाया, बल्कि अपने लिए भी एक लक्ष्य निर्धारित किया—इंदौर की आंखों में सबसे ज्यादा चुभने वाली जगह, देवगुराड़िया लैंडफिल साइट,

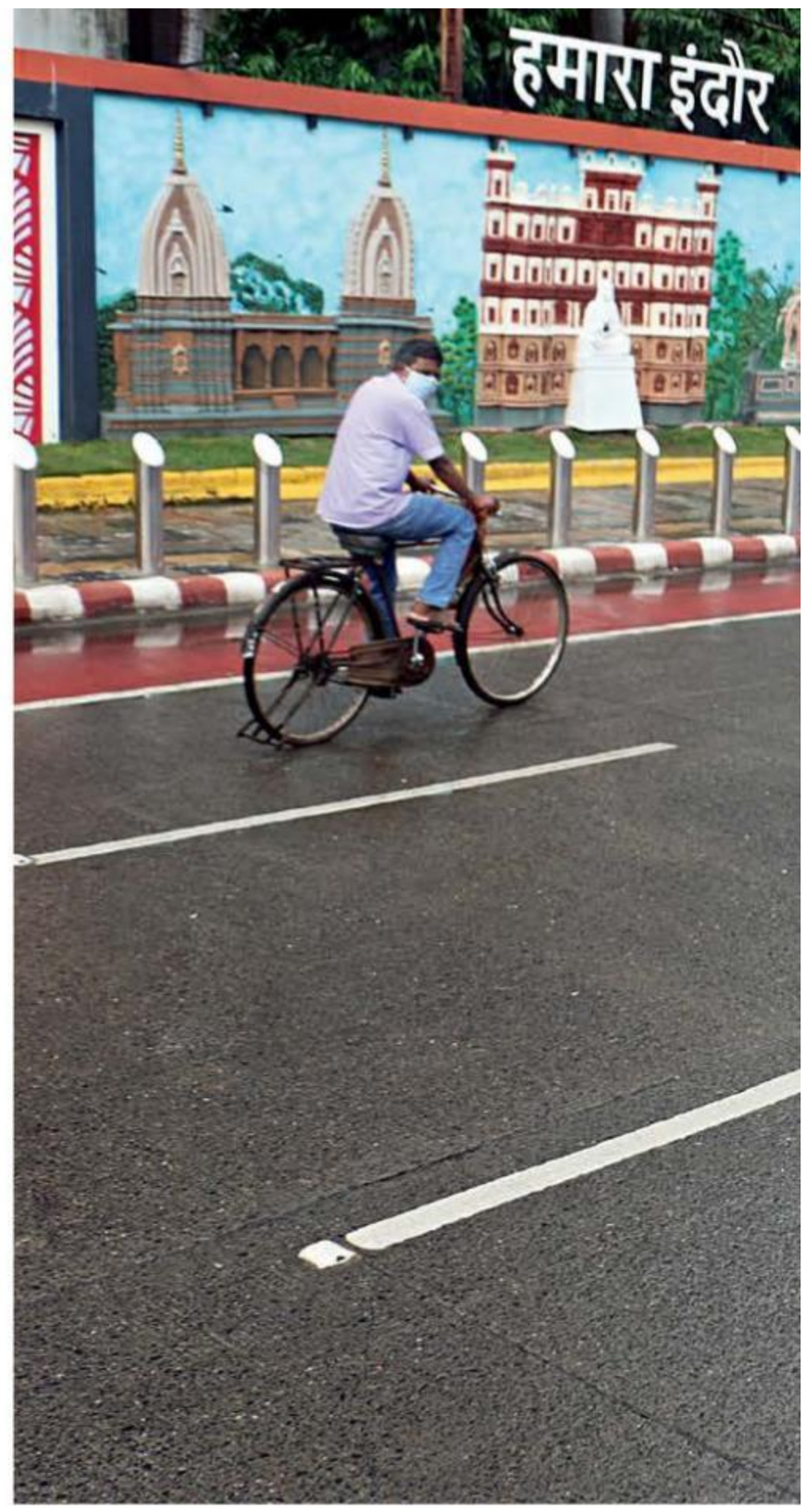

आइना सड़कें
इंदौर में पलासिया के आदर्श रोड इलाके में स्वच्छता अभियान में जुटीं सफाईकर्मी

से मुक्ति दिलाने का. देवगुराड़िया में चार दशकों से भी अधिक समय से कूड़ा डाला जा रहा था. फिलहाल पड़ोसी जिले उज्जैन के जिलाधिकारी आशीष सिंह कहते हैं कि ''कचरे का एक ढेर लोगों को प्रोत्साहित करता है कि वे भी वहीं कचरा डालें जिससे वह बड़ा और अप्रबंधनीय होता जाता है.''

देवगुराड़िया में व्यापक बायोरीमीडिएशन प्रक्रिया के माध्यम से लगभग 2,00,000 मीट्रिक टन कचरे को खत्म किया गया. इस कूड़ा पटान की चारदीवारी बनाकर 60,000 पौधे लगाकर वहां अब एक हरित पट्टी विकसित की गई है. इंदौर में पैदा होने वाले पूरे कचरे को अब संसाधित किया जाता है और देवगुराड़िया के आसपास से बदबू का नामोनिशान इस तरह से खत्म हो गया है कि अब इस कूड़ा पटान को गोल्फ कोर्स में बदलने का प्रस्ताव है.

इंदौर की सफलता की कहानी की गवाही रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने अपनी पुस्तक *द थर्ड पिलर* में दी है. परिवर्तन पर विस्तार से बात करने के पहले पुराने दौर के इंदौर के बारे में राजन ने लिखा, ''सर्राफा बाजार स्थित खाने-पीने के सामान के मशहूर बाजार में स्टॉलों से खरीदा हुआ खाना कागज के प्लेटों पर खाने के बाद, ग्राहक अपनी प्लेटें और बची-खुची खाद्य सामग्री वहीं जमीन पर फेंक दिया करते थे. लोग अपने घरेलू कचरे के प्रति भी अधिक सावधान नहीं थे और उसे आसपास कहीं भी फेंक देते थे जिसे शायद ही कभी उठाया जाता था.'' आज, या यूं कहें कि कोविड के दौरान जीवन का ढर्रा बदल जाने से ठीक पहले, सफाईकर्मियों के दल हर सुबह चार बजे सर्राफा बाजार में पहुंचते हैं और सूर्योदय होने तक सर्राफा बाजार में छटांक भर भी गंदगी नहीं बचती.

इंदौर के लोग अब अपने शहर के अर्जित किए गए स्वच्छता सम्मान पर गर्व करते हैं. यह भाव अब इस हद तक है कि सड़कों पर अनजाने में कोई गंदगी फैलाने वालों को आवाज देकर बुलाना यहां कोई असामान्य बात नहीं है. राज्य सरकार भी इंदौर की इस स्थिति को भुनाने के लिए और अपनी सभी प्रचार गतिविधियों में इसका उल्लेख कर रही है, खासकर निवेश को आकर्षित करते हुए.

उल्लेखनीय है कि इंदौर में चले जागरूकता अभियानों में क्रिकेट शब्दावली का खूब प्रयोग हुआ है. 2019 में, गायक शान ने एक जिंगल 'हैट-ट्रिक लगाएंगे' गाया था, जबकि अगले साल का नारा था 'चौका लगाएंगे'. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जोर देकर कहते हैं कि अगले दो साल में इंदौर अब छक्का लगाएगा. वह गलत नहीं कहते कि ''स्वच्छता अब इंदौर की संस्कृति का हिस्सा है.''■

स्वच्छ शहर

स्वच्छता सर्वेक्षण की रैंकिंग में बाकी कई शहर ऊपर-नीचे होते रहे लेकिन इंदौर को शीर्ष से अभी तक कोई हिला नहीं पाया है

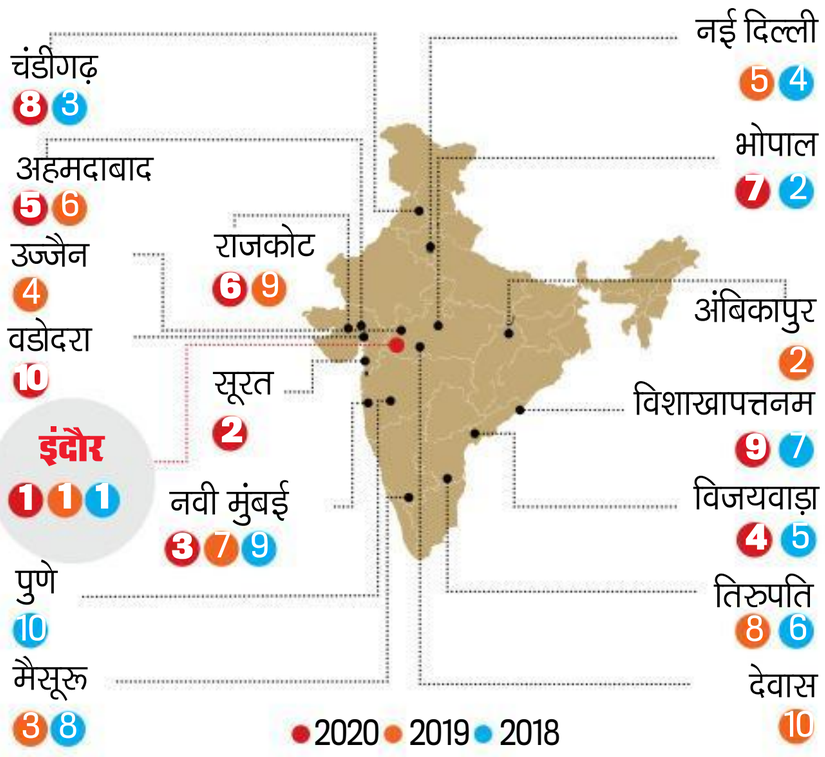

नवी मुंबई दूसरा अकेला ऐसा शहर है जो 2018 से अब तक टॉप 10 की सूची में बना रहा है. राष्ट्रीय राजधानी 2020 में सूची से बाहर हो गई

2020 में टॉप 3
(अधिकतम अंक 6,000)

5647.6
इंदौर

5519.6
सूरत

5467.9
नवी मुंबई

इंदौर का बेदाग रिकॉर्ड

2020	2019	2018
1. इंदौर	इंदौर	इंदौर
2. सूरत	अंबिकापुर	भोपाल
3. नवी मुंबई	मैसूरू	चंडीगढ़
4. विजयवाड़ा	उज्जैन	नई दिल्ली
5. अहमदाबाद	नई दिल्ली	विजयवाड़ा
6. राजकोट	अहमदाबाद	तिरुपति
7. भोपाल	नवी मुंबई	विशाखापत्तनम
8. चंडीगढ़	तिरुपति	मैसूरू
9. विशाखापत्तनम	राजकोट	नवी मुंबई
10. वडोदरा	देवास	पुणे

ग्राफिकः असित रॉय

सुभाशीष बसु

कैंपस की जंग
पौष मेले के मैदान के पास दीवार खड़ी करने के विरोध में विश्व-भारती के पूर्व कर्मचारी और छात्र; 17 अगस्त को भीड़ की तोड़फोड़ के बाद का नजारा (इनसेट)

सुबीर हलदर

विश्व-भारती हिंसा

फसाद की एक और दीवार

रोमिता दत्ता

विश्व-भारती बंगाल का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय है जिसके कुलाधिपति (चांसलर) प्रधानमंत्री हैं. विश्व-भारती इन दिनों सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) और बंगाल की सत्ता पर नजर गड़ाए बैठी भाजपा के बीच जंग का मैदान बन गया है. कवि, शिक्षाविद और नोबेल पुरस्कार विजेता रवींद्रनाथ टैगोर की ओर से 1921 में स्थापित इस विश्वविद्यालय की विरासत आज खतरे में है.

नवंबर, 2018 में कुलपति विद्युत चक्रवर्ती की नियुक्ति के बाद से विश्व-भारती परिसर में सियासी सरगर्मी बढ़ गई थी पर 15-17 अगस्त के बीच यह बहुत खराब तब स्तर पर पहुंच गई जब विश्वविद्यालय के एक प्रशासनिक फैसले के बाद स्थानीय भीड़ ने उत्पात मचाया. 15 अगस्त को विश्व-भारती प्रशासन ने अपने 20 एकड़ के परिसर में ही स्थित एक बड़े खुले मैदान के चारों ओर एक चारदीवारी का निर्माण शुरू किया. यहां हर दिसंबर में प्रतिष्ठित 'पौष मेला' विश्वविद्यालय प्रशासन ही आयोजित करता आया था. चार दिन से ज्यादा चलने वाला यह मेला विदेशी पर्यटकों को भी आकर्षित करता है, इससे स्थानीय उद्यमियों, शिल्पियों वगैरह के लिए यह एक मुनाफे का मौका देता है.

इससे पहले जुलाई में विश्वविद्यालय प्रशासन ने मेले का आयोजन बंद करने का ऐलान किया था. उसने कथित तौर पर अतिक्रमण और भूमि हड़पने को रोकने के लिए परिसर के इलाके की घेराबंदी का निर्णय लिया है. लेकिन दुनिया को लेकर टैगोर की व्यापक दृष्टि को जीने वाले लोगों के लिए, ये नई बाड़ें और दीवारें अभिशाप जैसी हैं. 17 अगस्त को ग्रामीणों और स्थानीय व्यापारियों का करीब 5,000 लोगों का एक समूह कथित रूप से तृणमूल नेताओं की शह पर विरोध करने और दीवार गिराने पहुंच गया.

असल में विश्वविद्यालय कर्मचारियों-छात्रों में खलबली तो चक्रवर्ती की नियुक्ति के समय ही मच गई थी क्योंकि 2017 में डीयू में गांधी भवन का निदेशक रहने के दौरान उन पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा था. 2015 में डीयू कुलपति के पद के लिए उनकी उम्मीदवारी का भी शिक्षाविदों ने खूब विरोध किया था. यहां आते ही उन्होंने अलोकप्रिय फैसले लेने शुरू कर दिए. इस साल जनवरी में, उन्होंने शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों पर मीडिया से बात करने पर रोक लगा दी; विरोध-प्रदर्शन करने वाले छात्रों को निलंबित करके उन्हें छात्रावासों से बाहर कर दिया; छात्र, शिक्षक और कर्मचारी संघों को भंग कर दिया; कथित अनियमितताओं और कुलपति के खिलाफ छात्रों को लामबंद करने के आरोप में 104 शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए—और उनमें से 12 को निलंबित कर दिया गया.

17 अगस्त की हिंसा के बाद ममता बनर्जी सरकार और केंद्र के बीच एक नई जंग छिड़ चुकी है. केंद्र ने जिला पुलिस से इसकी रिपोर्ट मांगी है और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भीड़ को हिंसा के लिए भड़काने की कथित फंडिंग की जांच शुरू कर दी है. राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने भी ट्विटर पर ममता से आग्रह किया कि वे परिसर में ''तोड़-फोड़ कराने वालों की जवाबदेही तय करने को उचित कार्रवाई करें.'' अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मामला और तूल पकड़ सकता है.

इस मामले में ममता ने साफ कहा, ''मैं विश्व-भारती में ऐसा कोई निर्माण नहीं चाहती, जो उसकी प्राकृतिक सुंदरता को बिगाड़ दे.'' उनकी इस टिप्पणी पर कि दीवार उठाने के दौरान वहां 'बाहरी लोग' (उनका आशय: भाजपा के गुंडे) मौजूद थे, चक्रवर्ती ने चुटकी ली: ''गुरुदेव टैगोर खुद शांति निकेतन के लिए बाहरी थे.'' साफ है: टैगोर के प्रिय शांति निकेतन में शांति जल्दी वापस नहीं लौटने वाली. ■

अर्थात्

ये रिश्ता क्या कहलाता है

अंशुमान तिवारी

मि. जकरबर्ग (फेसबुक) आप अपनी डेटा ताकत से प्रतिस्पर्धियों की जासूसी करते हैं. उनका अधिग्रहण करते हैं या उन्हें मिटा देते हैं?

मि. पिचाई (गूगल) विशेष सेवाओं वाले सर्च इंजन आपको फूटी आंख नहीं भाते. अपनी अकूत ताकत से आप तय करते हैं कि उनको ट्रैफिक न मिल पाए.

और मि. बेजोस (अमेजन) आपके प्लेटफॉर्म से जो कारोबारी सामान बेचते हैं क्या उनके डेटा का इस्तेमाल अमेजन कर रही है?

बीते हफ्तों में जब फेसबुक और भाजपा के रिश्तों को समझने की कोशिश हो रही थी और रिलायंस के डिजिटल कारोबार (सबसे बड़ी मोबाइल कंपनी) में फेसबुक, गूगल, क्वालकॉम (सबसे बड़े सोशल नेटवर्क, ऑपरेटिंग प्लेटफॉर्म व सर्च इंजन और तकनीक कंपनी) के निवेश और माइक्रोसॉफ्ट से करार पर 'जिओ-जिओ' हो रहा था, ठीक उस समय फेसबुक, एपल, गूगल और अमेजन के नेतृत्व अमेरिकी कांग्रेस (संसद) की समिति के कठघरे में थे. इन पर कंपीटिशन खत्म कर गलत तरीके से कारोबार करने गंभीर आरोप हैं.

राष्ट्रपति चुनाव के शोर और कोविड के जोर के बीच अमेरिका की कारोबारी दुनिया नब्बे का दशक याद कर रही है जब उसके आखिरी वर्षों में अमेरिका के कानून निर्माताओं ने बिल गेट्स की कंपनी को इंटरनेट ब्राउजर बाजार में प्रतिस्पर्धा रोकने का दोषी पाया था. यह अभियान उससे कहीं ज्यादा बड़ा और रोमांचक है.

मोनोपली, मुक्त बाजार की पैदाइशी दुश्मन है इसलिए अमेरिका के कानून निर्माता फेसबुक, गूगल, अमेजन और एपल पर ऐंटी ट्रस्ट कानून (बाजार में मोनोपली तोड़ने वाला) के तहत कार्रवाई की पेशबंदी कर रहे हैं. कांग्रेस की समिति इन कंपनियों के अंदरूनी संवादों के आधार पर यह सनसनीखेज मामले बनाए हैं.

फेसबुक ने व्हाट्सऐप और इंस्टाग्राम को निगल कर कैसे कंपीटिशन खत्म किया, इसका खुलासा अब हो रहा है. आपसी खतो-किताबत में कंपनी के अधिकारी यह कहते पाए कि गए प्रतिस्पर्धा खत्म करने के लिए कर्मचारी तोड़ने, कंपनी खरीदने और फिर खत्म कर देने में कोई हर्ज नहीं है.

यूट्यूब अधिग्रहण के पुराने दस्तावेजों के आधार पर गूगल कठघरे में है. कंपनी के गोपनीय संवाद दिखाकर सुंदर पिचाई से पूछा गया कि अगर गूगल के पास रोजगार सर्च आदि के लिए अच्छे रिजल्ट नहीं हैं तो क्या आप अन्य सर्च इंजन को ट्रैफिक नहीं देंगे. क्यों ग्राहक सभी सेवाओं के लिए सिर्फ गूगल के मोहताज रहें?

अमेजन तो फेडरल ट्रेड कमिशन और जस्टिस डिपार्टमेंट की जांच में फंस ही गई है. दुनिया के सबसे बड़े ई रिटेलर पर आरोप है कि उसने अपने प्लेटफॉर्म से सामान बेचने वालों और स्टार्ट-अप का डेटा चुराकर अपने उत्पाद विकसित किए. अमेजन ने थर्ड पार्टी डेटा के दुरुपयोग से इनकार नहीं किया. अभी तक की सुनवाई में एपल पर ज्यादा आरोप नहीं लगे हैं.

ऐंटी ट्रस्ट का हथौड़ा चला तो फेसबुक, गूगल, अमेजन को दो-तीन हिस्सों में तोड़ने की नौबत आ सकती है. और पूरी दुनिया में इन पर कार्रवाई व जुर्माना लगाया जा सकता है.

हैरत की बात है कि जिन कंपनियों को मोनोपली के लिए उनके जन्मस्थान पर सजा देने की तैयारी चल रही है, उन्होंने सिर्फ चार माह में भारतीय बाजार की सूरत ही बदल दी और कंपीटिशन कमिशन ने कुछ भी नहीं किया.

जिओ-फेसबुक-गूगल-माइक्रोसॉफ्ट-क्वालकॉम के एक साथ आने का बाजार के लिए मतलब है:

- भारत के मोबाइल सेवा बाजार में जिओ की हिस्सेदारी 33 फीसद है. दुनिया की सबसे बड़ी तकनीक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर ले कर आई है. गूगल के पास मोबाइल डिवाइस, एंड्राएड ऑपरेटिंग सिस्टम और पेमेंट सर्विस, फेसबुक के पास डेटा, चैट व सोशल नेटवर्क है. क्वालकॉम 5जी की तकनीक से लैस है.
- ये सब जिओ को एक सुपर ऐप बनाने की तरफ ले जाएगा. वह 2025 तक भारत में इंटरनेट के जरिए बिकने वाले सामान का 35 फीसद और डिजिटल पेमेंट का 50 फीसदी बाजार कब्जा सकती है.
- इसके एकाधिकार को ऐसे समझिए कि जैसे पेट्रोल-डीजल उत्पादन करने व बेचने वाली कंपनी पूरे एकाधिकार के साथ इंजन, पुर्जों, टायर, बॉडी, बाहरी भीतरी सुविधाओं सहित पूरी कार बनाए, बेचे, सर्विस दे. उन कारों के लिए हाइवे-सड़कें-गलियां भी बनाए उस पर टोल भी वसूले, उस सड़क के किनारे मकान, मॉल, मल्टीप्लेक्स, बनाए जहां उसी का सामान बेचा जाए. वह कंपनी इन्हें बनाने की तकनीक भी बनाए और यह सब कैसे बनेगा या चलेगा, इसके पैमाने भी तय करे.

कोविड के बाद दुनिया तकनीक केंद्रित होगी लेकिन इसे एकतरफा नहीं होना चाहिए, इसलिए अमेरिकी कानून निर्माता अपनी ही यश कथाओं को कठघरे में खड़ा कर रहे हैं. यह जानते हुए भी कि एकाधिकार, अवसरों के लुटेरे हैं, उपभोक्ताओं को ठगते हैं और ताकत केंद्रीकरण करते हैं. हमारे नेताओं, नियामकों और आत्मनिर्भरतावादियों ने भारत का उभरता बाजार प्लेट में सजाकर दुनिया का सबसे बड़ी मोनोपली को सौंप दिया है.

@anshuman1tiwari

मोनोपली, मुक्त बाजार की पैदाइशी दुश्मन है. भारतीय कंपीटिशन कमिशन ने संभवतः इस तथ्य को बिसरा दिया है

इलस्ट्रेशनः असित रॉय

खास रपट
रिया चक्रवर्ती

कहानी का दूसरा पहलू

सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर पिछले दो महीने से लगातार कटघरे में खड़ा किए जाने के बाद आखिरकार रिया चक्रवर्ती ने चुप्पी तोड़ी और अपने ऊपर लगे आरोपों का बिंदुवार जवाब देते हुए खंडन किया

सुहानी सिंह और किरण डी. तारे

सुशांत सिंह राजपूत की कहानी अभी तक कई किरदारों ने बयान की है. उनका कुक, उनके क्रिएटिव कंटेंट मैनेजर, एक पूर्व गर्लफ्रेंड जिसने चार वर्षों से उनसे बात नहीं की थी, एक कथित सबसे अच्छा दोस्त जिसके कॉल रिकॉर्ड खुलासा करते हैं कि उसने साल भर से ज्यादा वक्त से अभिनेता से बात नहीं की थी, पूर्व कर्मचारी, एक अभिनेत्री जिसके साथ उन्होंने कभी काम नहीं किया, वीडियो और इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए उनका परिवार, और मुंबई पुलिस, प्रवर्तन निदेशालय तथा केंद्रीय जांच ब्यूरो के सूत्रों से जुटाए गए रसीले ब्योरों के जरिए मीडिया. पर इस 34 वर्षीय अदाकार के आखिरी साल में उन्हें अप्रैल 2019 से उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती से बेहतर कोई नहीं जानता था. *इंडिया टुडे टीवी* के साथ खास बातचीत में इस अभिनेत्री ने अपनी खामोशी तोड़ते हुए उन सभी आरोपों का जवाब दिया जो 14 जून को अभिनेता की मौत के बाद 73 दिनों में उनके ऊपर लगाए गए. ऐसा उन्होंने अपने सपने में उनके रिश्ते के बारे में 'सच बताने' की राजपूत की पुकार सुनने के बाद किया. कंसल्टिंग एडिटर राजदीप सरदेसाई के साथ 90 मिनट से ज्यादा चली बातचीत के दौरान रिया ने जिन बातों का खुलासा किया, उनसे एक ऐसी औरत सामने आती है जिसे अचानक हुई इस मौत ने हिलाकर रख दिया, पर वह दो महीनों से ज्यादा वक्त से लगातार उछाले जा रहे आरोपों के तूफान के बीच बहादुरी से डटी है.

रिया ने राजपूत का बांद्रा स्थित डुप्लेक्स अपार्टमेंट छोड़ने से पांच दिन पहले 3 जून को मनोचिकित्सक डॉ. करसी चावड़ा को फोन किया. वे परेशान थीं कि अभिनेता एक बार फिर अवसाद से जूझ रहा था. रिया ने बताया कि चावड़ा ने राजपूत से बात की और माना कि उन्हें दवाइयां देनी पड़ेंगी. इसी दिन राजपूत ने इंस्टाग्राम पर एक मार्मिक पोस्ट साझा की, जो उनकी आखिरी पोस्ट थी. इसमें उन्होंने अपनी मां को याद किया जिनका निधन 2003 में हुआ था. इंटरव्यू के दौरान रिया ने जो सबसे बड़ा खुलासा किया, अगर सच है, तो वह यह है कि सुशांत की मां भी मानसिक सेहत की परेशानियों से दो-चार थीं और उन्हें उनके पिता ने छोड़ दिया था, जिसकी वजह से पिता और पुत्र के रिश्ते में तनाव था. रिया ने कहा कि जब उन्होंने डेट करना शुरू किया, तब सुशांत अपने पिता कृष्ण किशोर सिंह से पांच साल से मिले नहीं थे. यह सुशांत की कजिन दिव्या गौतम की उस बात के विपरीत है, जो उन्होंने 31 अगस्त के अंक में इस पत्रिका से कही थी कि कृष्ण किशोर सिंह 2018 में मुंबई आए थे, तब सुशांत पिता की दवाइयों और इलाज का बहुत ख्याल रखते थे. रिया के इंटरव्यू के तुरंत बाद सुशांत के परिवार का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील विकास सिंह ने *इंडिया टुडे टीवी* को बताया कि सुशांत मई, 2019 में अपने गांव गए थे और अपने पिता के साथ वक्त बिताया था.

सुशांत को उनके परिवार से दूर करने के आरोपों से इनकार करते हुए रिया ने कहा कि बायपोलर डिसऑर्डर का पता चलने पर इलाज शुरू हुआ, तब उन्हें सुशांत के परिवार के उनके साथ होने की अहमियत का एहसास हुआ. वैसे वकील विकास सिंह ने कहा है कि नवंबर में मुंबई के वाटरस्टोंस होटल में अपनी तीन बहनों के साथ मुलाकात के दौरान रिया सुशांत को थोड़ी देर के लिए एक तरफ ले गईं और उन्हें राजी कर लिया कि वे बहनों के साथ दिल्ली न जाएं. इसके जवाब में रिया कहती हैं कि उन्होंने तो दरअसल झगड़े को खत्म करने की अपनी इच्छा जाहिर की थी और सुशांत की बहन प्रियंका को गले लगाया था. उसी प्रियंका को, जिसके ऊपर अप्रैल 2019 में उन्होंने गलत ढंग से छूने का आरोप लगाया था. यह पहला मौका था जब रिया सुशांत की सबसे बड़ी बहन नीतू से मिलीं तथा उन्हें पता चला कि सुशांत की एक और बहन मीतू है जो मुंबई

जो खुशी के दिन थे
साल 2018 में सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती

में ही रहती है. लेकिन सुशांत की एक बहन ने इस मुलाकात का जो ब्योरा दिया है, वह अलग है. उन्होंने सीबीआइ को बताया कि सुशांत के एक बॉडीगार्ड ने परिवार को आगाह किया था कि उनकी जिंदगी खतरे में है. रिया ने सवाल किया, ''अगर उन्हें लगता था कि मैं उसके लिए मुनासिब लड़की नहीं हूं तो वे वाटरस्टोंस में उसे मेरे साथ छोड़कर क्यों चले गए? जनवरी में जब वह चंडीगढ़ गया था (नीतू और उनके पति ओ.पी. सिंह से मिलने) तब उन्होंने उसे (मुंबई लौटन से) रोका क्यों नहीं?''

वाटरस्टोंस में वह मुलाकात रिया और सुशांत के परिवार के बीच झगड़े की जड़ बन गई है. परिवार ने रिजॉर्ट में मुलाकात के दौरान रिया पर आरोप लगाया कि ''सुशांत के अवसाद का इलाज करवाने की आड़ में'' उन्होंने सुशांत को बंधक बना रखा है. सुशांत के बहनोई, आइपीएस अफसर ओ.पी. सिंह ने मध्य फरवरी में मुंबई पुलिस जोन 9 के पूर्व डीसीपी परमजीत सिंह दहिया को भेजे संदेशों में यही आरोप लगाया था.

रिया ने इनकार किया कि अभिनेता की जिंदगी के फैसले वे लेती थीं, ''वह ठीक वही करता था जो वह करना चाहता था.'' वे स्वीकार करती हैं कि सुशांत मैरुआना या गांजे का नशा करते थे. यह बात फरवरी 2019 तक नौ महीने सुशांत के बॉडीगार्ड रहे मुश्ताक ने भी कही. रिया ने इनकार किया कि वे उन्हें आत्महत्या के लिए उकसाने के मकसद से डॉक्टर की लिखी दवाइयां और नशीले पदार्थ देती थीं. असल में, जनवरी में सुशांत को भेजे गए उनके व्हाट्सऐप संदेशों से पता चलता है कि वे उन्हें नशे की लत से उबारने की कोशिशें कर रही थीं. वे साफ तौर पर नाकाम रहीं क्योंकि सुशांत के घरेलू नौकर नीरज सिंह ने उनकी मौत से महज कुछ दिन पहले उन्हें गांजे की सिगरेट बनाकर देने का जिक्र किया है.

रिया पर आरोप है कि वे सुशांत की मानसिक बीमारियों की सच्ची-झूठी बातें गढ़ रही थीं. रिया का कहना है कि ऐसा करके उन्हें भला क्या हासिल होता, खासकर तब जब वे अपने करियर का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट सुशांत के साथ करने वाली थीं. उन्होंने कहा, ''उन्हें मनोचिकित्सकों के पास ले जाकर मैं खुद ही इसे क्यों बर्बाद करना चाहती?'' यहां वे जिस प्रोजेक्ट की बात कर रही हैं, वह रूमी जाफरी के निर्देशन और वासु भगनानी निर्माण में बन रही एक फिल्म थी, जिसके लिए बताया जाता है कि सुशांत को 15 करोड़ रुपए देने का वादा किया गया था. पर कोविड-19 की वजह से करार पर दस्तखत नहीं हो सके, न अभिनेता को मेहनताने का भुगतान किया गया और न ही शुरुआती योजना के मुताबिक मई में शूटिंग शुरू हो सकी.

इत्तेफाक से सुशांत के पिता ने रिया पर अपने बेटे के बैंक खाते से 15 करोड़ रुपए ही हड़पने का आरोप लगाया है. सुशांत के परिवार ने यह भी शिकायत की है कि रिया ने सुशांत के पुराने कर्मचारियों को निकालकर उसके रुपए-पैसों और कारोबारी मामलों को अपने हाथ में ले लिया था. वहीं, रिया का कहना है कि सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा को, जो पटना में दर्ज एफआइआर में एक आरोपी भी है, प्रियंका ने ही नौकरी पर रखा था, जो दिल्ली में रहती हैं और वकील हैं.

मिरांडा ने सुशांत के फ्लैट में उनके साथ रह रहे सिद्धार्थ पिठानी से कहा था कि रिया अभिनेता के डेबिट और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल अपने निजी खर्चों के लिए कर रही थीं, वहीं रिया ने सफाई दी कि वे सुशांत के रुपए-पैसों पर जिंदगी बसर नहीं कर रही थीं. यह सुशांत ही थे जो 'किंग साइज' या उदार और भव्य जिंदगी जीना पसंद करते थे, जिसमें यूरोप के उनके टिकट तथा होटल का भुगतान और इटली में उनके भाई शौविक की मेजबानी करना शामिल था.

अक्तूबर में यूरोप के सैर-सपाटे के दौरान ही रिया को पता चला कि सुशांत की सेहत उतनी अच्छी नहीं थी. यहीं सुशांत ने उन्हें बताया कि 2013 में उन्हें अवसाद या डिप्रेशन का दौरा पड़ा था जिसके लिए उन्होंने डॉ. हरीश शेट्टी से इलाज करवाया था.

यूरोप की उस छुट्टी के दौरान उम्मीद के मुताबिक कुछ भी नहीं हुआ. रिया बताती हैं कि पेरिस में अपनी आखिरी प्रदर्शित फिल्म *दिल बेचारा* के किरदार मैनी की तरह पेरिस की सड़कों पर पूरी आजादी के साथ मौज-मस्ती करने के बजाए, सुशांत ने तीन दिनों तक खुद को पूरी तरह होटल के कमरे में बंद कर लिया. इटली में फ्लोरेंस के पलाजो मयनानी फिरोनी होटल में सुशांत को पक्का वहम हो गया कि कमरे में कोई है, वे सो नहीं सके और उन्होंने कमरा छोड़ने से इनकार कर दिया. यात्रा अधबीच छोड़ दी गई. उसके बाद सुशांत कभी पहले जैसे नहीं रह पाए.

जून का तूफानी महीना

रिया ने 8 जून को नीरज से कहा कि उनका सामान बांध दे और वे दोपहर होते-होते अपने भाई के साथ घर छोड़कर चली गईं. कुक नीरज के मुताबिक, वे परेशान थीं कि सुशांत ने उन्हें विदा तक नहीं किया. रिया जोर देकर कहती हैं कि यह सुशांत ही थे जिन्होंने उन्हें अचानक अपनी बहन मीतू के उनके साथ रहने आने से पहले घर छोड़कर चले जाने को कहा था. उन्हें जिस बात से ज्यादा चोट पहुंची, वह यह कि दुश्चिंता और बेचैनी के दौरों सहित खुद रिया की मानसिक सेहत की परेशानियों के प्रति सुशांत के मन में कोई हमदर्दी नहीं थी और सुशांत ने उनसे कह दिया कि वे डॉ. सुसन वॉकर के साथ अपने थेरैपी सेशन अभिनेता के घर पर नहीं कर सकतीं. उसी दिन रिया और फिल्मकार महेश भट्ट के बीच व्हाट्सऐप पर हुई एक बातचीत से संकेत मिलता है कि यह सुशांत के साथ उनके रिश्ते का अंत था. वे कहती हैं कि उन्होंने भट्ट से इसलिए संपर्क किया क्योंकि सुशांत नहीं चाहते थे कि वे वापस आएं. बाद में 9 जून को जब सुशांत ने उन्हें फोन करने के बजाए उनकी राजी-खुशी जानने के लिए महज एक संदेश भर भेजा, तो उन्होंने उनका नंबर ब्लॉक कर दिया. रिया ने कहा, ''मैं हैरान थी कि क्या वह मुझे इसलिए दूर धकेल देना चाहता था क्योंकि मेरी तबीयत नासाज थी.''

रिया चक्रवर्ती के मुताबिक, सुशांत सिंह राजपूत की मौत का सुराग उनके घर छोड़ने के बाद छह दिनों के दौरान सुशांत के घर में जो कुछ हुआ, उसमें छिपा है

उसी दिन तब सुशांत की मैनेजर दिशा सालियान की अपने मंगेतर के 14वें माले के अपार्टमेंट की बालकनी से गिरकर मौत हो गई. इसे दुर्घटनावश मौत करार दिया गया. मीडिया की सुर्खियों में जब उन्हें सुशांत की मैनेजर बताया गया, तब सुशांत की वकील प्रियंका खेमानी ने उनसे दिशा के बारे में पता करने के लिए फोन किया. रिया का कहना है कि दिशा और सुशांत लॉकडाउन से पहले फरवरी या मार्च की शुरुआत में सुशांत के घर पर बस एक बार मिले थे. उससे पूर्व उनकी पहले वाली मैनेजर श्रुति मोदी को पैर की चोट से उबरने के लिए विराम लेने के लिए कह दिया गया था.

पिठानी ने जूम टीवी को एक इंटरव्यू में कहा कि दिशा की मौत की खबर से सुशांत परेशान हो गए थे. रिया इसकी गवाह नहीं थीं, लेकिन उन्हें इसका अंदाजा था, क्योंकि 2018 में मीटू अभियान के दौरान इसमें सुशांत का नाम आने के बाद रिया उन्हें काफी दिनों तक मानसिक तनाव से गुजरते देख चुकी थीं. अभिनेता पर *दिल बेचारा* की उनकी सह-अदाकारा संजना सांघी ने उत्पीड़न का आरोप लगाया था और फिर डेढ़ महीने बाद उन्होंने सुशांत को बरी भी कर दिया था. सुशांत को यह भी लगता था कि फिल्म उद्योग में उनके काम को मान्यता नहीं दी जा रही थी और वे मानते थे कि उनका काम कितना भी अच्छा क्यों न हो, मान्यता और अवार्ड की शक्ल में कामयाबी कभी उनके हाथ नहीं आएगी. यही वजह थी कि उन्होंने मुंबई से बाहर जा बसने और बस फिल्म करने के लिए कभी-कभार ही महानगर लौटने के मंसूबे बनाए थे.

रविवार की वह अभागी दोपहर

रिया के मुताबिक, सुशांत की मौत का सुराग उनके घर छोड़ने के बाद छह दिनों के दौरान वहां जो कुछ हुआ, उसमें छिपा है. जब सुशांत ने दरवाजा नहीं खोला और न ही पिठानी तथा बहन मीतू के फोन कॉल का जवाब दिया, तो पिठानी ने दरवाजा तोड़ने के लिए एक ताले ठीक करने वाले को बुलाया. पिठानी ने सीबीआइ को बताया कि हरे कुर्ते के सहारे छत के पंखे से लटका सुशांत का शरीर देखने वाले पहले शख्स वही थे. उनके बाद हाउस मैनेजर दीपेश सावंत और नीरज ने वह दृश्य देखा. पिठानी ने मीतू को इत्तला दी कि अभिनेता ने खुद को फांसी लगा ली है. मीतू सुशांत के घर के लिए निकल चुकी थीं. नीतू को भी उसी वक्त फटाफट बताया गया और उन्होंने तथा ओ.पी. सिंह ने पिठानी से कहा कि शरीर को नीचे उतार लो. पिठानी ने ज्यों ही चाकू की मदद से कुर्ता काटा, सुशांत का शरीर बिस्तर पर ढह गया. ठीक इसी पल मीतू कमरे में दाखिल हुईं और सुशांत को उनके घरेलू नाम से पुकारते हुए चीख पड़ीं, ''गुलशन, ये तूने क्या किया''. बताया जाता है कि उन्होंने पिठानी से कहा कि वे उनकी गर्दन में कसा फंदा काट दें और सुशांत के सिर को बिस्तर पर सीधा करके रख दें.

रिया सुशांत की बहन मीतू से अपनी खामोशी तोड़ने की गुजारिश करती हैं, जो अभिनेता के सबसे निराशा के दिनों में उनके साथ मौजूद थीं लेकिन जिन्होंने इसके बावजूद 12 जून को उन्हें छोड़कर जाना चुना. रिया ने सवाल किया कि इतने मुश्किल हालात में अभिनेता को जिस चिकित्सा सहायता की जरूरत थी, वह उन्हें क्यों नहीं दी गई.

इंटरव्यू के दौरान रिया ने खुद पर लगाए गए कई सारे आरोपों का एक-एक कर जवाब दिया. मसलन, इन आरोपों का, कि वे दूसरे के कंधों के सहारे ऊपर चढ़ने वाली शख्स हैं, सुशांत की मानसिक बीमारी की वजह वही थीं, वे उनकी जिंदगी को नियंत्रित कर रही थीं, उनकी कमाई हड़प रही थीं, उन्हें नशीली दवाइयां दे रही थीं. लेकिन उनके बयानों की सचाई और उनके निर्दोष या दोषी होने का दारोमदार अब मामले की जांच कर रही एजेंसियों सीबाआइ, प्रवर्तन निदेशालय और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के ऊपर है. अदाकारा का कहना है कि उन्हें न्यायिक प्रणाली पर, और उससे ज्यादा अपने प्यार पर, भरोसा है. उन्होंने कुबूल किया, ''उससे प्यार करना तो मैं कभी भूल नहीं सकूंगी. मुझे अब भी लगता है वह यहीं है. जो चीज मुझे ताकत देती है, वह यह है कि वह ऊपर से मुझे देख रहा है.'' —साथ में **अमिताभ श्रीवास्तव**

“मैं लड़ूंगी और जीतूंगी. मेरा सच ही मुझे ताकत देता है”

इंडिया टुडे टीवी

खास बातचीत
रिया चक्रवर्ती

इंडिया टुडे टीवी के कंसल्टिंग एडिटर **राजदीप सरदेसाई** के साथ खास बातचीत में **रिया चक्रवर्ती** ने अपना पक्ष रखकर खुद को पाक-साफ बताया. उन्होंने सुशांत के साथ अपने रिश्ते, मानसिक बीमारी को लेकर उनके संघर्ष और उनकी मौत के बारे में सब कुछ बताया

प्र. आप स्टार बनने का सपना लेकर बॉलीवुड आईं. आपको विलेन बताया जा रहा है.

मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि अब मुझे इस तरह देखा जा रहा है. मेरे सपने मर चुके हैं. मैं बस एक गहरी सांस लेना चाहती हूं और नहीं चाहती कि जांच एजेंसियां मेरे पीछे पड़ी रहें. मैं एक सामान्य दिन बिताना चाहती हूं जहां मैं अपने माता-पिता के साथ नाश्ता कर सकूं और मेरे परिवार के किसी सदस्य को चिंता के कारण दौरा न पड़े. लेकिन मैं लड़ूंगी.

● सुशांत के साथ अपने रिश्ते के बारे में बताइए.

हम लंबे समय से दोस्त थे. 2013 में यशराज स्टूडियो के जिम में हमारी जान-पहचान हुई थी. मेरी पहली फिल्म हाल ही में रिलीज हुई थी और सुशांत ने *काई पो चे* के बाद एक नई प्रतिभा के रूप में वाइआरएफ (यश राज फिल्म्स) ज्वाइन किया था! कभी-कभार, अवार्ड शो में एक दूसरे से टकरा जाते थे. यहां तक कि अगर साल में हमारी एकाध बार मुलाकात होती भी, तो हम अपनी सभी समस्याओं पर चर्चा किया करते. मैं उसे पसंद करती थी, उसे दूसरों से अलग पाया. 13 अप्रैल, 2019 को, हम रोहिणी अय्यर [पब्लिसिस्ट] की पार्टी में मिले. यहीं से हमारा रिश्ता शुरू हुआ. उसने मुझे कहा कि वह पहले दिन से ही मुझे पसंद करने लगा था. मुझे रत्तीभर भी अंदाजा नहीं था कि उसे प्यार करने की मुझे इतनी बड़ी कीमत चुकानी होगी?

● उनकी ऐसी कौन सी बात आपको इतना आकर्षित करती थी?

आज तक मैं जितने लोगों से मिली हूं, सुशांत उनमें से सबसे ईमानदार इनसान था. मैंने खुद को उसके आसपास समेट लिया. जितना प्यार उसने मुझे दिया कि मैं खुद पर बड़ा गर्व महसूस करती थी. हमारी दोस्ती हमारे रिश्ते का आधार थी. आपके जीवन की सफलता-असफलता को भुलाकर कोई व्यक्ति आप पर विश्वास करता है. यह सब लुभाता है.

● आप 8 जून को सुशांत को छोड़कर क्यों चली गईं?

लॉकडाउन में सुशांत फिर से डिप्रेशन में चला गया. वह बाइपोलर डिसऑर्डर से पीड़ित पाया गया. ऐसे फेज आते थे जिसमें वह अक्सर कभी बहुत उन्मादी तो कभी बहुत गुमसुम हो जाया करता था. मैं डर गई थी और 3 जून को डॉ. करसी चावड़ा से संपर्क किया और उन्हें बताया कि सुशांत फिर से डिप्रेशन में जा रहा है और उसे मानसिक उन्माद (पैरानॉया) भी है. सुशांत और डॉक्टर ने बात की. डॉ. चावड़ा इस बात से सहमत थे कि उन्हें दवा की जरूरत है. सुशांत 1 जून से मुझसे कटने लगा. वह कहता रहा कि मुझे घर जाना चाहिए. मई-जून में मुझे भी एंग्जायटी अटैक आए थे. वह मुझे कहता है, ‘पहले खुद को बेहतर करो और उसके बाद मुझे ठीक करने में मदद करो.’ 8 जून को, मैंने उसके घर पर ही डॉ. सुसान वॉकर के साथ एक थेरेपी सेशन की योजना बनाई थी. पर सुशांत ने मुझे कहा कि घर जाओ और यह थेरेपी सेशन यहां मत लो. उसने कहा कि उसकी बहन मीतू आ रही है. जून में वह अपने परिवार से कूर्ग में शिफ्ट होने की योजना के बारे में बात करता रहा और पूछा कि क्या कोई आ सकता है. लेकिन परिवार के लोगों की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली. मैंने केवल एक शर्त रखी, मीतू को आ जाने दो उसके बाद मैं चली जाऊंगी. जब कोई व्यक्ति मानसिक स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहा है, तो यह महत्वपूर्ण है कि परिवार उसके साथ खड़ा हो. उसके परिवार के साथ मेरा रिश्ता शुरू से ही अच्छा नहीं था.

● पर महेश भट्ट को आपने जो व्हॉट्सऐप मैसेज उसमें आपने बताया कि आप सुशांत से अलग होने का फैसला कर चुकी हैं.
मैंने महेश भट्ट से बात की क्योंकि वे मेरे लिए पितातुल्य हैं. मैंने उन्हें बताया कि मेरे अंदर अब और ताकत नहीं है. मैंने उनसे पूछा, 'उसने (सुशांत ने) मुझे अपने घर से निकाल दिया है, मैं क्या करूं?' उन्होंने मुझे समझाया कि अपने पिता के बारे में सोचो और उनके लिए मजबूत बनो. हमारी इस बातचीत को गलत तरीके से पेश किया गया.

● यूरोप में क्या हुआ था? कब पता चला कि सुशांत को कोई मानसिक बीमारी है?
जब हम पेरिस पहुंचे, तो वह तीन दिनों तक अपने कमरे से बाहर ही नहीं आया. मुझे यह थोड़ा अजीब लगा क्योंकि वह सड़कों पर घूमने और मस्ती के लिए बहुत उत्साहित था. स्विट्जरलैंड में, वह खुश था और बहुत उत्साहित भी. पर इटली में हम एक गोथिक होटल, पलाजो मैगनानी फेरोनी में रुके थे. हमारे कमरे में एक गुंबदनुमा छत थी, जिसमें कुछ डार्क पेंटिंग थी. सुशांत उस रात सो नहीं सका. उसने कहा कि यहां कुछ है. अगर कोई कहने लगे कि यह जगह भूतिया है और उसे कुछ विचित्र चीजें दिखाई दे रही हैं तो हमारा चिंतित होना

> ''इसके सबूत कहां हैं कि मैंने पैसे निकाले? उन खातों को पता लगाएं. फ्रंट इंडिया फॉर वर्ल्ड फाउंडेशन में सुशांत 99 फीसद हिस्सेदार हैं. मैं और मेरे भाई जिन दो कंपनियों से जुड़े हैं उनमें कोई लेन-देन हुआ ही नहीं है''

स्वाभाविक था. लेकिन वह उस होटल को छोड़ने के लिए भी राजी नहीं था. उसकी हालत खराब हो गई थी, इसलिए हमें यात्रा रोकनी पड़ी और उसे वापस भारत लाना पड़ा.

● आरोप लगाए जा रहे हैं कि आप और आपका परिवार उनके पैसे पर ऐश कर रहा था.
मुझे खुद इस बात से समस्या थी कि वह कितना खर्च क्यों कर रहा है. वह एक स्टार, एक राजा की तरह जीता था. वह थाईलैंड घूमने गया, जहां उसने अपने दोस्तों को साथ ले जाने के लिए एक निजी जेट किराए पर लिया और उसके लिए 70 लाख रुपए खर्च कर दिए. मैं उसके पैसे पर नहीं जी रही थी. हम एक प्रेमी युगल की तरह रह रहे थे.

● आप और आपके भाई शॉविक उनकी दो कंपनियों के डायरेक्टर हैं. आरोप हैं कि इस कंपनी के आपके भाई के नाम पर बेनामी खाते हैं और उसके जरिए आपने पैसे निकाले हैं.
कोई सबूत है? उन खातों का पता लगाएं. एक भी पैसे का लेन-देन नहीं हुआ है. दूसरी कंपनी फ्रंट इंडिया फॉर वर्ल्ड फाउंडेशन एक गैर सरकारी संगठन है, जिसके माध्यम से सुशांत बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान करना चाहता था. सुशांत इसमें 99 प्रतिशत हिस्सेदार है और शॉविक को मात्र 1 फीसद हिस्सेदारी दी गई थी. मेरे भाई और मैं जिन दो कंपनियों से जुड़े हैं उनमें कोई लेन-देन हुआ ही नहीं है.

● सुशांत के पिता का आरोप है कि आपने कई खाते में लेन-देन के जरिए उनके बेटे से 15 करोड़ रुपए ऐंठ लिए.
वे 15 करोड़ रुपए कहां हैं? मेरे खाते में तो नहीं है. मैं सभी जांच एजेंसियों के साथ सहयोग कर रही हूं. सुशांत के बैंक स्टेटमेंट लीक हो गए हैं और सभी जानते हैं कि उसके खाते में 15 करोड़ रु. थे ही नहीं.

● फिर सुशांत का परिवार ऐसे गंभीर आरोप क्यों लगा रहा है कि आपने नवंबर में उन्हें सुशांत से संपर्क नहीं करने दिया और आप सुशांत की जिंदगी के सारे फैसले कर रही थीं?
यह सच नहीं है. 8 जून को, वह अपनी बहन मीतू के साथ था, और मैं भी चाहती थी कि मीतू वहां रहें. फरवरी में, वह अपनी बहन और बहनोई से बांद्रा के एक कैफे में मिला और अच्छा समय बिताया. तो यह अलगाव की बात कहां से आई? 20 जनवरी को, वह चंडीगढ़ [अपनी बहन से मिलने] के लिए सड़क मार्ग से गया. वह कुछ दिनों में ही लौट आया. उन्होंने उसे रोका क्यों नहीं? हो सकता है वह आपके साथ नहीं रहना चाहता हो. हो सकता वह आपको पसंद नहीं करता हो. मुझे नहीं पता कि वह क्यों इतनी जल्दी वापस आ गया.

● आइपीएस अधिकारी ओ.पी. सिंह (सुशांत की बहन नीतू के पति) का दावा है कि उन्होंने फरवरी में मुंबई पुलिस से शिकायत भी की थी कि सुशांत के जीवन को इसलिए खतरा है क्योंकि वह आपके साथ रहते हैं.
वे एक वर्दीधारी अधिकारी हैं और प्रोटोकॉल जानते हैं. अगर वे सुशांत के बारे में चिंतित थे, तो फिर फरवरी में एक कैफे में सुशांत के साथ खाना क्यों खा रहे थे और लिखित शिकायत क्यों नहीं दर्ज कराई? किसी ने तो उन पर विश्वास किया होता. इसके बजाए, उनके शब्द थे, 'आप रिया को पकड़ लीजिए और उसे मारिए'

● अगर आप सुशांत को इतना प्यार करती थीं तो आपने उनके परिवार से क्यों नहीं संपर्क किया?
मैंने कोशिश की थी. जब वे (उनकी बहनें) उससे मिलने आईं, तो मैंने सबसे बड़ी बहन (प्रियंका, मतभेदों के बावजूद) के पैर छुए. उनके भाई का मानसिक स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण था. वह रो रहा था और दो महीने से उन्हें फोन कर रहा था. वे पहले क्यों नहीं आईं? मैं चाहती थी कि उसका परिवार उसके साथ रहे और उसे उबरने में मदद करे. लेकिन वे लोग आते और एक दिन में ही वापस चले जाते थे.

● उनके पिता का क्या था?
सुशांत खुद कहते थे, पिता के साथ उनके रिश्ते बचपन से ही अच्छे नहीं थे. सुशांत जब बहुत छोटे थे तभी उनके पिता ने उनकी मां को छोड़ दिया था. सुशांत अपनी मां से बहुत नजदीक थे. पिता के इस काम से उन्हें बहुत दुख हुआ था.

● क्या उनके डिप्रेशन की वजह से आप उनसे दूर हो गईं?
इसकी वजह से मैं ज्यादा नजदीक आई. जब आप किसी का ख्याल रखने लगते हैं, तो आप उसके लिए नर्स या मां की तरह हो जाते हैं...आप उन्हें बिला शर्त प्यार करने लगते हैं.

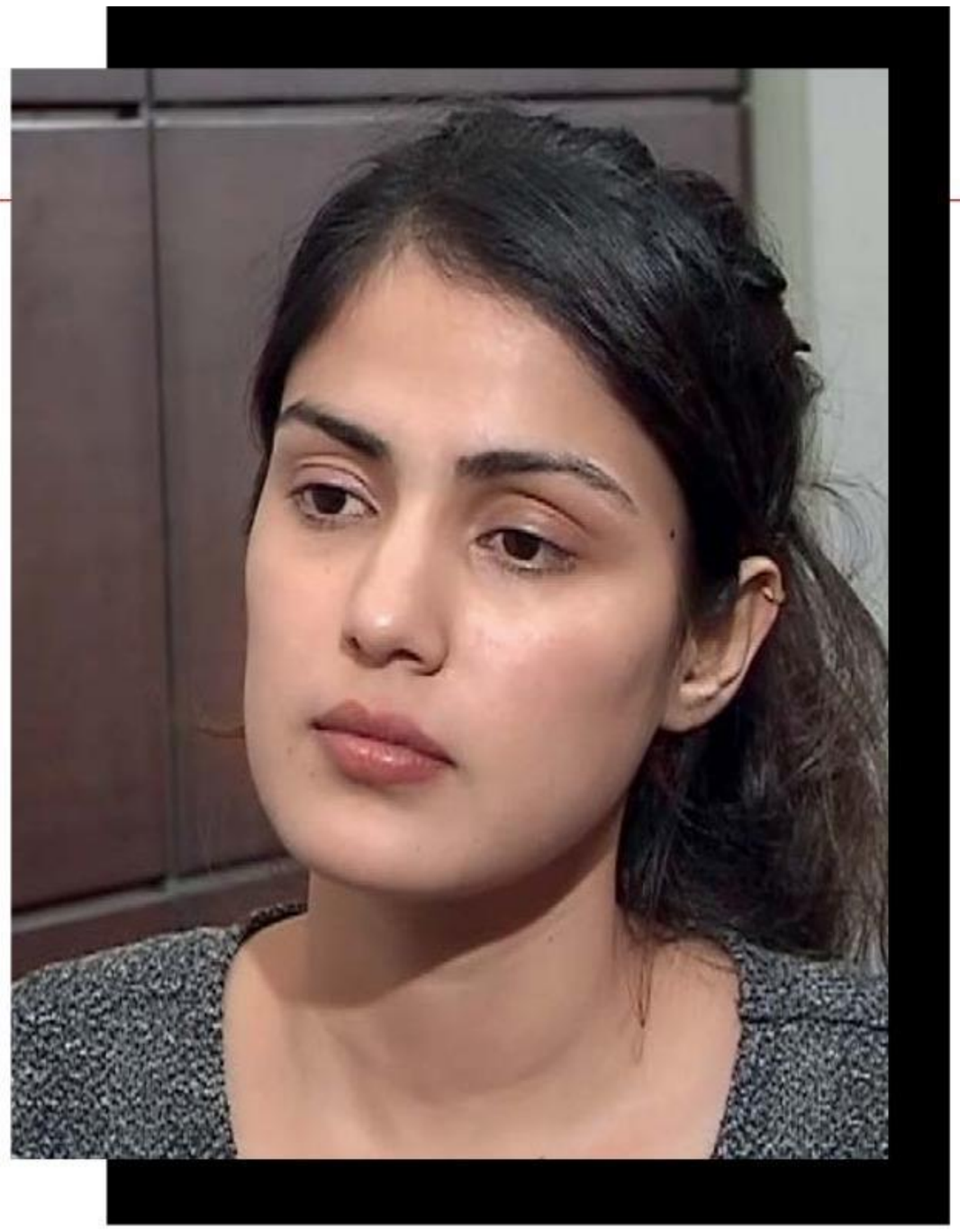

● आरोप हैं कि आपने सुशांत की जिंदगी को नियंत्रित करना शुरू कर दिया और उनके कर्मचारियों को बदल दिया.
यह आधारहीन आरोप है. जब मैं पहली दफा सुशांत के घर गई थी, सिद्धार्थ पिठानी पहले से वहां रह रहे थे. हाउस मैनेजर मिरांडा को प्रियंका ने नियुक्त किया था. कुक केशव, सफाईकर्मी नीरज, दीपेश, सब पहले से थे.

● वे कह रहे हैं कि आपने अपने और अपने परिवार के पेशेवर हितों के लिए उभरते सितारे सुशांत का शोषण किया.
आप इस बारे में रूमी जाफरी से पूछ सकते हैं. जून और जुलाई, 2019 में जब मैं *चेहरे* की शूटिंग कर रही थी तो सुशांत मुझसे मिलने सेट पर आया करता था. वहीं वह रूमी से मिला. वे लोग नादिरा बब्बर के थिएटर ग्रुप के साथ काम करते थे और उनकी पहचान वहीं से थी. उसने रूमी से कहा कि वह मेरे साथ एक नाटक *लैला–मजनूं* करना चाहता है. अन्नू कपूर इस नाटक को निर्देशित करते और रूमी इसे लिखते. सुशांत चाहता था कि रूमी उसके लिए एक फिल्म लिखें जिसमें वह मेरे साथ काम करना चाह रहा था.

● क्या इसी फिल्म के लिए आपको 15 करोड़ रुपए का साइनिंग अमाउंट मिला था?
वासु भगनानी ने उसे फिल्म के लिए 15 करोड़ रुपए का प्रस्ताव दिया था. सुशांत इससे खुश था. यह फरवरी में हुआ था जब उसकी बहन और बहनोई उससे मिलने आए थे. सुशांत ने उन्हें यह अच्छी खबर सुनाई थी और बातचीत में 15 करोड़ का जिक्र किया था. मुझे लगता है कि शायद उसी 15 करोड़ रुपए के बारे में बात की जा रही है.

● क्या आप कह रही हैं कि 15 करोड़ रुपए बैंक खाते में नहीं डाले गए थे?
बिल्कुल. किसी कागजात पर साइन नहीं हुए. यह मौखिक समझौता था. लॉकडाउन से अनुबंध टल गया. पैसे का कोई लेन–देन नहीं हुआ.

● क्या आपका किसी ड्रग कारोबारी के साथ कोई संबंध है?
बस यही आरोप बाकी रह गया था...मुझे सूली पर चढ़ाया जा रहा है.

● हाउसकीपर मिरांडा (रिया को एक व्हाट्सऐप मैसेज में) ने कहा कि ड्रग स्टॉक खत्म हो गया है. नशा कौन करता था? आप या सुशांत?
दुर्भाग्यपूर्ण कि मुझे यह बात किसी की मौत के बाद कहनी पड़ रही है. सुशांत प्राय: मारिजुआना का सेवन करता था. मुझसे मिलने से पहले से करता था. उसे यह आदत *केदारनाथ* की शूटिंग से पहले लगी थी. असल में, यही वह बात थी जिसमें मैं उसे कंट्रोल करने की कोशिश करती थी. पर सुशांत हमेशा वही करता था जो वह करना चाहता था.

● क्या सुशांत ने आप से 8 से 14 जून के बीच संपर्क किया?
मुझे सुशांत का आखिरी मैसेज 9 जून को मिला कि 'हाउ आर यू माइ बेबू?' मैं उदास थी क्योंकि वह जानता था कि मेरी तबीयत खराब है. उसने मुझे मेसेज किया, पर कॉल नहीं किया. इसलिए मैंने उसे 9 जून को ब्लॉक कर दिया क्योंकि मुझे लगा कि अब वह मुझे नहीं चाहता. मैं उसके और उसकी बहन के बीच नहीं आना चाहती थी. मेरे अभिभावकों को इसके बारे में पता नहीं था. वह हमारे पारिवारिक ग्रुप में भी था. वह तब भी मेरे भाई के साथ संपर्क में था. उन्होंने उसे 10 जून को मेसेज करके पूछा कि मैं कैसी हूं. उसने यह नहीं जिक्र किया कि उसे मेरी जरूरत है, वह ऐसा कहता तो मैं उसके पास लौट जाती.

● आप शवगृह गई थीं जहां सुशांत का शरीर रखा था. वहां आपने कहा, आइ एम सॉरी बाबू. क्या यह सही बात है?
अगर किसी ने अपनी जान दे दी है तो आप इसके अलावा और क्या कहेंगे? आइ एम सॉरी यू लॉस्ट योर लाइफ.

● चीजें जिस तरह से घटीं आपको उसका खेद है?
मुझे खेद है कि हमने उस सबसे खूबसूरत लड़के को खो दिया. मुझे उस जोक पर खेद है कि एक इनसान की जिंदगी, उसकी मौत पर बनाया जा रहा है. कम से कम उसकी इज्जत रखिए.

● यह कहा जा रहा है कि सुशांत नेपोटिज्म के शिकार थे; कि लोग अपने लोगों को ही बॉलीवुड में आगे बढ़ाते हैं. क्या उन्होंने कभी आपसे कहा कि वे इस इंडस्ट्री के शिकार हैं?
सुशांत इससे अपसेट रहता था कि उसे फिल्म पुरस्कारों के लिए नामित नहीं किया जाता. खासकर, इसलिए क्योंकि उसने *सोनचिरैया* और *छिछोरे* जैसी बहुत सारी कामयाब और अलग किस्म की फिल्में की थी. हालांकि उसकी फिल्में थीं, तकनीशियन थे (नामित) पर सुशांत का नाम कहीं नहीं था. और वह इस बात से अपसेट था.

● कभी आत्महत्या का ख्याल आया?
हां. शायद मेरे पूरे परिवार को आत्महत्या कर लेनी चाहिए या कोई आकर बस हमें गोली मार दे. हम स्तब्ध और अपमानित महसूस कर रहे हैं. हम लोग मध्यवर्गीय लोग हैं. हमारे पास इज्जत के अलावा कुछ और नहीं है. आज, मुझे एक ड्रग डीलर बताया जा रहा है, कल मैं एक हत्यारिन थी. यह अंतहीन और आधारहीन है.

● लेकिन आप लड़ेंगी...
मैं लड़ूंगी और मैं जीतूंगी. और मैं चाहती हूं कि यह जीत सिर्फ मेरी खातिर न हो, बल्कि हर उस औरत के लिए हो जिन्हें गालियां दी जाती है, तिरस्कार किया जाता है, इसलिए कि वे किसी से प्यार करती थीं और उसके साथ रह रही थीं. ■

ढाक के तीन पात

सात अगस्त को सोनिया गांधी को लिखा गया खत कांग्रेस के लिए इलाज को मजबूर करने वाली चोट जैसा हो सकता था, पर हमेशा की तरह गांधी परिवार के भक्तों ने एकजुट हो खत लिखने वालों की ही लानत-मलामत कर डाली

कौशिक डेका

अगस्त की 24 तारीख को कांग्रेस कार्यसमिति (सीडब्ल्यूसी) की बैठक एक चिट्ठी पर विचार-विमर्श के लिए बुलाई गई थी. यह पत्र नेताओं के एक समूह ने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को लिखा था. पार्टी की सर्वोच्च निर्णायक संस्था दो संकल्पों के साथ खत्म हुई और ये दोनों ही अनुमान के अनुरूप थे. एक, उसने सोनिया से तब तक अध्यक्ष बने रहने को कहा ''जब तक परिस्थितियां अखिल भारतीय कांग्रस समिति (एआइसीसी) का अधिवेशन बुलाने की इजाजत न दें''; दूसरा, उन्हें संगठन में अपनी समझ से कोई भी उपयुक्त बदलाव करने को अधिकृत कर दिया गया.

चिट्ठी पर 7 अगस्त की तारीख थी और इस पर कम से कम 23 नेताओं ने दस्तखत किए थे. इसमें कई दूसरी बातों के अलावा पूर्णकालिक, सक्रिय और सर्वसुलभ नेतृत्व के साथ-साथ सामूहिक नेतृत्व के एक सांस्थानिक तंत्र की मांग की गई थी, जिसका 'गांधी परिवार अभिन्न अंग होगा.' इससे दो साफ और दोटूक बातें निकलीं. एक, सोनिया के कांग्रेस अध्यक्ष बने रहने को लेकर तारी अनिश्चितता खत्म होनी चाहिए; दूसरे, गांधी परिवार को सारी सत्ता और अधिकार अपनी मुट्ठी में रखने के बजाए एक सामूहिक व्यवस्था में उनका इस्तेमाल किया जाना चाहिए. कइयों ने इसे गैर-गांधी पार्टी अध्यक्ष की मांग के तौर पर देखा, दूसरों ने इसे पार्टी के असली मुखिया राहुल गांधी के लिए मिल-जुलकर फैसले लेने की कार्यप्रणाली अपनाने के इशारे की तरह देखा.

लिहाजा कार्यसमिति के फैसलों से यह धारणा बनी कि उन तमाम मुद्दों को सिरे से खारिज कर दिया गया है जो पत्र पर दस्तखत करने वालों ने उठाए थे. इन पत्र लेखकों में राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद, कार्यसमिति के सदस्य आनंद शर्मा, मुकुल वासनिक और जितिन प्रसाद, पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी, शशि थरूर, कपिल सिब्बल और मिलिंद देवड़ा, पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह

मोहम्मद जाकिर/गेट्टी इमेजेज

छाया राज?
कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी बेटे राहुल गांधी के साथ

चिट्ठी का मजमून लीक हो जाने की वजह से उसमें उठाए गए मुद्दों से ध्यान ही हट गया. कुछ नेताओं ने तो इसमें भाजपा के साथ मिलकर की जा रही एक साजिश भी सूंघ ली

हुड्डा और पृथ्वीराज चव्हाण और बिहार चुनाव अभियान के मौजूदा प्रमुख अखिलेश प्रसाद सिंह शामिल थे. कांग्रेस महासचिव (संगठन) के.सी. वेणुगोपाल ने यह तो कहा कि अगला अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया यथासंभव जल्द से जल्द शुरू होगी, लेकिन सामूहिक नेतृत्व या संगठन चुनावों की दिशा में उठाए जा रहे कदमों का कोई जिक्र न किया. कार्यसमिति के संकल्प ने निकट भविष्य में गैर-गांधी कांग्रेस अध्यक्ष की संभावना को भी खारिज कर दिया. संकल्प कहता है, ''अत्यधिक प्रबल विचार और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की इच्छा को देखते हुए कार्यसमिति ने एकमत से हर संभव तरीके से सोनिया गांधी और राहुल गांधी के हाथ मजबूत करने का संकल्प लिया.'' बैठक में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सामूहिक नेतृत्व का विचार साफ और दोटूक खारिज कर दिया, ''सामूहिक नेतृत्व पर उनके जोर देने से कोई मकसद नहीं सधेगा. हमें नेतृत्व देने के लिए सोनिया जी और राहुल जी पर भरोसा करना पड़ेगा.'' पूर्व लोकसभा सांसद सुष्मिता देव कहती हैं, ''मैं पार्टी में कमेटियों से थक चुकी हूं. हर फैसले के लिए विचार-विमर्श के बहुत सारे दौर चलते हैं. क्या यह सामूहिक नेतृत्व नहीं है?''

अलबत्ता पत्र लेखक इसे 'मुंहतोड़ हार' (जैसा कि उनके विरोधी इसे पेश कर रहे हैं) के तौर पर स्वीकार करने को तैयार नहीं. वे दावा करते हैं कि उन्होंने जिन सुधारों की मांग की है, कांग्रेस का अधिवेशन उनकी शुरुआत की दिशा में पहला कदम होगा. दस्तखत करने वाले एक प्रमुख नेता ने *इंडिया टुडे* से कहा, ''पत्र में सोनिया या राहुल के नेतृत्व पर सवाल नहीं उठाए गए थे. यह पार्टी में सांस्थानिक सुधारों और अगले आम चुनाव में 272 की उड़ान का रास्ता खोजने के बारे में था.'' एक और पत्र लेखक ने कहा कि वे ''रातोरात बदलाव होने की उम्मीद नहीं कर रहे थे. सार्वजनिक तौर पर स्वीकार किया गया है कि महामारी से उबरते ही अध्यक्ष पद का चुनाव होगा. कांग्रेस का अधिवेशन बुलाया जाएगा, जिसका मतलब है कि कार्यसमिति के कुछ चुनिंदा सदस्य अपनी इच्छाएं पूरी पार्टी पर नहीं थोप सकेंगे. यह अच्छी शुरुआत है.''

यह अच्छी शुरुआत हो या न हो, संगठन में सुधार लाने की इस धड़े की कोशिश ने शुरुआत में ही खटास पैदा कर दी जब

विरोध एक स्वर से

गुलाम नबी आजाद
राज्यसभा में विपक्ष के नेता, कार्यसमिति सदस्य

आनंद शर्मा
राज्यसभा सदस्य, कांग्रेस कार्यसमिति सदस्य

भूपिंदर सिंह हुड्डा
पूर्व मुख्यमंत्री, हरियाणा

कपिल सिब्बल
राज्यसभा सदस्य और पूर्व केंद्रीय मंत्री

शशि थरूर
लोकसभा सदस्य और पूर्व केंद्रीय मंत्री

मनीष तिवारी
लोकसभा सदस्य और पूर्व केंद्रीय मंत्री

वीरप्पा मोइली
कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री

जितिन प्रसाद
पूर्व केंद्रीय मंत्री

मिलिंद देवड़ा
पूर्व केंद्रीय मंत्री

पृथ्वीराज चौहान
महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और पूर्व केंद्रीय मंत्री

चिट्ठी की मुख्य बातें कार्यसमिति की बैठक से एक दिन पहले एक मीडिया संस्थान को बता दी गईं. इन नेताओं को अपनी चिंताएं जाहिर करने का पूरा अधिकार था, लेकिन लीक होने की वजह से, उठाए जा रहे मुद्दों से ध्यान भटक गया. इसकी बजाए बैठक में उन्हें चिट्ठी की मंशा और समय को लेकर सवालों का सामना करना पड़ा. कुछ ने तो भाजपा के साथ सांठगांठ से साजिश की तरफ इशारा किया. यहां तक कि नपा-तुला बोलने वाले नेता भी 'पत्र लेखकों' पर जमकर बरसे. मनमोहन सिंह ने कहा, ''सोनिया गांधी को अध्यक्ष बने रहना चाहिए और निहित स्वार्थों की ओर से उठाई जा रही गैरमौजूं बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए...ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि उन्होंने यह सब मीडिया के जरिए उठाया.''

अप्रिय बाता-बाती के अलावा इस प्रसंग से पार्टी के भीतर की वह फूट भी उजागर हो गई है जो पिछले दो-एक साल में उभरी है. इसके केंद्र में हैं राहुल गांधी. असल में, माना जा रहा है कि यह चिट्ठी बम कांग्रेस की नई कार्यकारी टीम की प्रतिक्रिया में फोड़ा गया है जिसकी योजना पिछले दो महीने से भी ज्यादा समय से बनाई जा रही थी. इसमें मुख्यत: ऐसे लोग शामिल होंगे जो 'कांग्रेस को लेकर राहुल के विजन से मेल खाते' हैं. पार्टी के अंदरूनी लोगों का दावा है कि राहुल कांग्रेस के शीर्ष पद पर तब तक लौटने को राजी नहीं जब तक उनकी पसंद की टीम काबिज न हो और पार्टी 'निजी हितों को तरजीह देने वाले' नेताओं से निजात न पा ले.

पिछले साल लोकसभा चुनाव में पार्टी की बुरी हार की जिम्मेदारी लेकर कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देते वक्त राहुल ने तकलीफ जाहिर की थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा-आरएसएस की मशीनरी के खिलाफ अपनी लड़ाई में उन्हें अक्सर अकेला छोड़ दिया गया. 23 जून को कार्यसमिति की बैठक में भी उन्होंने यही शिकायत की और ज्यादातर नेताओं पर मोदी की सीधी आलोचना से बचने का आरोप लगाया. उनकी बहन और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी उनका साथ दिया, जबकि राहुल के साथ अपनी नजदीकी के लिए जाने जाने वाले राज्यसभा सदस्य राजीव सातव ने वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं में जुझारूपन न होने का आरोप लगाया. इसका जवाब 7 अगस्त की चिट्ठी पर दस्तखत करने वालों में शामिल आनंद शर्मा ने दिया. उन्होंने कहा कि कई बड़े नेताओं ने मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आगे रहकर मोर्चा संभाला है, संसद के रिकॉर्ड इसके गवाह हैं.

इनमें से कुछ 'पत्र लेखकों' और राहुल के वफादारों के बीच तनाव 30 जुलाई को कांग्रेस के राज्यसभा सांसदों के साथ सोनिया गांधी की बैठक में भी सामने आए. जब एक और पत्र लेखक और पूर्व

कहां रखी उंगली

चिट्ठी में उन 'बीमारियों' की पहचान की गई थी जिनसे कांग्रेस ग्रस्त रही है

- युवाओं ने नरेंद्र मोदी के पक्ष में निर्णायक ढंग से वोट डाला है जबकि उनके बीच अपना आधार तेजी से खो रही है. यह गंभीर चिंता का विषय है.
- पार्टी का इतनी तेजी से पतन उस समय हो रहा है जब देश आजादी के बाद सबसे गंभीर राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा है. यहां तक कि लोकसभा चुनाव में बुरी तरह हार को साल भर से ज्यादा बीत जाने के बाद भी पार्टी ने अपने निरंतर अवसान के कारणों को जानने के लिए ईमानदारी से कोई आत्मनिरीक्षण शुरू नहीं किया है
- नेतृत्व को लेकर अनिश्चितता और पार्टी में अंदरूनी स्थिति डावांडोल होने से कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरा है
- कांग्रेस कार्यसमिति (सीडब्ल्यूसी) भाजपा सरकार के खिलाफ जनमत बनाने में 'प्रभावी भूमिका' नहीं निभा पा रही. कार्यसमिति की बैठकें 'कभीकभार' होती हैं और वे भी राजनैतिक घटनाक्रमों की प्रतिक्रिया में बुलाई जाती हैं. कांग्रेस संसदीय दल (सीपीपी) की बैठक तो सीपीपी अध्यक्ष सोनिया गांधी रस्मी भाषणों और शोक सभाओं तक ही महदूद होकर रह गई है
- प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षों और दूसरे पदाधिकारियों जैसी अहम नियुक्तियों के मामले बिलावजह लटकाकर रखे जाते हैं, किसी राज्य में सम्मानप्राप्त और व्यापक स्वीकार्यता वाले नेताओं की समय पर नियुक्ति ही नहीं होती. राज्य कांग्रेस अध्यक्षों को संगठन के बारे में निर्णय लेने की आजादी ही नहीं होती
- युवक कांग्रेस और भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ (एनएसयूआइ) में चुनावों की जो परंपरा शुरू की गई है, उसने खासे टकराव और विभाजन वाली स्थितियां बना दी हैं. इससे हुआ यह है कि इन संगठनों पर उन लोगों ने 'कब्जा' करना शुरू कर दिया जिनके पास या तो अकूत पैसा था या जिन्हें किसी राजनैतिक संरक्षण हासिल था

बताया इलाज भी

चिट्ठी में वे उपाय भी सुझाए गए हैं जिनके जरिए कांग्रेस फिर से उठ खड़ी हो सकती है

- पूर्णकालिक अध्यक्ष हो जो हमेशा सक्रिय और पार्टीजनों को उपलब्ध रहे
- सामूहिक नेतृत्व का कोई संस्थागत तरीका ईजाद किया जाए, गांधी परिवार के सदस्य जिसका अपरिहार्य अंग हों
- कांग्रेस कार्यसमिति का चुनाव पार्टी संविधान के तहत हो; कार्यसमिति राष्ट्रीय एजेंडा तय करने और नीतिगत पहलों के लिए एक विचार-बहस की इकाई, उसका मंच बने
- कांग्रेस संसदीय बोर्ड की अवधारणा को फिर से जिंदा किया जाए, जिसमें पार्टी अध्यक्ष और नौ दूसरे सदस्य शामिल रहें
- ब्लॉक, राज्य और अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के स्तर पर संगठनात्मक चुनाव हों
- एक स्वतंत्र चुनाव इकाई बनाई जाए जो जो साफ-सुथरे, निष्पक्ष और लोकतांत्रिक ढंग से सगंठनात्मक चुनाव कराने का पुख्ता इंतजाम करे
- समान सोच वाली पार्टियों का एक राष्ट्रीय गठजोड़ बने और कांग्रेस छोड़कर गए नेताओं को फिर से साथ लाने के उपाय किए जाएं

केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने पार्टी की ढलान के लिए अपने भीतर झांकने और ईमानदार चर्चा की मांग की, सातव ने पलटवार करते हुए कहा कि अपने भीतर झांकने की शुरुआत यूपीए-दो के वक्त से होनी चाहिए. अगले दिन तिवारी, थरूर और शर्मा सरीखे यूपीए की सरकार में मंत्री रह चुके नेताओं ने सातव का नाम लिए बगैर सोशल मीडिया पर इसका जवाब दिया और कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को यूपीए और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की उपलब्धियों पर गर्व होना चाहिए. एक हफ्ते बाद सोनिया गांधी के नाम वह पांच पेज की चिट्ठी सामने आई.

कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक, पत्र लेखक 'अपनी मां सोनिया गांधी की ओर से पार्टी चला रहे' राहुल और पार्टी के सत्ता ढांचे में आगे बढ़ते उनके विश्वासपात्रों के साथ लगातार ज्यादा से ज्यादा असहज महसूस कर रहे थे. मसलन, उनके पसंदीदा वेणुगोपाल को न केवल महासचिव (संगठन) बनाया गया बल्कि राजस्थान से राज्यसभा में भेजा गया. सातव को गुजरात से संसद के ऊपरी सदन में लाया गया. उनके एक और पुराने वफादार अजय माकन को हाल में राजस्थान का प्रभारी महासचिव बनाया गया और कार्यसमिति में शामिल किया गया. सुष्मिता देव अब पार्टी की महिला शाखा की प्रमुख हैं. असम से लोकसभा सांसद 37 वर्षीय गौरव गोगोई पश्चिम बंगाल के प्रभारी हैं, जहां से लोकसभा की 42 सीटें आती हैं.

इससे पहले 18 अप्रैल को जब सोनिया गांधी ने 'मौजूदा चिंता के विषयों पर विचार-विमर्श' के लिए 11 सदस्यीय सलाहकार समूह का गठन किया था, इसमें सात ऐसे नेताओं को शामिल किया गया था जो पार्टी में अपनी हैसियत के लिए राहुल के ऋणी हैं. इससे कई लोगों में नाराजगी पैदा हुई. गुलाम नबी आजाद और आनंद शर्मा सरीखे दिग्गज नेताओं को न लिया जाना उभरते भावी नेतृत्व का संकेत था. पत्र लेखकों ने इस हफ्ते चिट्ठी में राहुल की तो तारीफ की, लेकिन उनके हाथों शुरू की गई युवक कांग्रेस और एनएसयूआइ की चुनाव प्रक्रिया की आलोचना से साफ हो गया कि उनके नेतृत्व के कुछ निश्चित पहलू इस समूह के नेताओं को रास नहीं आए. चिट्ठी में दावा किया गया कि इस चुनाव प्रक्रिया की वजह से धनबल और राजनैतिक संरक्षण वाले लोगों ने इन संगठनों की राज्य इकाइयों पर कब्जा कर लिया है.

ये 'विद्रोही' राहुल के उस अफसाने का हिस्सा भी नहीं थे, और खुद अपनी इच्छा से नहीं थे, जो वे कोविड-19 महामारी से लेकर लद्दाख में चीनी आक्रामकता तक कई सारे मुद्दों पर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बुनने की कोशिश करते आ रहे हैं. इनमें से कई तो मोदी पर राहुल के निजी हमलों से असहज थे, क्योंकि ये उलटे कांग्रेस को ही नुक्सान पहुंचाते मालूम देते थे. कई दूसरे नेता (जो पत्र लेखकों में शामिल नहीं हैं) शिकायत करते हैं कि राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर पार्टी का रुख तय करने के लिए कांग्रेस के मंचों पर कोई नियमित चर्चा नहीं होती. असल में, कुछ हल्कों का कहना है कि सामूहिक नेतृत्व का विचार राहुल की एकतरफा कार्रवाइयों का मुकाबला करने के लिए रखा गया. पत्र में कहा गया कि कार्यसमिति की बैठकें इन दिनों किसी विशेष विषय पर केंद्रित होती हैं. संसदीय बोर्ड को फिर से जिलाने की मांग की गई, जिसे 1993 में तब के कांग्रेस अध्यक्ष और प्रधानंत्री पी.वी. नरसिंह राव ने भंग कर दिया था.

धीरे-धीरे इस तरह दरकिनार कर दिए जाने से न केवल कुछ नेताओं में बेचैनी पैदा हुई, बल्कि इसने पार्टी के भविष्य को लेकर कार्यकर्ताओं को भी चिंतित कर दिया. राहुल कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर न लौटने को अड़े हैं, वहीं इस पद पर बने रहने की सोनिया की अनिच्छा और उनकी सेहत ने अनिश्चितता बढ़ा दी है. थरूर, तिवारी और देवड़ा सरीखे नेताओं ने पहले भी गैर-गांधी अध्यक्ष चुनने की हिमायत की थी, लेकिन ज्यादातर लोग इस विचार से उत्साहित नहीं दिखे. इन हालात में आम भावना यह है कि एक के बाद एक दो लोकसभा चुनावों में अपमानजनक हार और राज्यों में सिलेसिलेवार पराजयों के बाद कामकाज के मौजूदा रवैए और रफ्तार से पार्टी नहीं चल सकती.

यही वजह है कि 7 अगस्त की चिट्ठी की गूंज अलग-अलग उम्र, भूगोल, पद और वफादारी वाले भिन्न-भिन्न नेताओं के समूह में सुनाई दी और उन्हें एक साथ ले आई. आनंद शर्मा ने ट्वीट किया, ''भाजपा से मुकाबला करने के लिए भारत को मजबूत विपक्ष की जरूरत है. पार्टी को नई ऊर्जा देने के सुझाव ईमानदारी से दिए गए हैं और मतभेद नहीं हैं. उम्मीद है सभी साथियों ने इसे पढ़ा होगा.'' चिट्ठी में उठाए गए मुद्दों पर कार्यसमिति की बैठक में कोई चर्चा नहीं हुई और बड़ी तादाद में पार्टी नेताओं ने इन मुद्दों से सहमत होने के बावजूद पत्र लेखकों को अपना गिरता राजनैतिक करियर बचाने की कोशिश कर रहे दुस्साहसी नेताओं के समूह के तौर पर खारिज कर दिया. कार्यसमिति के एक सदस्य ने *इंडिया टुडे* से कहा, ''पत्र लेखकों में तीन किस्म के नेता हैं. पहली किस्म के नेताओं के खिलाफ विभिन्न मामले चल रहे हैं; दूसरे असंतुष्ट नेता हैं क्योंकि उन्हें कुछ खास पद नहीं मिले या उन्हें खोने का डर है; तीसरे वे नेता हैं जो खुद को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर देखते हैं.''

इस किस्म की अपमानजनक बातों के बावजूद पत्र लेखक दावा करते हैं कि उन्होंने देश भर से 303 कांग्रेस सदस्यों के दस्तखत जुटा लिए थे. कइयों ने नैतिक समर्थन दिया, हालांकि वे खुलकर सामने आने को तैयार न थे. नैतिक समर्थन मिले या न मिले, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उन्होंने पार्टी के ढांचे से जुड़े बेहद अहम मुद्दे उठा दिए हैं. एक पूर्व कांग्रेस मुख्यमंत्री कहते हैं, ''फिलहाल तनाव भले शांत हो गया हो, पर अगर ठोस कदम नहीं उठाए जाते हैं और बदलाव दिखाई नहीं देता है तो असंतुष्टों की तादाद बढ़ेगी. इससे ज्यादा अहम यह कि पार्टी मटियामेट भी हो सकती है.'' परिवार के वफादार भरोसा दिलाते हैं कि 'जल्द कदम उठाए जाएंगे'. यह तो पहले भी सब सुन चुके हैं. ■

पर कार्यसमिति ने किया क्या?

चिट्ठी में उठाए गए मुद्दों पर कहीं कोई बात ही नहीं हुई. इसके बजाए चिट्ठी लिखे जाने के पीछे के मंतव्य और समय को लेकर सवाल उठाए गए. बैठक के अंत में कार्यसमिति ने किया यहः

- ''अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का अधिवेशन बुलाने लायक समय और परिस्थिति न बन पाने तक'' सोनिया गांधी से अध्यक्ष पद पर बने रहने की विनती
- सोनिया और राहुल गांधी के हाथ हर संभव ढंग से मजबूत करने का संकल्प लिया
- सोनिया को इस बात के लिए अधिकृत किया कि वे संगठन में जिस तरह का बदलाव जरूरी समझें, उसे अंजाम दें

मंदी का वायरस

कोविड संक्रमण के प्रकोप से बुरी तरह पस्त देश की अर्थव्यवस्था **मंदी की ओर लुढ़कती जा रही है.** उसे गर्त से निकालने के लिए सरकार को फौरन उठाने होंगे कुछ बड़े ही साहसिक कदम

एम.जी. अरुण और **श्वेता सिंह**, साथ में **अनिलेश एस. महाजन**
इलस्ट्रेशनः **नीलांजन दास**

ग

वी मुंबई के पनवेल में अपनी छोटी-सी कपड़े की दुकान में बैठे 48 वर्षीय महादेव कदम पथराई आंखों से अगस्त महीने की एक सुबह बरसते आसमान को देख रहे हैं कि एक दिन और ग्राहकों को ताकते बीतेगा या फिर एकाध ग्राहकों से ही संतोष करना पड़ेगा. वे बताते हैं कि मार्च के आखिरी हफ्ते से जून के अंत तक केंद्र सरकार और स्थानीय प्रशासन के लॉकडाउन की वजह से कोई बिक्री नहीं हुई. जून के आखिर में दुकान खुलने पर शुरू में थोड़ा-बहुत काम चला भी तो जल्दी ही खत्म हो गया.

स्थानीय अधिकारियों के निर्देश के मुताबिक, ग्राहकों को अंदर जाने से रोकने के लिए दुकान के दरवाजे पर बंधी रस्सी के उस पार एक कुर्सी में धंसे-से वे कहते हैं कि अपने तीन दशकों के कारोबारी जीवन में उन्होंने ऐसा बदतर वक्त नहीं देखा. वे कहते हैं, ''नया माल भरने की बात ही कहां है? अभी नए साल पर लाया माल ही नहीं बिक पाया है. गणेश उत्सव (जो 22 अगस्त को शुरू हुआ) में भी कोई फर्क नहीं पड़ा.'' उन्हें हर महीने 8,000 रु. दुकान का किराया चुकाना है और एक पर्सनल लोन की किस्त का मोरेटोरियम भी अगस्त में खत्म हो रहा है. इस तरह उनके आगे अनिश्चित भविष्य ठाठें मार रहा है.

कोविड-19 महामारी, सख्त लॉकडाउन और मांग टूटने से देश भर में छोटे-बड़े करोड़ों कारोबार तबाह हो गए हैं और कदम जैसे अनेक लोगों को दिवालिया होने की कगार पर धकेल गए हैं. सबसे बुरा हाल तो सेवा क्षेत्र, खासकर खुदरा व्यापार, होटल-रेस्तरां और आवाजाही क्षेत्र का है. अनेक एमएसएमई (लघु, छोटे और मझोले उद्यम) तो वजूद बचाने के लिए ही जूझ रहे हैं या क्षमता से काफी कम काम कर पा रहे हैं. कुछ तो अपना काम ही बदलने पर मजबूर हो गए हैं. मसलन, इंजीनियरिंग उत्पाद या रासायनिक सामान के बदले हैंड सैनिटाइजर, साबुन, निजी सुरक्षा उपकरण और भारी मांग वाले मास्क बनाने लगे हैं लेकिन पहले से कमाई काफी घट गई है. बड़े कारोबारी भी अपनी इकाइयां काफी कम क्षमता पर चला रहे हैं और थोड़े-से स्टाफ से काम लेकर बाकी की छंटनी कर रहे हैं. ये हालात चारों ओर अब दिखने भी लगे हैं. सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआइई) का कहना है कि लॉकडाउन शुरू होने के बाद से 1.89 करोड़ वेतनभोगी लोग नौकरी गंवा चुके हैं, करीब 50 लाख नौकरियां तो जुलाई में ही खत्म हो गईं. नतीजतन, मांग टूटी और कमजोर मांग से निवेश भी गिर गया. कारोबारी बैंक से कम कर्ज उठा रहे हैं क्योंकि निवेश रोक दिया गया है. बैंकिंग क्षेत्र सरकारी अनुमान के मुताबिक, पहले ही 7.27 लाख करोड़ रु. के डूबत कर्ज के बोझ तले दबा है, आने वाले महीनों में डूबत कर्ज (एनपीए) के और बढ़ने का अंदेशा है क्योंकि महामारी के चलते कारोबारी तबाही की वजह से कर्ज की किस्तें न चुका पाने की आशंका भी बढ़ रही है.

कड़वी हकीकत

कई एजेंसियां जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान लगा रही है और सबमें यह साझा है कि गिरावट बड़ी है. इस पर आम राय-सी लगती है कि देश की अर्थव्यवस्था मौजूदा वित्त वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही में 13 फीसद से 23 फीसद तक सिकुड़ गई है. बदतर तो यह है कि जानकार पूरे वित्त वर्ष में नकारात्मक वृद्धि का अनुमान लगा रहे हैं, कुछ का अनुमान है कि 3.2 फीसद से 9.5 फीसद तक वृद्धि सिकुड़ सकती है. मसलन, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का अनुमान है कि भारतीय अर्थव्यवस्था इस वित्त वर्ष में 4.5 फीसद तक सिकुड़ जाएगी.

कड़वी हकीकत यह है कि देश 1979-80 के बाद पहली दफा मंदी की गिरफ्त में है. तब अर्थव्यवस्था 5.8 फीसद सिकुड़ गई थी (उस वक्त कृषि पर निर्भरता भारी थी और दो साल लगातार मॉनसून खराब रहा था). अमेरिका स्थित थिंक टैंक नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च के मुताबिक, मंदी वह है जब 'अर्थव्यवस्था में चौतरफा आर्थिक गतिविधियों में काफी गिरावट कुछ महीनों से ज्यादा जारी रहे, अमूमन वास्तविक जीडीपी, वास्तविक आमदनी, रोजगार, औद्योगिक उत्पादन और थोक-खुदरा बिक्री में गिरावट दर्ज हो.' 6 अगस्त को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि देश की जीडीपी वृद्धि पहली छमाही में ''सिकुड़ने के दायरे में रह सकती है,'' और वास्तविक जीडीपी वृद्धि वित्त वर्ष 2021 में नकारात्मक रहने का अनुमान है. पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग कहते हैं, ''दो तिमाहियों में नकारात्मक वृद्धि का मतलब मंदी होता है, और जून तथा सितंबर की तिमाही में तो शर्तिया नकारात्मक वृद्धि रही है.'' उनका अनुमान है कि देश में आर्थिक उत्पादन जून में खत्म हुई तिमाही में 25 फीसद गिर गया. वे कहते हैं, ''यह गिरावट भारी है लेकिन अप्रत्याशित नहीं,'' इसी अवधि

-4.5

फीसद

सिकुड़ जाएगी अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2020-21 में, आइएमएफ का अनुमान

ग्राफिकः तन्मय चक्रवर्ती

कगार पर लटकी

रोजगार और जीडीपी वृद्धि दर से लेकर घरेलू खपत तक सभी प्रमुख आर्थिक सूचकांकों से बेइंतहा खस्ताहाली के ही संकेत

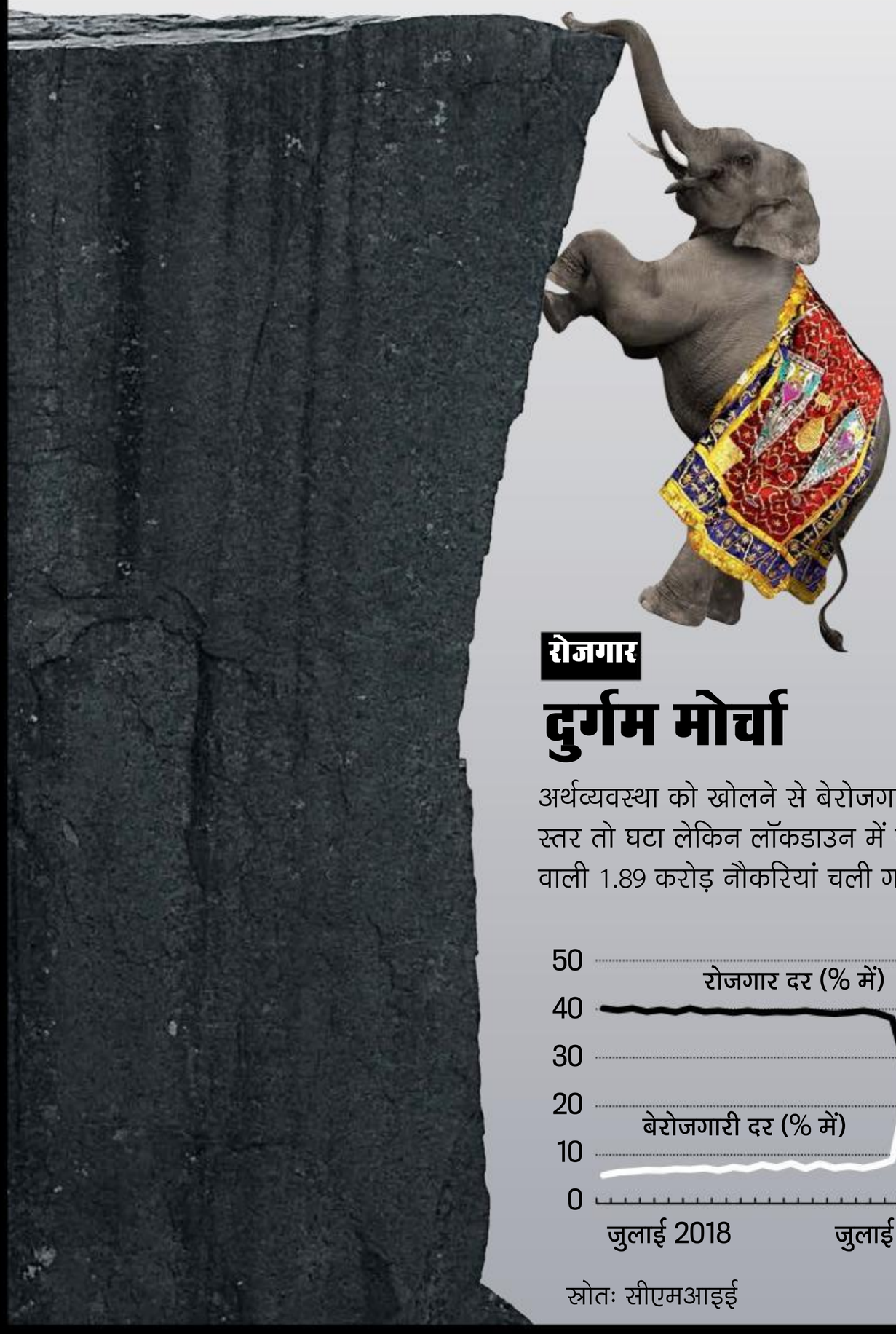

रोजगार

दुर्गम मोर्चा

अर्थव्यवस्था को खोलने से बेरोजगारी का स्तर तो घटा लेकिन लॉकडाउन में वेतन वाली 1.89 करोड़ नौकरियां चली गईं

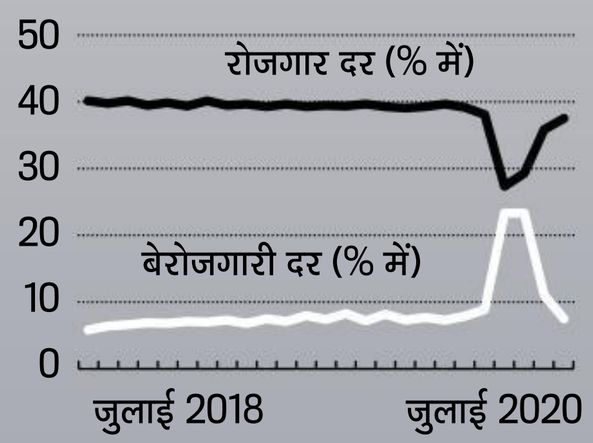

स्रोतः सीएमआइई

जीडीपी

लगातार गिरावट

लॉकडाउन से काफी पहले ही दिसंबर 2019 तक लगातार तीन तिमाहियों में जीडीपी में गिरावट दर्ज हुई, कोविड ने इसे कोढ़ में खाज बना दिया

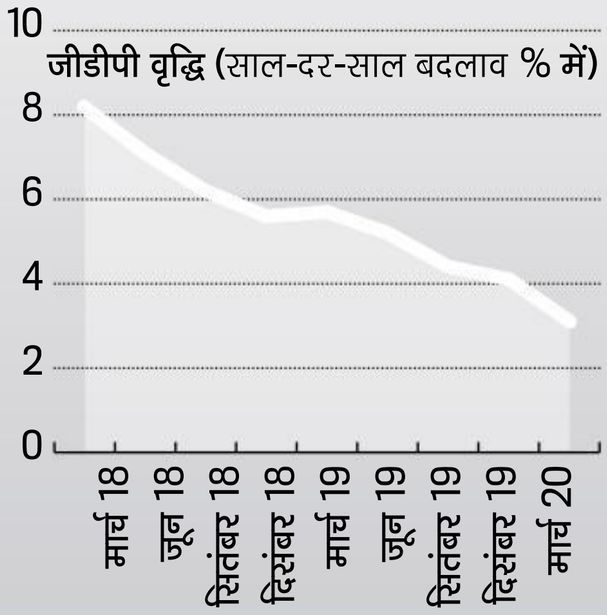

खपत

मांग ही नहीं

रोजगार के मोर्चे पर अनिश्चितता से मांग में भारी गिरावट आ गई है

निजी अंतिम खपत व्यय
(साल-दर-साल बदलाव % में)

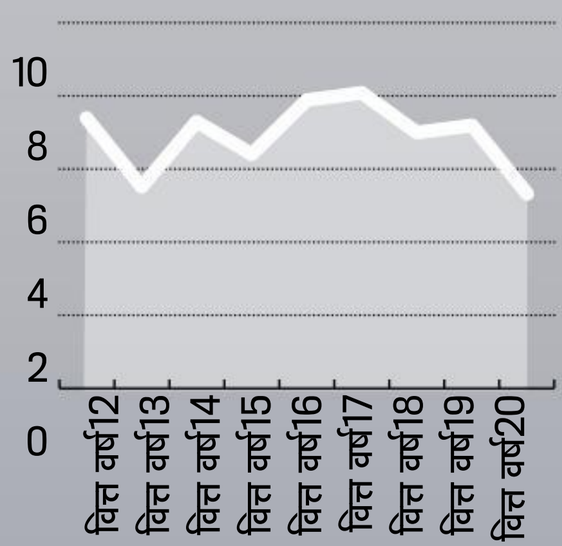

(नोटः निजी अंतिम खर्च सामान और सेवाओं के मद में निजी जरूरत का खर्च है)

''निवेश बढ़ाना होगा (आर्थिक बहाली के लिए). ऐसा नहीं हुआ तो तय मानिए कि हम 4.2 फीसद वृद्धि दर से गिरकर इस वर्ष शून्य से भी नीचे -7 या -8 फीसद की दर पर पहुंच जाएंगे''

कौशिक बसु
पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री, विश्व बैंक

में अमेरिका में आर्थिक उत्पादन 30 फीसद और ब्रिटेन में करीब 26 फीसद गिरा. जो भी हो, भारत में वृद्धि के चारों प्रमुख इंजन—घरेलू खपत, निजी निवेश, सरकारी खर्च और निर्यात—बैठते जा रहे हैं.

कोविड की कीमत

कोविड लॉकडाउन की वजह से कारोबारों के बंद होने, नौकरियां खत्म होने और तनख्वाह में कटौती ने मांग पर बुरा असर डाला है—कम आमदनी से स्वाभविक तौर पर खर्च कम हो गए हैं. 25 अगस्त को जारी अपनी सालाना रिपोर्ट में, रिजर्व बैंक ने कहा है कि 'लॉकडाउन के बाद मई और जून में (उपभोग के मामले में) ऊपर जा रहा ग्राफ जुलाई और अगस्त में आकर धीमा हो गया, उसकी मुख्य वजह

लॉकाडाउन का दोबारा लगाना या उसे कड़ाई से लागू करना रहा है.' इससे पता चला कि खपत पर लगा झटका गंभीर है और इसके मायने यह हैं कि 'आर्थिक गतिविधियों में सिकुड़न दूसरी तिमाही में भी जारी रहेगी', यह भी गौरतलब है कि जुलाई में उपभोक्ताओं का भरोसा अब तक के लिहाज से सबसे अधिक टूटा, हाल के एक सर्वेक्षण में अधिकतर लोगों में सामान्य आर्थिक परिस्थितियों, रोजगार, महंगाई और आमदनी के प्रति गहरी हताशा है. यह उपभोग के आंकड़ों में भी दिखता है—सामान और सेवाओं की मांग में अब तक की सबसे अधिक कमी देखी जा रही है. मसलन, रियल एस्टेट सेक्टर में अनबिकी जायदाद भरी पड़ी है. इस साल मार्च के आखिर में आठ बड़े शहरों में 4,55,351 घर अनबिके पड़े हैं, जिनकी कीमत 3.7 लाख करोड़ रु. है. इसी तरह, वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में यात्री वाहनों और शहरी क्षेत्रों में उपभोक्ता सामान की बिक्री पिछले साल की तुलना में क्रमशः पांचवां हिस्सा और एक-तिहाई ही रह गई है.

खपत कम होने से निजी निवेश भी गिर गया है—अपने उत्पादों के लिए बाजार के बगैर, कंपनियों में नई परियोजनाओं पर खर्च करने का बिल्कुल उत्साह नहीं है. सीएमआइई के मुताबिक, नई निवेश परियोजनाओं की वार्षिक वृद्धि दर 2019-20 में महज 1.85 फीसद रह गई है. ठीक पांच साल पहले, यह आंकड़ा 103 फीसद था. मंदी का नतीजा यह भी है कि कंपनियों ने अपनी तिजोरी बंद कर दी है और उधारी कम कर दी है. भारतीय उद्योगों की फंड उगाही कैलेंडर वर्ष 2020 की पहली तिमाही में 78 फीसद कम हो गई है, क्योंकि कंपनियां अपने खर्चे का काम फंड उगाही की बजाए मौजूदा नकद प्रवाह से ही चलाना चाह रही हैं. कई निजी इक्विटी फंड में 'ड्राइ पाउडर' (उगाही जा चुकी रकम) की मात्रा बढ़ गई हैं क्योंकि उन्हें निवेश के रास्ते नहीं मिल रहे. इसका दूसरा पहलू यह है कि बैंक, खासकर सार्वजनिक बैंक, हालिया अतीत में बड़े नुक्सान झेलने के बाद कर्ज देने को लेकर एहतियात बरत रहे हैं. क्रिसिल के अनुमान के मुताबिक, इस वित्त वर्ष में बैंक क्रेडिट वृद्धि दर कई दशकों के सबसे निचले स्तर 0.1 फीसद पर गोता लगा सकती है.

हालांकि, शेयर बाजार का रुख एकदम उलट है. अप्रैल-जून की तिमाही में बाजार में करीब 20 फीसद की बढ़त दर्ज की गई—पिछले 11 साल में यह सबसे अधिक तिमाही वृद्धि है—और इससे महामारी के दौर के शुरुआती दिनों के नुक्सान की भरपाई हो गई. 26 अगस्त को बीएसई सेंसेक्स 230 अंक की बढ़त के साथ 39,073.92 पर बंद हुआ. विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों की आमद के मामले में भारत ने अन्य उभरते बाजारों को पीछे छोड़ दिया है—अगस्त, 2020 में अब तक करीब 6 अरब डॉलर की आमद हुई है. विशेषज्ञों का कहना है कि लॉकडाउन के शुरुआती झटके से परेशान होने के बाद शेयर बाजार देश के दीर्घकालिक विकास की कहानी पर लौट रहा है, और इसकी क्षमता लॉकडाउन के पहले के अपने 42,000 के अंक को वापस पा लेने की है.

कई लोगों ने निजी निवेश खासकर इन्फ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में आई गिरावट की भरपाई सरकारी खर्चों के जरिए होने की उम्मीद जताई थी. उन्हें उम्मीद थी कि इससे रोजगार पैदा होंगे और सीमेंट और स्टील वगैरह की मांग बढ़ेगी. पिछले साल दिसंबर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अगले पांच साल के लिए 102 लाख करोड़ रु. की इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की घोषणा की थी. ये परियोजनाएं बिजली, रेलवे, शहरी सिंचाई, परिवहन, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों की हैं. इस साल अप्रैल में सरकार ने अगले दो साल में 15 लाख करोड़ रु. की लागत से सड़कों के निर्माण का लक्ष्य भी तय किया. इन घोषणाओं के बावजूद बहुत थोड़ा ही जमीन पर उतर पाया. मसलन, सरकारी आंकड़े ही बताते हैं कि सड़क निर्माण पर खर्च 2018-19 में 1.37 लाख करोड़ रु. से घटकर 2019-20 में (नवंबर, 2019 तक) 85,275 करोड़ रु. रह गया है. यही नहीं, सड़क निर्माण भी 2018-19 में 10,855 किमी प्रति वर्ष से घटकर 2019-20 में (दिसंबर, 2019 तक) 6,940 किमी रह गया. उम्मीद थी कि राज्य सरकारें 2025 तक नेशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के मद में 111 लाख करोड़ रु. का कम से कम 40 फीसद खर्च करेंगी, पर उन्होंने भी अचानक पूंजीगत खर्चों को 2019-20 में घटा दिया. केयर रेटिंग्स के मुख्य अर्थशास्त्री मदन सबनवीस कहते हैं, ''सार्वजनिक निवेश में राज्यों का हिस्सा दो-तिहाई है, लेकिन वे अभी स्वास्थ्य को छोड़कर किसी भी क्षेत्र में अधिक खर्च करने की स्थिति में नहीं हैं.''

यहां तक कि निर्यात में भी संकट है जो जुलाई में लगातार पांचवें महीने घटता हुआ दर्ज किया गया है. पेट्रोलियम, रत्नों और आभूषण, चमड़े और चमड़े के उत्पादों और इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे क्षेत्रों में कमी की वजह से वार्षिक आधार पर निर्यात में 10.21 फीसद की कमी आई है. उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, जुलाई

सब धीमा-धीमा

उत्पादन क्षेत्र के सामान और कुल औद्योगिक उत्पादन सहित सभी तरह के उत्पादन के आंकड़े सामान्य से काफी कम हैं और महंगाई बढ़ रही है

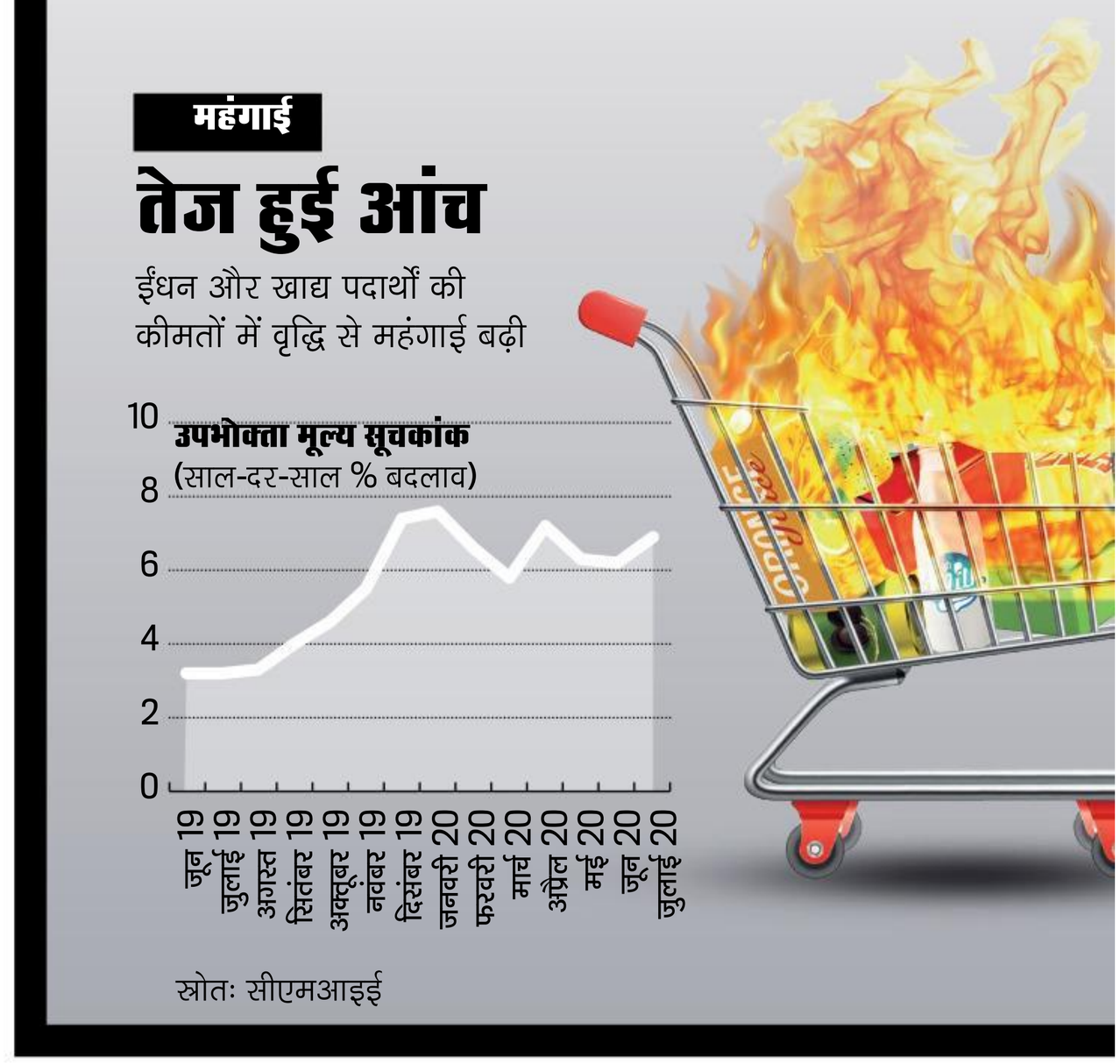

महंगाई

तेज हुई आंच

ईंधन और खाद्य पदार्थों की कीमतों में वृद्धि से महंगाई बढ़ी

स्रोतः सीएमआइई

आइआइपी

गहरा संकट

औद्योगिक उत्पादन लॉकडाउन और कमजोर मांग से बुरी तरह प्रभावित हुआ

(आइआइपीः औद्योगिक उत्पादन सूचकांक)

नोटः एनएसओ ने एक विज्ञप्ति में कहा है कि अप्रैल और मई 2020 के आइआइपी की तुलना उससे पहले के महीनों के सूचकांकों से करना ठीक न होगा. यहां वृद्धि दरों की गणना सूचकांक के आंकड़ों से सीएमआइई ने की है

पीएमआइ

सब कुछ धराशाई

सेवा क्षेत्र में गिरावट उत्पादन क्षेत्र से कहीं बड़े पैमाने पर है

(पीएमआइः पर्चेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स; स्रोतः आइएसएस मार्किट)

मैन्युफैक्चरिंग

भारी गिरावट

उत्पादन क्षमता के मुकाबले 70 फीसद तक गिराटव आई है, जो 10 साल के औसत से भी कम है

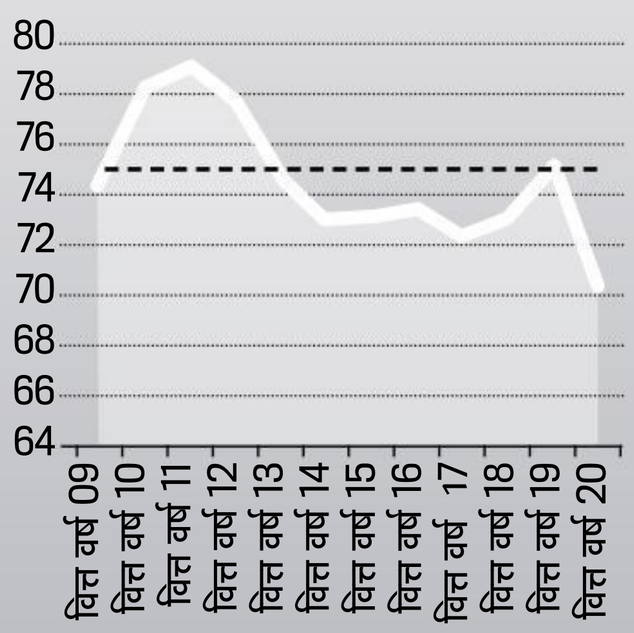

स्रोतः भारतीय रिजर्व बैंक

“आत्मनिर्भर भारत का फोकस एमएसएमई पर है, (जिनमें) सबसे अधिक रोजगार पैदा करने की क्षमता है. उन्हें कर्ज मुहैया कराने से (कोविड का आर्थिक) असर कम हुआ है”

अरविंद सुब्रह्मण्यम
मुख्य आर्थिक सलाहकार, आर्थिक मामले विभाग, वित्त मंत्रालय

2020 में वस्तुगत निर्यात 1.77 लाख करोड़ रु. पर रहा, जो 2019 की जुलाई में 1.81 लाख करोड़ रु. था. यह 2.14 फीसद की नकारात्मक वृद्धि है. अप्रैल-जुलाई की अवधि के लिए, भारत का कुल निर्यात लगभग 141.82 अरब डॉलर होने का अनुमान है, जो पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 21.99 फीसद कम है. कोविड-19 की वजह से वायरस के फैलाव को रोकने के लिए देशों ने परिवहन पर बंदिशें आयद कर दी हैं, ऐसे में वैश्विक व्यापार पर इसका असर अपरिहार्य है. बहरहाल, भारतीय निर्यात संगठनों के परिसंघ के महानिदेशक अजय सहाय कहते हैं कि निर्यात में सुधार आ रहा है—इसके कम आंकड़े इस वजह से दिख रहे हैं क्योंकि निर्यात के सामान अधिकतर कम कीमत वाले कच्चे माल हैं. वे कहते हैं, ‘‘इस वित्त वर्ष की शुरुआत परिधान निर्यात में 65 फीसद की कमी के साथ हुई थी, जिसमें जून में आकर सुधार हुआ और वह 12 फीसद हो गया है.’’ फार्मा और तकनीकी वस्त्रों के लिए, बाजार बहुत अच्छा है और भारत अधिक से अधिक हिस्सेदारी पर कब्जा कर रहा है. वे कहते हैं, ‘‘खाद्य पदार्थों के मामले में भी चीन को काफी झटका लगा है और यह भारत के हित में है.’’ परिधानों, फुटवियर, रत्नों और आभूषण और हस्तशिल्प के निर्यात के साथ समस्या पर वे बताते हैं कि कम अवधि के लिए ऑर्डर आ रहे हैं. वे कहते हैं, ‘‘इस समय तक सामान्य तौर पर हमें अगले साल के फरवरी-मार्च तक के ऑर्डर हासिल हो जाते थे, पर अभी हमें क्रिसमस पूर्व के समय के ऑर्डर ही मिल रहे हैं. खरीदार लंबे समय के फैसले नहीं ले रहे क्योंकि वे बाजार को लेकर अनिश्चित हैं.’’

इन सबके बीच, भारत को वास्तविक नियंत्रण रेखा के पार से चीनी घुसपैठ का भी सामना करना पड़ रहा है और इससे दोनों देशों के बीच कई हफ्तों तक तनाव जारी रहा और दोनों ओर के फौजी मारे गए. इस तनाव की वजह से लोगों ने चीनी सामान का बहिष्कार करने की मांग की और नतीजतन, भारत ने 59 चीनी ऐप को प्रतिबंधित कर दिया और उस देश से निवेश के प्रवाह पर बंदिशें लगा दीं. साथ ही, सरकार का आत्मनिर्भर अभियान कई क्षेत्रों में घरेलू क्षमताओं के निर्माण पर केंद्रित है, जिसका

खास मकसद चीनी कंपनियों और उत्पादों को बाहर रखना है.

अर्थव्यवस्था के प्रमुख स्तंभों के डगमगाने के साथ ही इस वित्त वर्ष की शेष तिमाहियों के लिए आर्थिक परिदृश्य पर अंदेशों के बादल छाए हैं. संकट से पार पाने के लिए कंपनियों ने अपनी पेटी कस रखी है, ऐसे में नौकरियों का बाजार भी ढीला ही रहेगा. असंगठित क्षेत्र और एमएसएमई पर इसका सबसे बुरा असर पड़ेगा. इस बीच खाद्य पदार्थों और ईंधन की कीमतों में वृद्धि से महंगाई में बढ़ोतरी मध्य वर्ग के बजट को जोर का झटका दे रही है और नीति-निर्माताओं की एड़ियों से पसीना आ रहा है.

आगे क्या

महामारी ने कारोबारों के बंद होने, नौकरियों के जाने और तनख्वाहों में कटौती के नतीजतन आर्थिक वृद्धि के चार इंजनों को यह जो नुक्सान पहुंचाया है, संभावना यही है कि इसकी वजह से उन्हीं चार मोर्चों पर अभी और भी बुरी खबरें सुनने को मिलेंगी.

मसलन, नौकरियों के जाने को ही लीजिए. कुछ कारोबार खासकर ट्रैवल, विमानन और हॉस्पिटैलिटी में काम कर रही सेवा क्षेत्र की फर्मों पर, वैश्विक और घरेलू लॉकडाउन की विशेष रूप से जबरदस्त मार पड़ी है. बाजार हिस्सेदारी के लिहाज से भारत की सबसे बड़ी विमान कंपनी इंडिगो अपना 10 फीसद स्टाफ या करीब 2,300 लोगों की छंटनी कर चुकी है. यह रुझान तब तक चलता रहेगा जब तक महामारी और लॉकडाउन बने रहते हैं. क्रिसिल की एक रिपोर्ट कहती है कि भारत के हवाई यात्रियों के यातायात में इस वित्त वर्ष में जबरदस्त गिरावट आने का अंदेशा है—घरेलू यात्राओं में 40-50 फीसद और अंतरराष्ट्रीय यात्राओं में 60-65 फीसद. इसी तरह, केयर रेटिंग्ज के अनुमान के मुताबिक, हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र 2019-20 में करीब 1.25 लाख करोड़ रु. का राजस्व गंवा चुका है. यह इशारा करता है कि अभी और नौकरियां जा सकती हैं, जिसका और भी बदतर असर आर्थिक वृद्धि पर पड़ेगा. मैन्युफैक्चरिंग एक और क्षेत्र है जो इस दुष्चक्र में फंस गया है. एमएसएमई, जिसमें करीब 12 करोड़ लोग काम करते हैं और जो भारत के निर्यात में 45 फीसद का योगदान देता है, खास तौर पर कमजोर है. ऑटोमोटिव क्षेत्र भी इसी से मिलते-जुलते संकट की स्थिति में है. करीब 4.4 करोड़ लोगों को रोजगार और देश की जीडीपी में 9.4 फीसद का योगदान देने वाले इस क्षेत्र में इस साल जून में कुल बिक्री घटकर आधी रह गई, जिससे वेतन और अनुबंध पर काम करने वालों की नौकरियां जोखिम में पड़ गई हैं.

'फोर्ब्स मार्शल' के को-चेयरमैन और भारतीय उद्योग परिसंघ के पूर्व अध्यक्ष नौशाद फोर्ब्स कहते हैं, ''मासिक वेतन वाली नौकरियों में जो हो रहा है, वह बेहद चिंताजनक है.'' वे कहते हैं कि तमाम उद्योगों की फर्मों को इस तूफान में टिके रहने के लिए सरकारी सहायता की जरूरत है, जो वैसी ही कर्ज की गारंटियों की शक्ल में हो सकती है जो एमएसएमई क्षेत्र को दी गई हैं. नौकरियों की फिसलन को रोकना बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि इससे खर्च में और भी ज्यादा गिरावट का सिलसिला शुरू होगा, जिससे फिर और नौकरियां जाएंगी और इस तरह यह दुष्चक्र चलता रहेगा.

अलबत्ता मई में सरकार ने जिन प्रोत्साहन उपायों का ऐलान किया था, उनका वांछित असर दिखाई नहीं देता. 20 लाख करोड़ रु. के पैकेज में मोटे तौर पर बैंकों में नकदी बढ़ाने पर जोर दिया गया था ताकि एमएसएमई को कर्ज की उपलब्धता और बढ़े और किसानों तथा आर्थिक पिरामिड के सबसे निचले हिस्से के लोगों को आमदनी में सहारा मिले. इस पैकेज

उम्मीद के कुछ दीए

चौतरफा अंधियारे में विदेशी निवेश और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में हल्की रोशनी

एफपीआइ

बड़ा दांव

शुरुआती बिकवाली के बाद विदेशी निवेशकों की शेयर बाजार में वापसी अर्थव्यवस्था की दीर्घावधिक संभावनाओं का संकेत

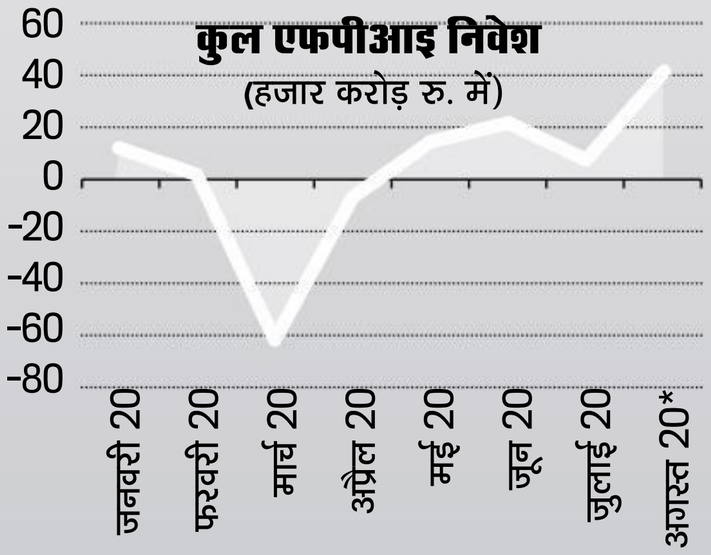

नोटः इक्विटी में; *25 अगस्त 2020 तक; एफपीआइः विदेशी पोर्टफोलियो निवेश, विदेश से शेयर बाजार में निवेश का तरीका; *स्रोतः एनएसडीएल*

ग्रामीण मजदूरी

आशा की किरण

रबी फसल अच्छी होने से ग्रामीण मजदूरी स्थिर बनी हुई है

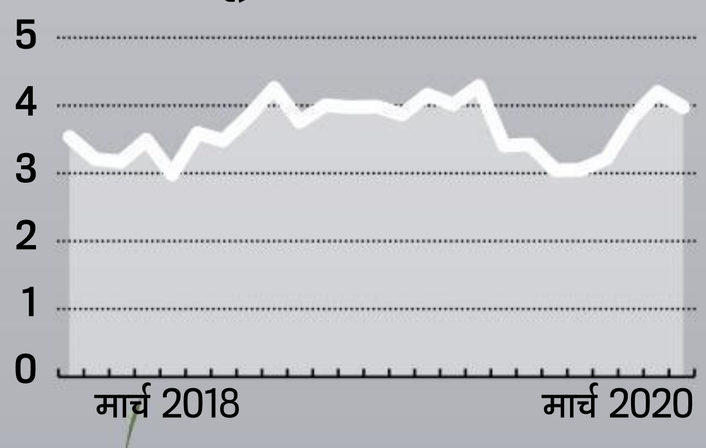

स्रोतः सीएमआइई

से उम्मीद में शुरुआती उछाल आया था, लेकिन अब लगता है कि यह अर्थव्यवस्था की तकलीफों से निबटने के लिए अत्यंत नाकाफी है. हालांकि छोटी फर्मों के कारोबार की संभावनाओं में सुधार के लिए कई उपाय किए गए थे. मसलन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर ऐसी फर्मों को देय राशि तेजी से चुकाने के लिए जोर डाला गया था, जबकि बैंकों से कहा गया था कि वे कर्ज चुकाने पर छह महीने के लिए मोरेटोरियम लागू करें और वृद्धि को प्रोत्साहन देने के लिए एमएसएमई से जुड़े नियम-कायदों को नए सिरे से तय करें. महीनों बाद ज्यादातर छोटे कारोबार अब भी अपने वजूद के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं. लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आर.के. भारद्वाज कहते हैं कि असल समस्या यह है कि खपत पूरी तरह चौपट हो गई है. वे कहते हैं, ''मांग में अनिश्चितता है, जो हमें सबसे ज्यादा चोट पहुंचा रही है.'' हालांकि दूसरी कारोबारी परेशानियों में कमी आई हैं. मसलन, कामगारों की कमी हो गई थी, क्योंकि प्रवासी कामगार लॉकडाउन की वजह से अपने गृह राज्य से अपने रोजगार के शहर तक आ-जा नहीं पा रहे थे. लेकिन मांग में इस गिरावट का मतलब है कि कारोबार उतना नहीं कमा सकते जितना वे कमाया करते थे. कर्ज पर मोरेटोरियम, पीएसयू से बकाया रकमों का मिलना और कर्ज आसानी से मुहैया होना मांग में गिरावट सरीखी बुनियादी परेशानी की भरपाई नहीं कर सकता.

मसलन, लुधियाना के निटवियर क्लब के चेयरमैन विनोद थापर कहते हैं कि खुदरा दुकानों के लगातार बंद रहने से मांग को धक्का पहुंचा है और इसने फैक्ट्रियों को महज 30-35 फीसद क्षमता पर चलने को मजबूर कर दिया है. (लुधियाना ऊंची कीमत वाले परिधानों की मैन्युफैक्चरिंग का केंद्र है.) इस बीच पीएसयू को आपूर्ति करने वाले एमएसएमई का कहना है कि इन उद्यमों ने मोटे तौर पर लंबित भुगतान जारी करना शुरू कर दिया है, लेकिन नए ऑर्डर नदारद हैं. यहां तक कि कुछ क्षेत्रों में अच्छे बदलाव भी चेतावनी के साथ आए हैं. मसलन, निर्यातकों का कहना है कि कपड़ों, ऑटोमोबाइल कलपुर्जों, खेल के साजो-सामान और हाथ के औजारों में मांग कुछ हद तक लौटी है, लेकिन तब भी मांग कोविड से पहले के स्तर से कम ही है.

उम्मीद की अकेली किरण ग्रामीण अर्थव्यवस्था मालूम देती है. भाजपा के लोकसभा सांसद और वित्तीय मामलों की स्थायी समिति के अध्यक्ष जयंत सिन्हा कहते हैं, ''भारत की 60-70 फीसद आबादी को सहारा और जीडीपी में 46 फीसद का योगदान देने वाली ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उछाल आ रहा है. तकरीबन 10 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के जरिए आमदनी में सहायता के तौर पर 40,000 करोड़ रु. मिले हैं.'' यहां उम्मीद की कुछ वजहें हैं. जुलाई में खरीफ की बुआई में हुई मजबूत प्रगति के दम पर ट्रैक्टर की बिक्री में 38.5 फीसद की बढ़ोतरी हुई, वहीं इसी महीने में मोटर साइकिलों की बिक्री में आ रही गिरावट कुछ थमी और जून की 35.2 फीसद से घटकर जुलाई में 4.9 फीसद रह गई. गैर-टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु बाजार में भी तेजी आई है. हालांकि यहां बड़ी चेतावनियां भी हैं. विशेषज्ञ बताते हैं कि ग्रामीण मांग देश की जीडीपी में महज 15 फीसद का योगदान देती है और यह क्षेत्र इतना बड़ा नहीं है कि अपने दम पर समग्र अर्थव्यवस्था को जिला दे. साथ ही, रिजर्व बैंक के मुताबिक, ''ग्रामीण मांग की और ज्यादा बहाली तनख्वाहों में मंद वृद्धि ने रोक रखी है, जो अब भी प्रवासी संकट और उससे जुड़े रोजगार के नुक्सानों की बंधक है.''

महंगाई एक और परेशानी है. उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआइ, उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं की एक बास्केट की कीमतों का औसत भारांश) पर आधारित महंगाई जुलाई में

कामचलाऊ

दिल्ली के मायापुरी में इस एमएसएमई की तरह अधिकतर में कम स्टाफ और कम क्षमता का काम

राजवंत रावत

धड़ाम

सभी अनुमानों में इस वित्त वर्ष में नकारात्मक वृद्धि के आसार

वित्त वर्ष '21 के लिए जीडीपी वृद्धि दर अनुमान

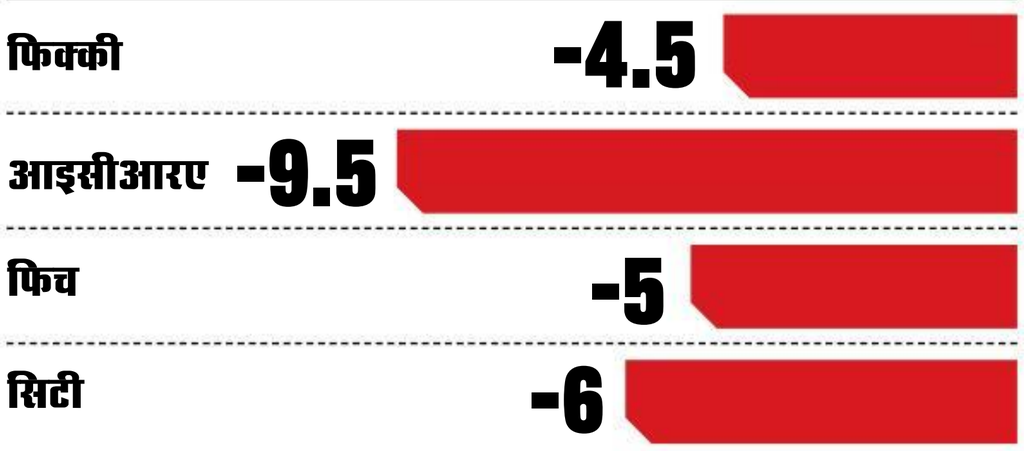

सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 में वित्त वर्ष '21 में वृद्धि दर 6 से 6.5 फीसद का अनुमान लगाया गया था

6.9 फीसद पर पहुंच गई, जो लगातार चौथे महीने रिजर्व बैंक के मुद्रास्फीति के लक्ष्य की ऊपरी सीमा से भी आगे निकल गई है. खपत पर इसके नतीजे होंगे. नौकरियों के नुक्सान और तनख्वाहों में कटौतियों के चलते उपभोक्ताओं के बजट पहले ही सिकुड़ गए हैं. कीमतों में बढ़ोतरी से मांग को और ज्यादा धक्का लगेगा. इस स्थिति में अनूठी बात यह है कि मुद्रास्फीति इसलिए नहीं बढ़ रही है क्योंकि बहुत ज्यादा धन बहुत कम वस्तुओं के पीछे भाग रहा है, बल्कि मांग और आपूर्ति दोनों में भारी जुड़वां गिरावट आई है, जिसके नतीजतन वस्तुओं के दाम बढ़े हैं. इसका एक फौरी नतीजा व्यापक चर्चा में है और वह है नीतिगत ब्याज दरों में रिजर्व बैंक की कटौती के दौर का थम जाना. केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने 6 अगस्त को कोई बदलाव किए बगैर रेपो रेट (वह दर जिस पर व्यावसायिक बैंक रिजर्व बैंक से उधार लेते हैं) को 4 फीसद और रिवर्स रेपो रेट को 3.35 फीसद पर बनाए रखा. इससे महंगाई का दबाव जरूर कुछ कम हो सकता है, लेकिन इसका यह मतलब भी है कि कर्जों का और सस्ता होना रुक जाएगा, जिससे उधारी और निवेश की बढ़ोतरी नरम पड़ जाएगी.

समाधान

समस्या का मर्म बेशक कोविड-19 है. बहाली इस बात पर निर्भर करती है कि वैक्सीन कितनी जल्दी बनाई, बाजार में लाई और सबको मुहैया करवाई जा सकती है.

कई अल्पकालिक समाधान सुझाए जा रहे हैं. दूसरे प्रोत्साहन पैकेज के लिए काफी चीख-पुकार मची है. मसलन, एमएसएमई क्षेत्र जी-जान से अपनी यह मांग मंगवाने में लगा है कि सरकार कर्मचारियों की तनख्वाह चुकाने के लिए राहत पैकेज लाए. अलबत्ता निचले पायदान के लोगों को नकद खैरात पहले ही दी जा चुकी हैं. ऐसे में सरकार कोई और बड़ा वित्तीय कदम उठाने से पहले अर्थव्यवस्था को हुए नुक्सान का आकलन करने के लिए इंतजार करो और देखो का रवैया अपनाती मालूम दे रही है.

इंडिया टुडे ने जिन विशेषज्ञों से बात की, उनमें से कइयों का कहना है कि सरकार को अपने बटुए की डोर ढीली करनी चाहिए. उनका कहना है कि केंद्र सरकार के राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को जीडीपी के मौजूदा तीन फीसद से बढ़ाकर चार फीसद कर देना चाहिए. साथ ही, राज्य सरकारों के कर्ज के लक्ष्य को जीडीपी के मौजूदा 20 फीसद से बढ़ाकर 30 फीसद कर देना चाहिए. इससे सरकार की खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था के चार इंजनों में से एक में सीधे उछाल आएगा. (*देखें क्या भारत उबर सकता है?*). उनका यह भी कहना है कि इन निधियों को गरीब परिवारों को आय सहायता और कमजोर कारोबारों को वित्तीय सहायता देने पर खर्च किया जाना चाहिए. एक और पहलू कामकाजी पूंजी के संकट से निबटना है. अगर बड़ी कंपनियों को कम लागत में कर्ज सुलभ हो, तो वे अपने छोटे सप्लायरों को भुगतान करने की बेहतर स्थिति में होंगी.

अन्य विशेषज्ञ मांग बढ़ाने के लिए हस्तक्षेपों की वकालत करते हैं. प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण और कर कटौतियां की बदौलत उपभोक्ताओं के हाथ में ज्यादा पैसा होगा, जिससे घरेलू खपत बढ़ेगी. वे सिफारिश करते हैं कि सरकार आय हस्तांतरण, मनरेगा सरीखी योजनाओं, केंद्र की तरफ से राज्य सरकारों को बकाया राजस्व देने में तेजी और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे पर खर्च बढ़ाने के लिए ज्यादा रकम आवंटित करे. दूसरे प्रस्तावों में मुफ्त अनाज वितरण योजना का विस्तार करना शामिल है. वे बिजली वितरण कंपनियों का निजीकरण करने, जमीन अधिग्रहण की अड़चनें हटाकर रेलवे में एफडीआइ को प्रोत्साहन देने, खरीद के नियमों में ढील देने सरीखे मध्यम और लंबे वक्त के ढांचागत हस्तक्षेपों की भी सिफारिश करते हैं.

फोर्ब्स भी इन्हीं बातों के पैरोकार हैं. वे कहते हैं कि ढांचागत सुधार वक्त की जरूरत हैं. इनमें ऊंची ब्याज दरों में कमी

"भारत को संरक्षणवाद के तौर-तरीकों से ऊपर उठने की दरकार है. उसे दक्षिण पूर्व एशिया, यूरोपीय संघ और अमेरिका से व्यापार समझौते करने चाहिए"

नौशाद फोर्ब्स
को-चेयरमैन, फोर्ब्स मार्शल

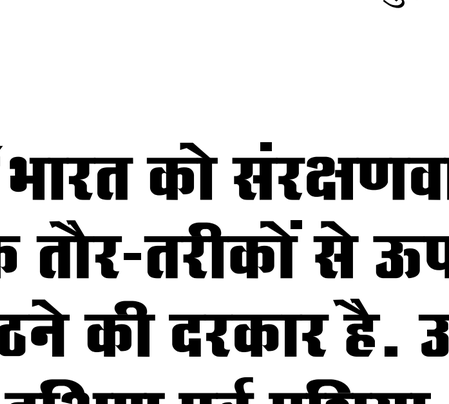

इलाज के नुस्खे

- केंद्र खजाना खोले, राजकोषीय घाटे का लक्ष्य मौजूदा जीडीपी के तीन फीसद से बढ़ाकर चार फीसद करे
- राज्य सरकारों की खर्च करने की क्षमता बढ़ाने के लिए कर्ज-जीडीपी लक्ष्य मौजूदा 20 फीसद से बढ़ाकर 30 फीसद किया जाए
- गरीब परिवारों को आमदनी और कमजोर कारोबारी इकाइयों को वित्तीय मदद मुहैया कराई जाए
- कार्यशील पूंजी के संकट को दूर करें. अगर बड़ी कंपनियों को कम दर में कर्ज उपलब्ध होगा तो वे छोटे आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान करने में सक्षम होंगे
- मांग बढ़ाने में मदद करें. प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण और कर छूट से उपभोक्ताओं के पास पैसा आएगा, जिससे घरेलू मांग में इजाफा होगा
- आमदनी बढ़ाने के उपाय किए जाएं—मनरेगा जैसी योजनाओं में इजाफा करें और केंद्र से राज्यों की देय राशि मुहैया कराने में तेजी लाएं

- सार्वजनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर में सुधार लाएं, इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनियों को दीर्घकालिक कर्ज मुहैया कराने के लिए विशेष एनबीएफसी बनाएं, ताकि इन कंपनियों की समस्याएं दूर की जा सकें
- मध्यम और दीर्घ अवधि के उपायों पर गौर करें. मसलन, बिजली वितरण कंपनियों का निजीकरण करें और भूमि अधिग्रहण तथा खरीद प्रक्रिया को आसान बनाकर रेलवे में एफडीआइ का स्वागत करें
- ऊंची ब्याज दरों को घटाने के लिए वित्तीय क्षेत्र में सुधार करें, भारतीय उत्पादकों को फिलहाल कर्ज पर 12-13 फीसद ब्याज देना पड़ता है, जो सभी उभरती अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ज्यादा है
- एमएसएमई और वेतनभोगी कर्मचारियों पर फोकस करें, 'शहरी मनरेगा' जैसी योजना लाएं, जिसके तहत असंगठित क्षेत्र के छोटी इकाइयों के मजदूरों को सरकार से हर रोज 200 रु. मिले
- जिनकी नौकरियां चली गईं और जिनकी नौकरियां जाने का खतरा है, उन्हें मदद करें. मसलन, कनाडा में 30 फीसद से अधिक आमदनी घटने वाली कंपनियों को सरकार वेतन के मद में सब्सिडी दे रही है
- पेचीदा कानूनों को सरल बनाकर बड़े औद्योगिक क्षेत्र में एफडीआइ आकर्षित करें
- बैंकों के अलावा कॉर्पोरेट बॉन्ड सहित अन्य वित्तीय विकल्प पैदा करें

लाने के लिए वित्तीय क्षेत्र के सुधार भी शामिल हैं. भारतीय उत्पादक फिलहाल कर्ज पर 12–14 फीसद ब्याज अदा करते हैं, जो उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ज्यादा है, यहां तक कि ब्लू चिप कारोबार भी 7–10 फीसद का ब्याज चुका रहे हैं. पूंजी की इतनी ऊंची लागत के चलते निर्यातकों के लिए उन देशों की कंपनियों से प्रतिस्पर्धा कर पाना नामुमकिन हो जाता है जहां पूंजी की लागत इस आंकड़े से आधी से भी कम है.

दूसरे विशेषज्ञ एमएसएमई और वेतनभोगी कर्मचारियों पर लगातार ध्यान देते रहने का सुझाव देते हैं. एक प्रस्ताव 'शहरी मनरेगा' किस्म की एक योजना लाने का है, जिसमें असंगठित क्षेत्र की छोटी फर्मों के कामगारों को सरकार की तरफ से 200 रु. रोज मिले. इसके तीन फायदे होंगे. एक, नौकरियां बची रहेंगी, नियोक्ताओं के वेतन बिल में कमी आएगी और इस योजना के लिए पंजीकरण से असंगठित क्षेत्र के प्रशासनिक डेटाबेस में सुधार आएगा, जिससे अर्थव्यवस्था ज्यादा औपचारिक बनने की तरफ बढ़ेगी. नाम न जाहिर करने की शर्त पर एक नीति निर्माता कहते हैं, ''हमें एमएसएमई को रोजगार समर्थन और राज्यों को और ज्यादा धन देने के लिए अतिरिक्त 3–3.5 लाख करोड़ रु. खर्च करने की जरूरत है. हमें बुनियादी ढांचे पर भी आक्रामक ढंग से खर्च करने की जरूरत है.''

सरकार का ध्यान अभी तक उनको बचाने पर रहा है जो सबसे ज्यादा खतरे में हैं—एमएसएमई और सबसे निचले पायदान के लोग. हालांकि दूसरे भी हैं जिन्हें तत्काल सहायता की जरूरत है. मसलन, जब नौकरियां गंवाने की बात आती है, तो दो विशिष्ट समूहों को मदद की जरूरत है. एक वे जो अपनी नौकरियां पहले ही गंवा चुके हैं और दूसरे वे जिनके सिर पर अपनी नौकरी गंवाने का खतरा मंडरा रहा है. दूसरे देशों ने इन मुद्दों से निबटने के लिए अनूठे मॉडल अपनाए हैं. मसलन, कनाडा 30 फीसद राजस्व से हाथ धो बैठने वाली कंपनियों को वेतन बिल में सब्सिडी की पेशकश कर रहा है. भारत में दो वजहों से यह बहुत जोखिम भरा होगा. एक, विश्वसनीय डेटा का न होना और दूसरा, धोखाधड़ी की हमेशा मौजूद आशंका.

मध्यम से लंबे वक्त के समाधानों में जिस एक क्षेत्र में ध्यान देने की जरूरत है, वह है विदेशी निवेश. अभी तक वैश्विक निवेशक कुछ हद तक कानूनों की जटिलताओं की वजह से भारत में निवेश करने से कतराते रहे हैं. हालांकि देश ने स्मार्टफोन सरीखे इलेक्ट्रॉनिक्स में निवेश आकर्षित करने में प्रगति की है, लेकिन ये क्षेत्र इतने छोटे हैं कि जीडीपी की सुई को वाकई ज्यादा आगे नहीं बढ़ा सकते. ज्यादा बड़े उद्योगों के लिए भी ऐसे ही प्रोत्साहन की जरूरत है.

कइयों का कहना है कि रिजर्व बैंक और वित्त मंत्रालय को मांग को मजबूत करने के लिए रकम झोंकने के तरीकों की पड़ताल करनी चाहिए. इनमें हाथ में ज्यादा नकदी रखने के लिए मुद्रा की ज्यादा छपाई सरीखे उपाय भी शामिल हैं. कुछ अर्थशास्त्रियों की दलील है कि सुस्त या मंदी की आशंका से ग्रस्त अर्थव्यवस्था के लिए मांग की मजबूती की खातिर अधिक मुद्रा का प्रवाह कोई बुरी बात नहीं है. दूसरों का कहना है कि ऊंची मुद्रास्फीति केवल उस मुद्रास्फीति से कमाने वालों को फायदा पहुंचाती है. सबनवीस कहते हैं, ''जब खाद्य कीमतें ऊंची हैं, तो विक्रेता को फायदा मिलेगा. यह मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्रोत्साहन हो सकता है.'' रिजर्व बैंक अपनी सालाना रिपोर्ट में और ज्यादा वित्तीय विकल्पों की साफ जरूरत को सामने रखती है और कहती है कि बैंक फाइनेंस के विकल्पों को बढ़ावा देना होगा, जिनमें कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार भी शामिल है. वह ऐसी विशेषीकृत एनबीएफसी की जरूरत को भी सामने रखता है, जो बुनियादी ढांचा वित्तीय कंपनियों के तौर पर वर्गीकृत हों ताकि बुनियादी ढांचे की विशिष्ट वित पोषण की समस्याओं से निबट सकें.

अंतिम समाधान चाहे जो हो, सरकार को अपनी रणनीति को बहुत अच्छी तरह नापना–तौलना होगा. कुछ का कहना है कि मौजूदा मंदी व्यावसायिक चक्र की वजह से नहीं है, इसलिए सुधारों को तब तक इंतजार करना चाहिए जब तक अर्थव्यवस्था पूरी तरह खुल नहीं जाती और असली नुक्सान का पता नहीं चल जाता. एक वैश्विक बैंक से जुड़े एक अर्थशास्त्री आगाह करते हैं, ''अगर हम व्यावसायिक चक्र की मंदी के लिए ज्यादा माकूल नीतियों को अभी अमल में लाते हैं तो हो सकता है बाद में हमें पता चले कि हम गलत राह पर दौड़ रहे थे.''

बहरहाल, भारतीय अर्थव्यवस्था अपने अब तक के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही है. यह पहले ही सुस्ती की हालत में थी जब कोविड–19 ने इसे बिल्कुल कगार पर ही धकेल दिया. इसलिए इसका इलाज और भी मजबूत करना होगा. सरकार को गहराई से समझने की जरूरत है कि आबादी के तमाम तबके किस तकलीफ से गुजर रहे हैं. फिर अगर उसे कोविड के बाद के नए भारत का निर्माण करना है तो निश्चित डेटा तैयार करना होगा, लक्ष्यबद्ध नीतिगत हस्तक्षेप करने होंगे और प्रक्रियाओं को सरल बनाना होगा. कोविड–19 ने भारतीय अर्थव्यवस्था को फिर से तैयार भले ही करने दिया हो, लेकिन इस संकट को अवसर में बदलने के लिए नीति निर्माताओं को रफ्तार बनाए रखनी होगी और फुर्ती तथा मुस्तैदी से इसका जवाब देना होगा. तभी आगे की राह खुलेगी. ■

क्या उबर पाएगा हिंदुस्तान?

पहले से ही संकटों में घिरी भारत की अर्थव्यवस्था को कोविड ने जोरदार झटका दिया है और देश के सामने एक बड़ी मंदी मुंह बाए खड़ी है. *इंडिया टुडे* के अर्थशास्त्रियों का बोर्ड (बीआइटीई) इस बात का अंदाजा लगा रहा है कि यह कितने दिनों तक चलने वाला है और इस बीमार अर्थव्यवस्था को चंगा करने के लिए उनकी क्या सलाह है

डी.के. श्रीवास्तव
चीफ पॉलिसी एडवाइजर अर्न्स्ट ऐंड यंग

प्रणब सेन
कंट्री डायरेक्टर इंडिया टीम, इंटरनेशनल ग्रोथ सेंटर

डी.के. जोशी
मुख्य अर्थशास्त्री, क्रिसिल

सौम्य कांति घोष
चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया

प्र.

क्या भारतीय अर्थव्यवस्था मंदी से गुजर रही है? आपके अनुमान के मुताबिक, यह कब तक खत्म हो सकता है?

● मैत्रीश घटक

हां, हर संकेतक यही कहता है. अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के मुताबिक, 2020-21 के दौरान देश की अर्थव्यवस्था 4.5 फीसद सिकुड़ जाएगी, जबकि नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च (एनसीएईआर) का पूर्वानुमान है कि कोई बहुत बड़ा प्रोत्साहन न मिले तो यह सिकुड़न 12.5 फीसद तक हो सकता है. 2020-21 की पहली तिमाही में विकास दर के आकलन का केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन (सीएसओ) का आंकड़ा जल्द ही आने वाला है और ऐसा लग रहा है कि यह भी नकारात्मक ही होगा. हर तरफ से, 2020-21 की पहली तिमाही में जीडीपी के आकार में कमी का अंदाजा महत्वपूर्ण रूप से सामने आया है. इसकी पुष्टि दूसरे आर्थिक संकेतकों से भी होती है, जिनमें विश्व बैंक के अध्ययन के मुताबिक, बिजली की खपत के सैटेलाइट चित्र भी शामिल हैं. ऐसे में दूसरी तिमाही में विकास दर के सकारात्मक होने का अंदाजा लगाना भी मुश्किल ही है और दो लगातार तिमाहियों में सिकुड़न को मंदी माना जाता है. यह कहना कठिन है कि यह कब खत्म होगा. जब तक महामारी को वैश्विक स्तर पर और भारत में नियंत्रित नहीं किया जा सकेगा, तब तक अर्थव्यवस्था के पटरी पर लौट आने की उम्मीद कम है.

● डी.के. श्रीवास्तव

भारत की वृद्धि के 2020-21 की पहली और दूसरी तिमाही में कम होने के अंदेशे हैं. विश्व बैंक और आइसीआरए के मुताबिक, पूरे साल भर में, कई बहुपक्षीय संस्थाएं और रेटिंग एजेंसियां 3.2 फीसद से 9.5 फीसद तक के संकुचन की भविष्यवाणी कर रही हैं. असल में, वित्तीय वर्ष के सभी चारों तिमाहियों में यह सिकुड़न देखने को मिल सकती है. बहरहाल, मुझे उम्मीद है कि भारतीय अर्थव्यवस्था कम से कम 2020-21 की चौथी तिमाही से सराकात्मक विकास दर की राह पर चल पड़ेगी.

● प्रणब सेन

भारतीय अर्थव्यवस्था पूरी तरह से मंदी के दौर से गुजर रही है. वित्त वर्ष 21 की पहली तिमाही में यकीनन 20 फीसद के आसपास सिकुड़न दिखेगी और दूसरी तिमाही में भी, 5 से 10 फीसद की कमी दर्ज की जाएगी. यह मंदी कम से कम एक और तिमाही तक जारी रहेगी क्योंकि मुझे अंदेशा है कि तीसरी तिमाही में भी विकास दर नकारात्मक ही रहेगी. चौथी तिमाही में, हम बेस इफेक्ट की वजह से हल्की-फुल्की सकारात्मक विकास दर देख पाएंगे लेकिन महामारी लंबे समय तक चलती रही तो यह भी बदल जाएगा.

> **“वैसे अर्थव्यवस्था में अप्रैल की भारी गिरावट के मुकाबले सुधार दिखा, फिर भी यह आम दिनों के कारोबार से बेहद नीचे है. हालात ऐसे ही रहेंगे जब तक वैक्सीन नहीं आती”**
>
> **—डी.के. जोशी**

● डी.के. जोशी

भारत जैसे विकासशील देशों में मंदी दुर्लभ ही होती है. आजादी के बाद से, हमने पांच मंदी ही देखी हैं जब पूरे वित्त वर्ष में जीडीपी कम हो गई हो. अगर हम किसी वित्तीय वर्ष में जीडीपी में विकास दर कम होने के संदर्भ में मंदी को देखें तो हमारे सामने यह मंदी स्पष्ट रूप से दिख रही है. क्रिसिल को अंदेशा है कि पिछले वित्त वर्ष की तुलना में इस साल जीडीपी में 5 फीसद की कमी दर्ज होगी.

पूर्वानुमान का यह काम इस तथ्य से और कठिन हो गया है कि लॉकडाउन के बाद डेटा संग्रह के लिए प्रतिक्रिया दर अनिश्चित हैं और आर्थिक आंकड़े अविश्वसनीय हो गए हैं. पर हम उपलब्ध बिंदुओं को मिला सकते हैं. वैसे अप्रैल में बेहद कड़े लॉकडाउन के बाद से अर्थव्यवस्था काफी खुली है, फिर भी गूगल मोबिलिटी इंडिकेटर ने जून-जुलाई में आवागमन में कोविड-पूर्व के दिनों के मुकाबले भारी कमी दर्ज की है. जब हमने यह समझा कि आर्थिक गतिविधियां रास्ते पर आ रही हैं, टियर 2 और टियर 3 शहरों में कंटेनमेंट उपायों के फिर से लागू किए जाने और कुछ सेवाओं पर जारी बंदिशों (हवाई सेवाओं, खेलों, मनोरंजन और सत्कार) और उपभोक्ताओं के जोखिम न उठाने की प्रवृत्ति ने बंटाधार कर दिया.

मैन्युफैक्चरिंग और सेवाओं के लिए परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (पीएमआइ) अभी भी 50 के नीचे है और यह मंदी की ओर इशारा कर रहा है. हवा की गुणवत्ता और यातायात के आंकड़े सामान्य से कम आर्थिक गतिविधियों की ओर इशारा करते हैं. पेट्रोलियम उत्पादों की खपत, जीएसटी की उगाही और वाहनों का पंजीकरण भी इसी तरह के ट्रेंड को दर्शा रहे हैं. इसलिए, हालांकि अर्थव्यवस्था में अप्रैल की भारी गिरावट के मुकाबले सुधार दिखा, फिर भी, यह अब भी आम दिनों के कारोबार से बेहद नीचे है. फिर भी, हमारे लिए नकारात्मक जोखिम तब तक ऊंचा बना रहेगा जब तक कि कोविड-19 वैक्सीन नहीं खोजी जाएगी और बड़े पैमाने पर इसका उत्पादन नहीं होता.

अभी जो कुछ हम कह सकते हैं: इस तिमाही (जुलाई-सितंबर) के बाद के हिस्सों में अगर यह महामारी अपने चरम पर पहुंच कर ढलान की ओर बढ़ती है तो चौथी तिमाही से जीडीपी वृद्धि थोड़ी सकारात्मक स्थिति की ओर बढ़ेगी.

● सौम्य कांति घोष

हां, अर्थव्यवस्था में मंदी आ गई है और यह दौर कुछ वक्त के लिए बना रह सकता है. हम चौथी तिमाही में बस इसके पटरी पर आने की उम्मीद भर कर सकते हैं. पर इसका सटीक समय बता पाना कठिन है. महामारियों का लंबा इतिहास है, जिनका काल कुछ वर्षों से लेकर कई लहरों के साथ 100 साल तक का रहा है.

प्र. क्या भारत में महसूस की जा रही मंदी दुनियाभर में चल रही गिरावट से अलग है?

● मैत्रीश घटक

भारत में एक बड़ा अनौपचारिक क्षेत्र है, और इसका अनुमान लगाना भी मुश्किल है कि इस पर कितनी बुरी मार पड़ी है. सामान्य तौर पर, सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट और आर्थिक मंदी के लिहाज से ब्राजील, मेक्सिको, और दक्षिण अफ्रीका जैसी ही स्थिति है—कुछ देशों में प्रभाव भारत की तुलना में बदतर है—लेकिन बिगड़ते स्वास्थ्य परिदृश्य को देखते हुए भारत के लिए सकारात्मक संकेत नहीं हैं. इसके अलावा, इस संकट के दस्तक देने से पहले ही भारत आर्थिक मंदी की राह पर था जो स्थितियों में सुधार की संभावना को और खराब करता है.

● डी.के. श्रीवास्तव

महामारी के आक्रमण से पहले ही भारत में आर्थिक मंदी दिखाई दे रही थी. भारत के विकास की संरचनात्मक के साथ-साथ चक्रीय समस्याएं भी हैं. ऐसा बचत और निवेश दरों में लगातार गिरावट, हाल के वर्षों में वास्तविक और नॉमिनल जीडीपी विकास दर में गिरावट और केंद्रीय कर राजस्व की वृद्धि में तेज गिरावट के कारण हुआ. यह सब कोविड के पहले से देखा जा रहा था. महामारी के प्रभाव ने नीति-निर्माताओं को राजकोषीय जवाबदेही एवं बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम के मानदंडों से भी ज्यादा उधार आधारित प्रोत्साहन बढ़ाने को विवश किया. 2020-21 के अंत तक सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में संयुक्त ऋण, एफआरबीएम की 60 फीसद सीमा के करीब 20 फीसद अंक तक अधिक हो सकता है. ऐसी संभावना है कि जब कोविड पर नियंत्रण पा लिया जाएगा, उसके बाद भी भारत की नीतिगत चुनौतियां बनी रहने वाली हैं.

● प्रणब सेन

कोविड-19 प्रेरित मंदी की प्रकृति पूरी दुनिया में एक जैसी है क्योंकि कारण एक ही है—राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन जिसमें जरूरी वस्तुओं और सेवाओं को छोड़कर सभी उत्पादन बंद हैं. भारत की स्थिति थोड़ी अलग है कि क्योंकि यह एक बहुत बड़ा देश और संघीय राज्य है. इन दो विशेषताओं के नतीजतन, महामारी ने अलग-अलग समय में देश के विभिन्न हिस्सों को प्रभावित किया, जिसने राज्य सरकारों को स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन लगाने के लिए प्रेरित किया है. इसके दो प्रभाव हैं: पहला, भारत में लॉकडाउन प्रभाव की अवधि लंबी है; और दूसरा, आपूर्ति श्रृंखला में सुधार की गति अभी भी अपेक्षाकृत धीमी देखी जा रही है. लेकिन केवल भारत में ही ऐसी स्थिति नहीं है. अमेरिका में भी स्थितियां ऐसी ही हैं और वहां भी ऐसे ही परिणाम दिख रहे हैं.

> “कोविड से पहले ही यहां मंदी दिख रही थी. भारत के विकास की संरचनात्मक के साथ-साथ चक्रीय समस्याएं भी हैं”
> —डी.के. श्रीवास्तव

● डी.के. जोशी

कई अन्य एशियाई अर्थव्यवस्थाओं और वैश्विक अर्थव्यवस्था की तुलना में इस बार भारत की अर्थव्यवस्था पर ज्यादा बड़ी चोट पड़ने की आशंका है. यहां तक कि वित्त वर्ष 2009 में वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान भी भारत की जीडीपी में सालाना 3.1 फीसद की वृद्धि हुई थी, जबकि वैश्विक अर्थव्यवस्था में संकुचन देखा गया था. भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था की तुलना में करीब 300 आधार अंक तेजी से बढ़ा था. अब हम इस वित्त वर्ष में 5 फीसद के संकुचन की उम्मीद कर रहे हैं, जो कि 2020 तक एसऐंडपी ग्लोबल के अनुमानित 3.9 फीसद के वैश्विक संकुचन से भी नीचे है.

हालांकि, एसऐंडपी ग्लोबल को उम्मीद है कि मध्यम अवधि में एशिया-प्रशांत अर्थव्यवस्थाओं (चीन और भारत को छोड़कर) में जीडीपी को औसतन 3 प्रतिशत का स्थायी नुक्सान होगा, भारत के लिए हम 10 प्रतिशत का नुक्सान मान रहे हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि भारत ने कमजोर विकेट पर वर्तमान संकट का सामना किया था और उसके पास कम बफर थे. महामारी ने चुनौतियां बढ़ाईं और व्यक्तिगत सुरक्षा को लेकर बदहाली और भय बढ़ा है.

साथ ही, भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था, जहां से जीडीपी का लगभग आधा हिस्सा आता है, अपनी शहरी अर्थव्यवस्था की तुलना में बेहतर है.

● सौम्य कांति घोष

संकेतक बाकी दुनिया के समान ही हैं. पर हमें यह याद रखना चाहिए कि कोविड से पहले जब विश्व अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही थी, हम एक मंदी के दौर में थे. अंतर केवल इतना है कि हमारे पास एक युवा आबादी है, इसलिए हमारे पास तेजी से तंदुरुस्त होने की अधिक संभावना है.

प्र.

आपके विचार में, क्या 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज ने संकट को कम किया?

● मैत्रीश घटक

अब तक यह साफ हो गया है कि 20 लाख करोड़ रु. की बताई गई रकम या 2019-20 में जीडीपी का 10 फीसद का आंकड़ा आर्थिक पैकेज को बढ़ा-चढ़ाकर बताने का मामला है. केंद्र सरकार ने जो तत्काल, (ऐसे उपायों को छोड़कर जो ऋण की गारंटी के माध्यम से भविष्य की देनदारियां बढ़ाएंगे), अतिरिक्त (संकट के आने से पहले जिनका बजट में उल्लेख नहीं था), वित्तीय (इनमें मौद्रिक नीतिगत उपाय शामिल नहीं) संसाधन पेश किए वह बताए गए प्रोत्साहन रकम से बहुत कम हैं और जीडीपी के करीब 1-2 फीसद के आसपास हैं. अब, थोड़ा पैकेज भी बिना पैकेज से बेहतर है, और इस पैकेज के बिना संकट का असर बदतरीन हो सकता था. पर हम सामने रखे गए संसाधनों की मात्रा के संदर्भ में और ज्यादा कर सकते थे, साथ ही नीतियों के मद में विविधता लाई जा सकती थी, जिसमें से एक मांग पक्ष पर अधिक ध्यान देना, मसलन क्या आमदनी, नौकरी या आजीविका में कमी की भरपाई के लिए प्रत्यक्ष आय समर्थन से मदद मिली? जवाब है हां.

● डी.के. श्रीवास्तव

इस पैकेज में मौद्रिक और राजकोषीय दोनों उपायों का समावेश था. इसका अब तक का असर, सीमित रहा है क्योंकि लगातार लॉकडाउन की वजह से अर्थव्यवस्था के बड़े हिस्से पर विभिन्न किस्म की रुकावटें लगी हुई हैं. राजकोषीय प्रोत्साहन से बजटीय राशियों पर अतिरिक्त व्यय, जो जीडीपी के प्रतिशत के रूप में मापा गया है, सीमित रहा है. दूसरे कई देशों की तुलना में, भारत का आर्थिक प्रोत्साहन कम रहा है.

● प्रणब सेन

20 लाख करोड़ रु. का पैकेज बचे रहने और आर्थिक पुनरोत्थान के लिए उपयुक्त है, लेकिन इसमें बड़ी गंभीर कमजोरियां है क्योंकि वित्तीय क्षेत्र में जोखिम उठाने और तनाव का स्तर काफी ऊंचा है, और यहीं से अधिकतर फंड के आने की उम्मीद थी. यही नहीं, यह पूरी तरह से अपर्याप्त और, वास्तव में, रिकवरी फेज के लिए अपर्याप्त भी था, जहां असली जरूरत समुचित वित्तीय प्रोत्साहन मांग पैदा करने की होनी चाहिए थी.

> **“यह 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज बचे रहने और आर्थिक पुनरोत्थान के लिए उपयुक्त है, पर यह पूरी तरह अपर्याप्त हैं”**
>
> **—प्रणब सेन**

● डी.के. जोशी

प्रोत्साहन की कोई राशि महामारी के संकट से बचाने के लिए काफी नहीं है. यह सिर्फ पीड़ा कम कर सकता है. 20 लाख करोड़ रु. के आर्थिक पैकेज (मौद्रिक और राजकोषीय उपायों का मिश्रण) ने थोड़ी-बहुत मदद तो की. केंद्रीय बैंक के उपायों ने वित्तीय स्थिति को सहज बनाने में मदद की और वित्तीय मदद कमजोर वर्गों को सीधे दी गई. जैसा कि पहले बताया गया है, और अधिक किए जाने की जरूरत है, जिसकी सीमा सरकार की इच्छा और अपनी वित्तीय क्षमता में अधिकतम बिंदु तक जाने से तय होगी.

● सौम्य कांति घोष

20 लाख करोड़ रु. में से, 40 फीसद तरलता आरबीआइ के जरिए डाली गई. बाकी, ऐसी गारंटी और कृषि क्षेत्र में सुधार थे जिन्होंने बैंकों को इसकी छूट दी कि वह एमएसएमई सेक्टर की कमजोर पड़ रही इकाइयों को कर्ज दे सकें. यह ठीक रहा पर हमें यह निश्चित करने की जरूरत है कि आपूर्ति की अव्यवस्था पूरी तरह मांग की समस्या में नहीं बदले. इस संदर्भ में यह जरूरी है कि एक प्रत्यक्ष राजकोषीय समर्थन को एकीकृत किया जाए.

प्र.

हर तरफ गंभीर आर्थिक पूर्वानुमानों के मद्देनजर, क्या आपको लगता है कि सरकार को अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के तरीकों पर पुनर्विचार करने की जरूरत है? आपका क्या नुस्खा है?

● मैत्रीश घटक

हां, भारत की प्रतिक्रिया मोटे तौर पर आपूर्ति पक्ष को लेकर रही (मसलन, कर्ज गारंटी). लेकिन इस तरह के संकट में, जिसने हर तरफ आमदनी, रोजगार और मांग पर बहुत बुरा असर डाला है, आपूर्ति पक्ष को संचालित करने के लिए नीतियां पर्याप्त नहीं हैं. मेरा मानना है कि मांग पैदा करने वाले उपाय, मसलन प्रत्यक्ष आय हस्तांतरण और करों में कटौती अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए जरूरी हैं. वहीं, इस संदर्भ में दूसरे उभरते विकासशील देशों की तुलना में भारत के कदम सीमित रहे हैं. मेरे ख्याल से तीन त्वरित कदम उठाए जाने चाहिए थे:

1. प्रत्यक्ष आय हस्तांतरण और मनरेगा को अधिक संसाधन आवंटित करना;
2. राज्यों के बकाया राजस्व के हस्तांतरण में तेजी; और
3. सार्वजनिक स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करने के साथ बुनियादी ढांचे पर खर्च करना

● डी.के. श्रीवास्तव

सरकार को इसे अपनी राजकोषीय और मौद्रिक नीति ढांचे को फिर से बनाने के अवसर में

बदल लेना चाहिए ताकि उन्हें और अधिक विकासोन्मुख बनाया जा सके. असल में, हाल के वर्षों में मौजूदा मौद्रिक नीति ढांचे के तहत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआइ) मुद्रास्फीति के अत्यधिक नियंत्रण और कर राजस्व वृद्धि में कमी के कारण वास्तविक और नॉमिनल जीडीपी विकास दर में कमी आई है, जिससे उपलब्ध राजकोषीय भंडार सिकुड़ गया. अगले कुछ वर्षों के लिए विशेष नीतिगत नुस्खा कुछ ऐसा है:

1. केंद्र का राजकोषीय घाटे को लक्ष्य जीडीपी के मौजूदा 3 फीसद की जगह बढ़ाकर 4 फीसद तक कर देना चाहिए और एफआरबीएमए को उसी के मुताबिक संशोधित किया जाना चाहिए. राज्य का कर्ज-जीडीपी लक्ष्य मौजूदा 20 फीसद से बढ़ाकर 30 फीसद तक करना चाहिए

2. मौद्रिक अधिकारियों को औसतन सीपीआइ मुद्रास्फीति को 4 फीसद की बजाए 5 फीसद के लक्ष्य पर रखना चाहिए, जबकि इसमें टोरेलेंट रेंज +/- 2 फीसद पॉइंट होनी चाहिए. राजकोषीय और मौद्रिक नीति परिषद का गठन राजकोषीय और मौद्रिक अधिकारियों के बीच समन्वय के लिए किया जा सकता है

3. 2020-21 और 2021-22 के लिए, नेशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन की तय सूची के अनुसार सरकारी पूंजीगत व्यय पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए, ताकि अधिकतम रोजगार और आउटपुट गुणक सृजित किए जा सकें.

● प्रणब सेन

अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने के तरीके सर्वविदित हैं और इसमें कुछ भी नया नहीं जोड़ा जाना चाहिए. नई चीज सिर्फ यही है कि राजकोषीय अनुशासन की अहमियत से जुड़ा विचार कुछ समय के लिए रोक देना चाहिए. जिन तीन त्वरित कदमों की मैं सिफारिश करूंगा वे हैं:

1. प्रत्यक्ष आय हस्तांतरण को बढ़ाया जाए जिनमें मुफ्त राशन बड़े पैमाने पर शामिल हो

2. इस साल और अगले साल के लिए बड़े पैमाने पर राजकोषीय प्रोत्साहन की घोषणा की जाए, और

3. सार्वजनिक निवेश को तेज करने पर विश्वसनीय तरीके से आगे बढ़ा जाए, राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण चिंता का विषय नहीं होना चाहिए

> **“अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए मांग पैदा करने वाले उपाय, मसलन प्रत्यक्ष आय हस्तांतरण और करों में कटौती जरूरी हैं. इस दिशा में भारत के कदम सीमित हैं”**
>
> **—मैत्रीश घटक**

● डी.के. जोशी

सरकार को अर्थव्यवस्था को समर्थन देने और उसे पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी.

अच्छी खबर यह है कि कृषि से, जो कार्यबल के 40 फीसद हिस्से को सीधे या परोक्ष रूप से सहारा देते हैं, इस साल बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है. एक तरह से, खाद्य सुरक्षा से जुड़े संसाधनों के मसले इससे हल किए जा सकेंगे.

लेकिन गैर-कृषि अर्थव्यवस्था को लगे गहरे झटके को देखते हुए, जीडीपी के 1.2 फीसद प्रत्यक्ष राजकोषीय समर्थन—जो केंद्र के विभिन्न घोषित पैकेजों का कुल जोड़ है—वह असरदार प्रोत्साहन के लिए लिहाज से बेहद कम है. अर्थव्यवस्था को समर्थन की मात्रा इस बात पर निर्भर करेगी कि यह कोविड-19 कितना लंबा चलेगा. कुछ बातें जिसे करने की जरूरत है:

1. यह देखते हुए कि संकट के वक्र ने अभी सरल रेखा में होने और फिर कम होने का कोई संकेत नहीं दिया है, सरकार को अपनी झोली खाली करनी होगी और जरूरतमंद परिवारों को आय का समर्थन (नकद सहायता) देनी होगी, और कमजोर पड़ रहे कारोबारों को राजकोषीय सहायता उपलब्ध करानी होगी ताकि इस संकट से रिकवरी की ओर एक पुल तैयार किया जा सके. मैं सुझाव दूंगा कि अब तक जो कल्पना की गई है, उस पर जीडीपी का कम से कम 1 फीसद अतिरिक्त प्रत्यक्ष राजकोषीय व्यय किया जाए

2. छोटे उद्यमों के लिए कार्यशील पूंजी की जरूरत को पूरा करने की ओर कदम बढ़ाए जाने चाहिए क्योंकि बड़ी कंपनियों ने भुगतान में देरी की है. यह काम बड़ी कंपनियों को कम दरों पर उपलब्ध कराए कर्ज से होगा ताकि वे भुगतान कर सकें

3. इस महामारी के बाद के समय में मांग को पटरी पर लाने के लिए अतिरिक्त खर्च की जरूरत है. उस वक्त, सरकार को इन्फ्रास्ट्रक्चर पर खर्च पर अधिक भरोसा करना चाहिए और उसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए (परियोजनाओं की पहचान करना और अन्य चीजों के साथ उनकी फंडिंग) ताकि अर्थव्यवस्था, विकास के वक्र पर फिर चढ़ने लगे

● सौम्य कांति घोष

हां, हमें नीति निर्माण में नए सिरे से सोचना होगा. इस सिद्धांत को लेकर अब शक होने लगे हैं कि अर्थव्यवस्था 'अदृश्य हाथों' के साथ बेहतर काम करती है. नीति निर्माताओं को अब इस बात पर यकीन हो गया है कि 'लक्षित सरकारी दखल' अधिक बेहतर काम करती हैं. मुझे लगता है कि मौजूदा परिस्थिति में आर्थिक सिद्धांतों पर पुनर्विचार की जरूरत है. हमें जरूरत है:

1. एक बड़े प्रति-चक्रीय राजकोषीय नीति की, जो केंद्र और राज्य दोनों को मदद करे

2. एमएसएमई को समर्थन के माध्यम से जीडीपी के प्रतिशत के रूप में मजदूरी में वृद्धि, मनरेगा में फेरबदल और असंगठित श्रम के लिए नीति, और

3. पावर, टेलीकॉम जैसे क्षेत्रों में सुधार के जरिए निजी निवेशकों की वापसी के लिए उचित वातावरण तैयार करना और तटीय आर्थिक क्षेत्रों के लिए नीति. ■

> **“नीति-निर्माताओं को अब इस बात पर यकीन हो गया है कि लक्षित सरकारी दखल अधिक बेहतर काम करती हैं”**
>
> **—सौम्य कांति घोष**

बराबरी की जंग साल 2018 में मराठा आरक्षण के लिए कांग्रेस और एनसीपी विधायकों ने प्रदर्शन किया, बाद में यह लागू भी हुआ पर अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई चल रही है

मंदार देवधर

खास रपट **डोमिसाइल आरक्षण**

स्थानीय कोटे का शिगूफा

मूल निवास के आधार पर नौकरियों में आरक्षण संविधान के खिलाफ है तो फिर मध्य प्रदेश और बिहार की सरकारों ने अपने प्रदेश के लोगों को सरकारी नौकरी में तवज्जो देने की घोषणा कैसे कर दी?

मनीष दीक्षित

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 18 अगस्त को अपने वीडियो संदेश के बाद ट्वीट करते हैं, ''अपने भांजे-भांजियों के हित को ध्यान में रखते हुए हमने निर्णय लिया है कि प्रदेश में शासकीय नौकरियां अब सिर्फ मध्य प्रदेश के बच्चों को ही दी जाएंगी. इसके लिए आवश्यक कानूनी प्रावधान किया जा रहा है. प्रदेश के संसाधनों पर प्रदेश के बच्चों का अधिकार है.'' शिवराज से पहले 2019 में कमलनाथ प्रदेश की नौकरियों में 70 फीसद स्थानीय लोगों को आरक्षण का ऐलान कर चुके हैं. इससे पहले 1998 में दिग्विजय सिंह सरकार ने 10वीं-12वीं के बाद पांच साल तक प्रदेश में पढ़ाई करने वालों को सरकारी नौकरियों में रखने की व्यवस्था की थी लेकिन ये आदेश अदालत में नहीं टिका इसलिए लागू नहीं हुआ. शिवराज के बाद बिहार सरकार ने भी शिक्षक भर्ती में प्रदेश के अभ्यर्थियों को तरजीह देने का फैसला किया है. सवाल यह उठता है कि मूल निवास (डोमिसाइल) के आधार पर क्या आरक्षण दिया जा सकता है. विशेषज्ञ कहते हैं कि संविधान में इसका कोई प्रावधान नहीं है. लेकिन कोर्ट के आदेश मिले-जुले हैं.

संविधान किसी भी आधार पर भेदभाव की इजाजत नहीं देता है लेकिन भेदभाव मिटाने के लिए और पिछड़े तबके को बराबरी पर लाने के लिए अपवाद स्वरूप दिए गए सरकार को अधिकार के इर्द-गिर्द ही आरक्षण के प्रावधान घूमते हैं. संविधान के मुताबिक, भारत के नागरिक देश में कहीं भी जाकर रह सकते हैं और रोजगार पा सकते हैं. अनुच्छेद 15 में जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव न करने की बात कही गई है. अनुच्छेद 16 (2) में निवास स्थान के आधार पर नौकरी में भेदभाव नहीं किया सकता. न्यायविद कहते हैं कि डोमिसाइल के आधार पर आरक्षण का कानून बनाने का अधिकार राज्यों को नहीं है.

सुप्रीम कोर्ट के फैसले शैक्षिक संस्थानों में दाखिले में स्थानीयता के आधार पर दाखिले को सही बताते हैं लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ही कुछ फैसले नौकरियां सौ फीसद स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित करने को गलत भी ठहराते हैं. यह फैसला आदिवासियों को नौकरी के मामले में आया था. फिर भी मूल निवास के आधार पर नौकरियों में भेद हो रहा है. लगभग सभी राज्यों में एससी-एसटी, ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर तबके के लोगों के लिए आरक्षित पद (मोटे तौर पर 60 फीसद) सिर्फ प्रदेश के लोगों के लिए ही हैं. अन्य प्रदेशों के कोटे वाले आवेदक सामान्य श्रेणी के माने जाते हैं. ऐसा इसलिए है क्योंकि आरक्षण जातियों पर आधारित है और हर राज्य की अपनी-अपनी एससी-एसटी और ओबीसी सूची है. इंदिरा साहनी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की अधिकतम सीमा 50 फीसद तय कर दी है,

डोमिसाइल कोटे की वैधानिकता

सुप्रीम कोर्ट के फैसले

▸ 1995

डी.पी. जोशी बनाम स्टेट ऑफ मध्य भारत के केस में सुप्रीम कोर्ट ने मध्य भारत (आज का मध्य प्रदेश) सरकार के उस फैसले को सही ठहराया जिसमें मेडिकल कॉलेज में सिर्फ मध्य प्रदेश के छात्रों की फीस माफ की थी. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, कुछ छात्रों से फीस लेना और बाकी से न लेना संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं है क्योंकि वर्गीकरण तर्कसंगत है. इसके पीछे बड़ा उद्देश्य है, अपने राज्य की सीमा के भीतर शिक्षा को बढ़ावा देना.

▸ 1985

उच्च शिक्षण संस्थाओं में अभ्यर्थियों का चयन उनके निवास स्थान के आधार पर करना संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन है. लेकिन इस पर कोई रूलिंग नहीं दी थी.

–सुप्रीम कोर्ट (1984 के प्रदीप जैन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में)

▸ 2004

राज्य में रिहाइश की शर्त पोस्ट ग्रेजुएट केस में दाखिले का आधार नहीं हो सकती.

–संविधान पीठ, सुप्रीम कोर्ट (सौरभ चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया)

▸ 2014

डोमिसाइल (स्थायी निवास) की संकल्पना तर्कसंगत नहीं है और संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन है.

–सुप्रीम कोर्ट (चारु खुराना बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के 2014 के फैसले में व्यवस्था)

▸ 2018

किसी राज्य में अनुसूचित जाति की श्रेणी का अभ्यर्थी दूसरे राज्य में नौकरी या पढ़ाई करने जाएगा तो वह उस दूसरे राज्य मे अनुसूचित जाति का नहीं माना जाएगा. अनुसूचित जाति-जनजाति के लोग इस श्रेणी के आरक्षण का लाभ सिर्फ अपने गृह राज्य में ले सकेंगे.

–सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों का फैसला

▸ अप्रैल 2020

सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश हाइकोर्ट के उस आदेश को पलट दिया जिसमें सरकार के आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षकों के 100 फीसद पद आदिवासियों के लिए आरक्षित कर दिए गए थे. जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने 1992 के इंदिरा साहनी मामले का हवाला देते हुए कहा कि आरक्षण 50 फीसद से ज्यादा नहीं हो सकता. उन्होंने कहा कि यह इलाका सौ फीसद आदिवासी आबादी वाला नहीं है इसलिए यह फैसला मेरिट की उपेक्षा करता है.

संविधान के प्रावधान

- अनुच्छेद 16 (1) राज्य के भीतर रोजगार और नियुक्तियों में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर की बात कहता है
- अनुच्छेद 16 (2) कहता है कि किसी भी नागरिक को उसके धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, कुल, जन्मस्थान या इनमें से किसी भी एक के आधार पर रोजगार में भेदभाव नहीं किया जा सकता.
- अनुच्छेद 16 (3) यह अनुच्छेद संसद को राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के किसी वर्ग या स्थानीय निवासियों के लिए नौकरी में प्रावधान के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है.

“अपने भांजे-भांजियों के हितों का ध्यान रखते हुए हमने निर्णय लिया है कि प्रदेश में शासकीय नौकरियां अब सिर्फ मध्य प्रदेश के बच्चों को ही दी जाएंगी. इसके लिए आवश्यक कानूनी प्रावधान किया जा रहा है”

शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश

इसके बावजूद सरकारें इस सीमा को तोड़ रही हैं. इन सभी मामलों को अदालत में चुनौती दी जा चुकी है और केस चल रहा है. आर्थिक आधार पर आरक्षण को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा चुकी है. अब सारी उठापटक अनारक्षित वर्ग में हो रही है.

मध्य प्रदेश में मूल निवासियों को आरक्षण के मसले पर जाने-माने वकील और राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने *इंडिया टुडे* से बातचीत में कहा, ‘‘डोमिसाइल के आधार पर आरक्षण देने के मसले पर सुप्रीम कोर्ट से 1954 से लेकर अब तक कई फैसले आ चुके हैं. इनमें कोर्ट ने कहा है कि डोमिसाइल के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता. सौ फीसद आरक्षण नहीं हो सकता, यह भी सुप्रीम कोर्ट ने ही व्यवस्था दी है.’’

इतना ही नहीं मध्य प्रदेश की घोषणा के बाद तन्खा ने चौहन को भेजे पत्र में कहा है, ‘‘यह घोषणा लुभावनी अवश्य प्रतीत होती है किंतु इसे वर्तमान के धरातल पर उतारने में व्यावहारिक कठिनाइयों की अनदेखी की गई है...आपको इस निर्णय से पूर्व संविधान विशेषज्ञों से राय अवश्य लेनी चाहिए थी.’’ झारखंड में उच्च न्यायालय ने शासकीय नौकरियों में शत प्रतिशत आरक्षण की झारखंड सरकार की कोशिश को असंवैधानिक मानते हुए शासन के आदेश पर रोक लगा दी. इसी तरह सिक्किम सरकार ने भी नौकरियों में 90 फीसद आरक्षण देने की योजना बनाई थी जिसे राष्ट्रपति ने खारिज कर दिया. तन्खा ने बताया कि यह विषय समवर्ती सूची का होने की वजह से राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए गया था.

अब सवाल उठता है कि अगर संविधान में व्यवस्था नहीं है तो फिर राज्य डोमिसाइल या मूल निवास के आधार पर आरक्षण दे कैसे रहे हैं? संविधानविद सुभाष कश्यप कहते हैं कि राज्य अनुच्छेद 16 के प्रावधानों के तहत कुछ वर्गों के लिए ऐसा कर सकते हैं. ये संविधान का थोड़ा सा ग्रे एरिया है. इसी की आड़ में आंध्र प्रदेश ने राज्य के नागरिकों के लिए नौकरियों में 75 फीसद आरक्षण कर दिया. लेकिन मध्य प्रदेश के मामले में सरकारी आदेश नहीं आया है. आदेश आने पर पता चलेगा कि वे किस तरह मूल निवासियों को सौ फीसद आरक्षण के प्रावधान को वैधानिक ठहराते हैं. अरुणाचल प्रदेश में आदिवासियों को नौकरी में 80 फीसद तक आरक्षण पर कश्यप कहते हैं कि एससी-एसटी को आरक्षण दिया जा सकता है और यह भी अनुच्छेद 16 के प्रावधानों के तहत ही

''यह घोषणा लुभावनी अवश्य प्रतीत होती है किंतु इसे वर्तमान के धरातल पर उतारने में व्यावहारिक कठिनाइयों की अनदेखी की गई है. आपको इस निर्णय से पूर्व संविधान विशेषज्ञों से राय अवश्य लेनी चाहिए थी''

विवेक तन्खा, सांसद, राज्यसभा

दिया गया है. वे कहते हैं, ''सुप्रीम कोर्ट ने 50 फीसद आरक्षण की सीमा तय की है लेकिन इसके भी अपवाद देखने को मिल रहे हैं.''

इस मामले में जिस तरह रह अदालत के फैसले स्पष्ट नहीं हैं उसी तरह कानून के जानकारों की भी राय बंटी हुई है. सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय कहते हैं, ''सिर्फ डोमिसाइल के आधार पर आरक्षण का मसला अभी तक कहीं से (संसद या सुप्रीम कोर्ट से) सेटल नहीं हुआ.'' जयपुर हाइकोर्ट के अधिवक्ता सुधीर तिवारी का कहना है कि कानूनन डोमिसाइल रिजर्वेशन नाम की कोई चीज नहीं है. वे कहते हैं, ''जब राजनैतिक निर्णय होता है तो उसकी बहुत सी वजहें होती हैं. कई बार नेता घोषणा कर देते हैं, घोषणा के तहत हुआ निर्णय भले ही अदालत से खारिज हो जाए, उनका राजनैतिक मकसद तो पूरा हो जाता है.'' लोकसभा के पूर्व सेक्रेटरी जनरल पी.डी.टी. आचारी कहते हैं, ''डोमिसाइल के आधार पर कानून संसद ही बना सकती है. राज्य सरकार नहीं बना सकती. संसद जब कोई कानून बनाती है तो इसे लागू करने में राज्यों को भी अधिकार मिलता है.''

लेकिन सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील डी.के. गर्ग कहते हैं कि राज्यों को अनुच्छेद 309 के तहत नौकरियों की शर्त तय करने का अधिकार है. राज्य डोमिसाइल के आधार पर कानून बना सकते हैं.

अलबत्ता, मध्य प्रदेश के मामले में आचारी का कहना है कि वहां की सरकार जब आदेश जारी करेगी तब ही सही स्थिति पता चलेगी. संविधान में निवास स्थान के आधार पर आरक्षण की बात अपवाद स्वरूप की गई है. स्थानीय जरूरतों के मुताबिक, कुछ जगहों पर डोमिसाइल आरक्षण की व्यवस्था की गई है. आंध्र में तेलंगाना, महाराष्ट्र में विदर्भ के लिए कुछ प्रावधान हैं और उत्तर-पूर्व के आदिवासी इलाकों में डोमिसाइल आधार पर विशेष आरक्षण लागू हैं. कई आदिवासी प्रधान क्षेत्रों में कानून के बजाए परंपराओं से व्यवस्था चल रही है तो ऐसा स्थानीयता के आधार पर ही हो रहा है.

राजस्थान में भी सीमा से परे जाकर आरक्षण दिया जा रहा है. राजस्थान में ट्राइबल सब प्लान (टीएसपी) एरिया में आदिवासियों को 45 फीसद आरक्षण दिया गया है. इन इलाकों में अनारक्षित श्रेणी में भी स्थानीय लोगों का कोटा है. जाति आधारित आरक्षण के खिलाफ काम कर रही संस्था समता आंदोलन के अध्यक्ष पाराशर नारायण शर्मा का कहना है कि डोमिसाइल के आधार पर आरक्षण देना सीधे तौर पर संविधान के प्रावधानों के खिलाफ है. वे कहते हैं, ''अदालतें भी कई बार नोटिस देकर मामला लटका देती हैं उस पर स्टे नहीं देती हैं. राजस्थान में गूजरों को आरक्षण दिया गया. हम दो बार इसके खिलाफ कोर्ट गए और इसे रद्द किया जा चुका है. लेकिन फिर आरक्षण दे दिया गया. हमने फिर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई कि राज्य के मुख्यमंत्री लगातार कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं लेकिन उस रिट में सवा साल हो चुके हैं अभी तक नोटिस जारी नहीं हुआ है.''

शिक्षा में डोमिसाइल के आधार पर आरक्षण मौजूद है. 1984 के प्रदीप जैन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऑल इंडिया कोटा की व्यवस्था की ताकि राज्यों को उनकी सीमा में आने वाले मेडिकल कॉलेजों में डोमिसाइल और स्थानीय संस्थान कोटे के जरिए 100 फीसद सीटें आरक्षित करने से रोका जा सके. मौजूदा समय में मेडिकल कॉलेजों में 15 फीसद सीटें ऑल इंडिया कोटे के लिए हैं. यानी इन सीटों पर दूसरे राज्यों के विद्यार्थी दाखिला ले सकेंगे. एनआइटी, मेडिकल कॉलेज जैसी अन्य शैक्षिक संस्थाओं में भी डोमिसाइल कोटा हैं.

पिछले डेड़ साल के भीतर मध्य प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र, हरियाणा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश मूल निवासियों को सरकारी-प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण का प्रवाधान या ऐलान कर चुके हैं जो कि लागू होने के विभिन्न चरणों में हैं. गुजरात, गोवा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड आदि राज्य भी स्थानीय निवासियों को प्राइवेट सरकारी नौकरियों में आरक्षण दे रहे हैं. राज्यों ने ब्लू कॉलर जॉब तो राज्यों के लिए ही आरक्षित किए हैं. मूल निवासियों को नौकरी में तरजीह देने के लिए राज्य स्थानीय भाषा में दक्षता की शर्त जोड़ते हैं. जानकार मानते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में स्थानीय लोगों के लिए नौकरियां आरक्षित करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि कंपनियां जरूरत पड़ने पर भर्ती करती हैं न कि नौकरी का सालाना अभियान चलाती हैं. गुजरात में स्थानीय कंपनियों को सरकारी छूटों का लाभ तब देने का प्रावधान है जब वे तय संख्या में स्थानीय लोगों की भर्ती करें. व्यवहारिक रूप से यह संभव नहीं है. गुजरात और महाराष्ट्र प्रवासियों को रोजगार देने के मामले में सबसे आगे हैं.

बाहरी राज्यों के लोगों के नौकरी करने का व्यावहारिक पक्ष भी है. शर्मा कहते हैं कि नौकरियों में पांच से सात फीसद ही दूसरे प्रदेश के लोग हैं. राजस्थान में सात लाख सरकारी कर्मचारी हैं, इनमें से 35-36 हजार से ज्यादा बाहरी राज्यों के नहीं हैं. लोग अपने राज्य में रहना चाहते हैं. सीमावर्ती जिलों में बाहरी राज्यों के लोगों की नौकरी में दिलचस्पी रहती है जैसे धौलपुर आदि. लेकिन गुजरात की सीमा पर ऐसा नहीं है. गुजरात से बमुश्किल ही कोई नौकरी करने राजस्थान आता है. वहां के लोग बिजनेस ज्यादा करते हैं.

मध्य प्रदेश के मामले में मुख्यमंत्री ने घोषणा शायद उपचुनाव के लिहाज से की है क्योंकि जिस ग्वालियर-भिंड इलाके की सीटों में उपचुनाव होने हैं, वहां पुलिस भर्ती में पड़ोसी राज्यों के लोग ज्यादा बाजी मार ले जाते हैं. डोमिसाइल के आधार पर आरक्षण पर कानूनी स्पष्टता अपरिहार्य है चाहे वह संसद तय करे या सुप्रीम कोर्ट. बहरहाल, 27 अगस्त 2020 को सुप्रीम कोर्ट में पांच जजों की संविधान पीठ ने फैसले में कहा कि वंचित तबकों को बराबरी पर लाने और असमानता दूर करने के लिए राज्य आरक्षण दे सकते हैं और सकारात्मक कदम उठाने में कोई संवैधानिक बाधा नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने एससी-एसटी आरक्षण में उप वर्गीकरण के लिए कही है. लेकिन इसकी व्याख्या और भावार्थ राज्यों को आरक्षण देने के व्यापक अधिकार की ओर भी इशारा करते हैं. देखते हैं, राज्य किस तरह कदम उठाते हैं. ■

सभी फोटोः मनीष अग्निहोत्री

संकट में ही निकला समाधान

उत्तर प्रदेश सरकार ने सबसे ज्यादा रोजगार देने वाले क्षेत्र एमएसएमई पर दिया विशेष ध्यान. नतीजाः महामारी के दौरान कारोबार के साथ ही रोजगार के अवसर भी बढ़े

आशीष मिश्र

पश्चिमी यूपी के संभल जिले की पहचान यहां भैंस की सींग से बनने वाले हैंडीक्राफ्ट से रही है. पिछले 50 वर्षों से यहां पर भैंस की सींग से शर्ट में लगने वाले बटन बनाने का काम हो रहा है. संभल से कच्चा बटन चीन की कंपनियां खरीद लेती हैं. ये कंपनियां इन बटन की बेहतर फिनिशिंग करके अमेरिका, यूरोप और भारत में महंगे दामों पर निर्यात करती हैं. भारत के साथ बढ़ते विवाद के चलते संभल ने चीन के साथ सारे व्यापारिक रिश्ते तोड़ लिए हैं. यहां के व्यापारियों ने अपना कच्चा माल चीनी कंपनियों को बेचने से मना कर दिया है. व्यापारियों के जज्बे को देखते हुए यूपी के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग (एमएसएमई) विभाग ने संभल जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर सरायतरीन इलाके में बटन की फिनिशिंग के लिए अत्याधुनिक विदेशी मशीनें लगाने की तैयारी शुरू कर दी है. करीब 10 करोड़ रु. वाले इस प्रोजेक्ट में राज्य सरकार की हिस्सेदारी 9 करोड़ रु. और स्थानीय उद्यमियों ने जमीन के साथ बाकी एक करोड़ रु. का इंतजाम किया है. संभल के बड़े बटन व्यवसायी शोएब यूसुफ कहते हैं, ''देश-विदेश में जो महंगे चाइनीज बटन बिकते थे वे सभी कच्चे रूप में संभल से ही खरीदे जाते थे. संभल में भी फिनिशिंग की आधुनिक मशीनें लग जाने के बाद यहां के बटन पूरी दुनिया में धूम मचाएंगे. इससे संभल को पूरे विश्व में नई पहचान मिलेगी.''

संभल से करीब 300 किलोमीटर दूर ताजनगरी आगरा में चमड़ा व्यवसाय से जुड़े उद्योगपति वर्षों से अपने उत्पादों की जांच के लिए चेन्नै या फ्रांस-जर्मनी की प्रयोगशालाओं का मुंह ताकते थे. बाहरी लैब की जांच में न केवल समय अधिक लगता था बल्कि यह पूरी प्रक्रिया काफी खर्चीली भी

स्वदेशी सुविधा आगरा में फुटवियर और लेदर टेस्टिंग लैबोरेटरी

पुराना उद्यम संभल की एक इकाई में जानवरों की सींग से बटन का निर्माण

थी. 'उत्तर प्रदेश निर्यात अवस्थापना विकास योजना' के तहत आगरा-मथुरा हाइवे पर 21 किलोमीटर दूर सिंगना इलाके में देश की अत्याधुनिक टेस्टिंग लैब बनाई गई है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 7 अगस्त को इस लैब का लोकार्पण किया और इसके साथ ही आगरा के चमड़ा व्यवसाइयों की दौड़भाग को भी विराम लगा. आगरा के मशहूर चमड़ा व्यवसायी पूरन डावर बताते हैं, ''लेदर, फुटवियर कंपोनेंट, गारमेंट और टेक्सटाइल में एक हजार तरह की हाइ रिस्क केमिकल और फिजिकल जांच की विश्वस्तरीय सुविधा शुरू होने से आगरा से चमड़ा उत्पादों के निर्यात में तेजी आएगी.'' साढ़े पंद्रह करोड़ रु. की इस लैब के लिए धनराशि का 80 फीसद हिस्सा राज्य सरकार ने दिया है. स्थानीय उद्योगपतियों ने जमीन के साथ बाकी 20 प्रतिशत राशि का इंतजाम किया है.

कोरोना संक्रमण के दौरान बने माहौल में उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश में एमएसएमई की फौज का इस्तेमाल प्रदेश के औद्योगिक विकास की गति को बढ़ाकर रोजगार की संभावनाएं पैदा करने के लिए कर रहे हैं. नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस (एनएसएसओ) के 73वें (2015-16) राउंड के नवीनतम आंकड़ों के मुताबिक, यूपी में ऑन एकाउंट एंटरप्राइज (ओएई), मतलब ऐसे उद्यम जो एक भी कर्मचारी को नौकरी पर रखे बगैर चल रहे हैं, की कुल संख्या 78,74,711 हैं. 'एस्टैब्लिशमेंट', यानी ऐसे उद्यम जिनमें कम से कम एक कर्मचारी को नौकरी मिली है, की संख्या 11,25,051 है. वहीं केंद्रीय एमएसएमई मंत्रालय में 'उद्योग आधार मेमोरेंडम' (यूएएम) के तहत यूपी में रजिस्टर्ड इकाइयों की संख्या 8,92,029 है. एमएसएमई की इतनी बड़ी संख्या के बल पर यूपी सरकार प्रदेश में औद्योगिक विकास को तेज करना चाहती है.

आर्थिक पैकेज की संजीवनी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संकट के बीच 12 मई को लाकडाउन चौथी बार बढ़ाने की घोषणा के साथ 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' के लिए 20 लाख करोड़ रु. के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया था. प्रधानमंत्री के आर्थिक पैकेज की घोषणा के तुरंत बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एमएसएमई विभाग के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह और तत्कालीन प्रमुख सचिव (अब अपर मुख्य सचिव) एमएसएमई नवनीत सहगल को आत्मनिर्भर भारत योजना का लाभ यूपी के उद्यमियों दिलाने के लिए युद्धस्तर पर कार्य करने का निर्देश दिया था. लोकभवन के सी ब्लॉक के पहले तल पर बैठने वाले एमएसएमई विभाग के अपर मुख्य सचिव सहगल ने पूरी रात अपना दफ्तर खोलकर बैंक और उद्यमियों के बीच समन्वय स्थापित किया. प्रधानमंत्री की घोषणा के महज 24 घंटे के भीतर मुख्यमंत्री ने यूपी के 56,754 एमएसएमई उद्यमियों को 2002.49 करोड़ रु. के ऑनलाइन ऋण वितरित किए. इस प्रकार लॉकडाउन अवधि में उद्यमियों को इतनी बड़ी संख्या में ऋण वितरित करने वाला यूपी पहला राज्य बन गया. इसी दिन 14 मई को मुख्यमंत्री ने लोगों को रोजगार दिलाने के लिए ऑनलाइन 'स्वरोजगार संगम' कार्यक्रम का भी आयोजन किया. इसमें 56,754 एमएसएमई इकाइयों में करीब दो लाख से अधिक कामगारों को रोजगार के अवसर मुहैया कराए गए. एमएसएमई विभाग 'ऑन एकाउंट एंटरप्राइज' और 'एस्टैब्लिशमेंट' श्रेणी के उद्यमों में कम से कम एक व्यक्ति को रोजगार दिलाने की व्यवस्था कर कुल 90 लाख रोजगार करने की दिशा में भी कार्रवाई कर रहा है. एमएसएमई विभाग यूपी में अब तक 2,71,473 नई इकाइयों को 8,949 करोड़ रु. का ऋण बैंकों के सहयोग से वितरित करा चुका है.

''देश-विदेश में जो महंगे चाइनीज बटन बिकते थे वे सभी कच्चे रूप में संभल से ही खरीदे जाते थे. यहां फिनिशिंग की आधुनिक मशीनें लग जाने के बाद यहां के बटन पूरी दुनिया में धूम मचाएंगे.''
शोएब यूसुफ, बटन व्यवसायी

उद्योगों को ऑनलाइन प्लेटफार्म

लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने 7 अगस्त को एमएसएमई विभाग की ओर से संचालित हस्तशिल्पियों के कौशल विकास की प्रशिक्षण योजना, अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए प्रशिक्षण योजना और 'एक जिला, एक उत्पाद' (ओडीओपी)-विपणन योजना की ऑनलाइन प्रक्रिया की शुरुआत की. उद्योगों को अधिक से अधिक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए ई-बे के साथ समझौता किया गया है. एमएसएमई विभाग की बदली कार्यप्रणाली के

मुख्य आर्किटेक्ट अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल बताते हैं, ''एमएसएमई विभाग की सभी प्रक्रियाएं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आने से उद्यमियों को अनावश्यक दौड़-भाग नहीं करनी पड़ रही है. इसने उद्यमियों के बीच राष्ट्रीय स्तर पर यूपी की एक अलग छवि बनाई है.'' लघु उद्योगों को तकनीकी जानकारियां मुहैया कराने के लिए एमएसएमई विभाग ने ''डॉ. ए.पी. जे. अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी'' (एकेटीयू) के साथ एमओयू किया है. एकेटीयू के कुलपति प्रो. विनय कुमार पाठक बताते हैं, ''विश्वविद्यालय से जुड़े 756 कॉलेजों के विद्यार्थी न केवल ओडीओपी योजना से जुड़ेंगे बल्कि इनोवेशन, इन्क्यूबेशन और स्वरोजगार को बढ़ावा देने की दिशा में भी काम करेंगे.''

▲ **छोटों को बड़ी मदद** मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एमएसएमई मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह और अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल की मौजूदगी में उद्यमियों को ऋण वितरित करते

संकट में सहारा बने छोटे उद्यम

कोविड-19 के खिलाफ जंग में एमएसएमई ने यूपी को सहारा दिया है. 25 मार्च से देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा हुए महज एक हफ्ता ही हुआ था कि देश भर में कोरोना संक्रमण के रोकथाम और इलाज में लगे डॉक्टरों और पैरामेडिकल कर्मचारियों के लिए जरूरी 'पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट' (पीपीई) किट की कमी महसूस होने लगी थी. यूपी में भी कोरोना संक्रमण के मामले धीरे-धीरे बढ़ रहे थे. लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने 1 अप्रैल की सुबह अपनी सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों की टीम-11 के बैठक में यूपी में ही पीपीई किट और वेंटिलेटर जैसे जरूरी उपकरणों के निर्माण की योजना बनाने को कहा. इसके बाद एमएसएमई विभाग हरकत में आ गया. विभाग के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह और अपर मुख्य सचिव सहगल ने अन्य अधिकारियों के साथ बैठक करके योजना का खाका खींचा. अगले दिन योजना की जानकारी मुख्यमंत्री को दी गई. उनकी अनुमति मिलते ही यूपी को पीपीई किट के निर्माण में आत्मनिर्भर बनाने की योजना को हकीकत में बदलने के प्रयास शुरू हो गए. सहगल ने प्रदेश में काम कर रहे टेक्सटाइल से जुड़े उद्यमियों से संपर्क किया और उन्हें पीपीई किट निर्माण करने को प्रेरित किया. लॉकडाउन में इन फैक्ट्रियों में काम करने वाले श्रमिकों को उनके गांव से लाने की व्यवस्था हुई. युद्ध स्तर पर कच्चे माल का इंतजाम हुआ. सभी उद्यमियों को स्टैंडर्ड पीपीई किट बनाने का प्रोटोकॉल समझाया गया. 5 अप्रैल को नोएडा, कानपुर और उन्नाव में आधा दर्जन टेक्सटाइल फैक्ट्रिकयों ने पीपीई किट का उत्पादन शुरू किया. आज यूपी में कुल 53 फैक्ट्रियों ने 50 हजार पीपीई किट रोज बनाने की क्षमता हासिल कर ली है. यूपी में कोविड के इलाज में लगे मेडिकल कॉलेज और अन्य अस्पतालों में बड़ी संख्या में प्रदेश में बनने वाली पीपीई किट का उपयोग हो रहा है. प्रदेश सरकार ने यूपी में वेंटिलेटर बनाने वाली नोएडा की एकमात्र इकाई को पुनर्संचालित करने में सहयोग किया है. यह इकाई अब रोज 300 वेंटिलेटर का उत्पादन की क्षमता हासिल कर पूरे देश में इसकी आपूर्ति कर रही है.

आसान हुआ उद्योग लगाना

एमएसएमई के जरिए यूपी में बड़े पैमाने पर रोजगार की संभावनाएं पैदा करने और औद्योगिक विकास का माहौल बनाने के लिए जरूरी है कि अधिक से अधिक मध्यम, लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना की जाए. इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (आइआइए) के यूपी चैप्टर के पूर्व अध्यक्ष सुनील वैश्य बताते हैं, ''प्रदेश में नई एमएसएमई लगाने के लिए 29 विभागों से करीब 80 अनुमतियां लेनी पड़ती हैं. उद्यमी कम से कम छह महीने आधा दर्जन विभागों से अनुमति पाने के लिए चक्कर लगाता रहता है.'' एमएसएमइ उद्योगों की स्थापना में लाल फीताशाही को दूर करने के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए योगी सरकार ने 18 अगस्त को कैबिनेट बाइसर्कुलेशन के जरिए ''सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (अवस्थापना एवं संचालन) अधिनियम-2020'' को मंजूरी दी है. इस नए ऐक्ट के तहत यह व्यवस्था की जा रही है कि जिला उद्योग केंद्र में उद्यमी के निर्धारित प्रपत्र जमा कराने पर 72 घंटे के भीतर स्वीकृति प्रमाणपत्र जारी कर दिया जाएगा. इस प्रमाणपत्र के जारी होने के बाद इकाई को 900 दिन तक किसी भी सरकारी विभाग से किसी भी प्रकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी और वह तत्काल अपना उद्यम शुरू कर सकेगा.

सहगल बताते हैं, ''नए अधिनियम के माध्यम से एक वर्ष में 5 लाख नए रोजगार उपलब्ध कराए जाने का लक्ष्य रखा गया है. इसमें ध्यान रखा गया है कि उद्यमियों की समस्याओं का त्वरित समाधान हो सके.'' निजी इकाइयों और एमएसएमई विभाग के बीच मामले सुलझाने के लिए फैसिलिटेशन काउंसिल का प्रावधान है लेकिन वर्तमान में एक ही फैसिलिटेशन काउंसिल होने के कारण एमएसएमई के काफी मामले लंबित हैं. नए ऐक्ट में मंडल स्तर पर इस तरह की फैसिलिटेशन काउंसिल बनाने का प्रस्ताव है. इससे मंडल स्तर पर एमएसएमई की समस्याओं का मंडलायुक्त की अध्यक्षता में फैसिलिटेशन काउंसिल में निराकरण प्राथमिकता के तौर पर किया जा सके.

कोरोना के बढ़ते संक्रमण और इसके दुष्परिणाम से निबटने के लिए राज्य सरकार अगर एमएसएमई के ढांचे को मजबूत करने में कामयाब हुई तो वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले यह प्रदेश सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी. ■

''नए अधिनियम के माध्यम से एक वर्ष में 5 लाख नए रोजगार उपलब्ध कराए जाने का लक्ष्य रखा गया है. इसमें ध्यान रखा गया है कि उद्यमियों की समस्याओं का त्वरित समाधान हो सके''

नवनीत सहगल, अपर मुख्य सचिव

मयूर
सुरेश

मेहमान का पन्ना

आपराधिक लापरवाही

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 'दंड कानूनों में सुधारों के लिए समिति' बनाई है. यह समिति दंड न्याय के तीन बुनियादी कानूनों, भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय कानून अधिनियम में बदलाव प्रस्तावित करेगी. मामूली से लेकर असाधारण तक ऐसी मिसालों की कमी नहीं, जो बताती हैं कि भारत की दंड संहिता समस्याओं से जकड़ी है. हालिया घटनाओं से पता चला कि गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम सरीखे गैरमामूली दंड कानूनों का इस्तेमाल किस तरह असहमतियों को दबाने के लिए किया जा सकता है. आरोप से पहले गिरफ्तारी और हिरासत जैसी प्रक्रिया से जुड़े नियमित पहलुओं का मतलब यह है कि हजारों लोग पर्याप्त कारण बताए बगैर गिरफ्तार किए और महीनों तक हवालात में रखे जाते हैं. दूसरे मुद्दे भी हैं जिनके बारे में ज्यादातर को कम ही पता है. मसलन, आपराधिक मुकदमे की औसत लंबाई क्या है? या साल-दर-साल पुलिस के हाथों गिरफ्तार लोगों की जातिगत, धार्मिक और लैंगिक बनावट क्या है? दंड प्रक्रिया की बुनियादी जानकारियां हमारे पास नहीं हैं.

ये जानकारियां नहीं होने से समिति परेशान नहीं है. उसने समस्याओं को पहचाने और शायद समझे बगैर ही उनके समाधान प्रस्तावित करना शुरू कर दिया है. समिति की वेबसाइट पर अकेली गड़बड़ी यह पहचानी गई है कि ये कानून उपनिवेश काल में बने थे और मौजूदा भारतीय परिप्रेक्ष्य में गैरमौजूं हैं. यकीनन समस्या को इससे कहीं ज्यादा स्पष्ट करने की जरूरत है.

गड़बड़ियों का गंभीरता से पता लगाने के लिए दंड प्रक्रिया की बारीकी से जांच जरूरी है, और इसलिए किसी को ऐसे अनुसंधान का काम सौंपना समिति का पहला तार्किक कदम होना चाहिए था. मसलन, मुकदमों में इतना लंबा वक्त क्यों लगता है? यह शिकायत बार-बार की जाती है और 'समयबद्ध मुकदमा' पक्का करने के लिए धुंधली आकांक्षाओं के अलावा देरी की वजहों के अनुभव-आधारित प्रमाण की जरूरत है. दंड कानून की जिंदा हकीकत में समिति की दिलचस्पी दिखाई नहीं देती.

यह बेरुखी समिति की अपनी बनावट और उसके काम के तरीके से भी जाहिर होती है. भारत के दंड कानूनों के एक सबसे महत्वाकांक्षी पुनर्मूल्यांकन की शुरुआत कर रही इस समिति में तमाम समुदायों का प्रतिनिधित्व होना और उसे व्यापक सार्वजनिक सलाह-मशविरा करना चाहिए था. चूंकि महामारी के बीचोबीच यह मुमकिन नहीं था, लिहाजा उसे इस काम को व्यापक सर्वे के व्यावहारिक हालात बनने तक टाल देना चाहिए था. इसके बजाए समिति ने इलेक्ट्रॉनिक 'सलाह-मशविरे' की आसान लेकिन अलोकतांत्रिक कवायद शुरू कर दी है.

इन 'सलाह-मशविरों' में हिस्सा लेने के लिए या तो एक ऑनलाइन फॉर्म में कमेंट लिखने होते हैं या समिति की बेवसाइट पर रजिस्टर करके एक विशिष्ट आइडी लेनी पड़ती है, जिसके बाद समिति दंड कानून में सुधारों से जुड़ी सिलसिलेवार प्रश्नावलियां भेजेगी. ये प्रश्नावलियां आम जनता की पहुंच से बाहर हैं और समिति दंड प्रक्रिया से जुड़े उनके अनुभवों को समझने के लिए आगे बढ़कर समाज के तमाम हिस्सों तक पहुंचने की कोई कोशिश नहीं कर रही है. ये ई-कंसल्टेशन भागीदारी को अंग्रेजी में समर्थ ऐसे लोगों तक सीमित कर देते हैं जिन्हें कंप्यूटर, इंटरनेट कनेक्शन और इस संकरी तथा अपारदर्शी प्रक्रिया में शामिल होने के दूसरे साधन सुलभ हैं.

खुद प्रश्नवालियों से भी सुधार के व्यापक लेकिन बेतरतीब तरीके की झलक मिलती है. मसलन, पहली प्रश्नावली (फिलहाल प्रश्नावली की केवल दो शृंखलाएं मौजूद हैं) के भाग ए में दो खंड हैं. एक 'सख्त जवाबदेही' और दूसरा सजाओं के बारे में. दंड कानून में 'सख्त जवाबदेही' के सिद्धांत को लेकर खासा विवाद है, क्योंकि यह मंशा की परवाह न करते हुए लोगों को जिम्मेदार ठहराने की वकालत करता है. समिति ने इस प्रश्न को सामने रखने का फैसला क्यों किया, यह परिप्रेक्ष्य की गैरमौजूदगी में हैरान करने वाला है.

यही नहीं, समिति ने जटिल नैतिक मुद्दों को ऐसे प्रश्नों में बदल दिया है जिनके सरलीकृत उत्तर ही दिए जा सकते हैं. मसलन, भाग सी का प्रश्न 7 पूछता है कि 'क्या आइपीसी का (आत्महत्या को परिभाषित करने वाला प्रावधान) सक्रिय इच्छामृत्यु का अपवाद जोड़ने के लिए संशोधित किया जाना चाहिए?' या प्रश्न 14 इस प्रकार है, ''आइपीसी के तहत (यौन हमले को आपराधिक बनाने वाले प्रावधान में) स्वीकृति का मानक क्या होना चाहिए?' ये पेचीदा सवाल हैं जिनकी परत-दर-परत समझ जरूरी है; ये बहस की मांग करते हैं; इनका जवाब ऑनलाइन फॉर्म में नहीं दिया जा सकता.

गंभीर समाधान के लिए दंड प्रक्रिया की जांच जरूरी है, इसलिए किसी को ऐसे अनुसंधान का काम सौंपना समिति का पहला तार्किक कदम होना चाहिए था

इतनी विशालकाय—और अहम—कवायद के लिए समिति को आदेश दिया गया लगता है कि वह सामुदायिक भागीदारी को सरसरी ढंग से निपटा दे और इने-गिने लोगों को सुलभ इलेक्ट्रॉनिक प्रश्नावली पर भरोसा करे, जो वह कर रही है. जहां अन्य संस्थाओं ने दंड कानूनों में बदलाव सुझाने के लिए बरसों या दशकों तक व्यापक मशविरा और सतर्क बहसें कीं, वहीं यह समिति मानती है कि वह यह भारी-भरकम काम छह महीनों में पूरा कर सकती है. कानूनी सुधार की प्रक्रिया के बारे में दंड संहिता के मूल मसौदा लेखक के चेतावनी से भरे शब्दों को याद कीजिए, ''हम जिस काम में लगे हैं, वह अज्ञानियों और नातजुर्बेकारों को आसान और सीधा-साधा लग सकता है.'' समिति बेहतर जानती होगी, आखिर उसे इतना भारी और दुष्कर काम जो सौंपा गया है.

मयूर सुरेश *लंदन की एसओएएस यूनिवर्सिटी में कानून के लेक्चरर हैं*

इलस्ट्रेशनः तन्मय चक्रवर्ती

असंतोष के केंद्र में मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय, जो हाल ही में नए परिसर में आया है

दोनों फोटोः पंकज तिवारी

पर हमें खेलना है

महामारी के दौरान ऑनलाइन पढ़ाई कम से कम नाट्य विधा के छात्रों को बिल्कुल रास नहीं आ रही. लॉकडाउन के बाद प्रैक्टिकल कक्षाएं करवाने से कम पर वे राजी नहीं. एमपीएसडी में असंतोष खुलकर सामने आया पर एनएसडी और बीएनए में भी खदबदाहट कम नहीं

शिवकेश

नाटक वालों का काम अगर चौतरफा विसंगतियों के खिलाफ आवाज उठाना रहा है तो अब नाट्य विद्या सिखाने वाले प्रतिष्ठानों को चौकन्ना हो जाना चाहिए क्योंकि विरोध का रुख अब उन्हीं की चौखट की ओर मुड़ गया है. बड़े नाट्य प्रशिक्षण संस्थानों में महामारी के चलते ट्रेनिंग के नुक्सान को लेकर छात्रों में उठ रही खदबदाहट ने शिक्षकों-प्रशासकों को सकते में डाल दिया है. और उनमें, सोशल मीडिया पर तेजी से 'शेयर' होते इस असंतोष से निबटने की युक्ति खोजने को मोबाइल संवाद एकाएक बढ़ गया है.

पहली बड़ी दस्तक हुई है उत्तर भारत की सांस्कृतिक राजधानी कहे जाने वाले शहर भोपाल के नौ साल पुराने मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय (एमपीएसडी) में, जहां 26 छात्रों को 6,000 रु. महीने की छात्रवृत्ति के साथ थिएटर में साल भर का डिप्लोमा कोर्स करवाया जाता है. कोविड-19 महामारी के चलते मार्च से ही अस्त-व्यस्त हुए 2019-20 के सत्र में यहां प्रस्तावित चार नाटकों में से सिर्फ दो और 5-6 आंशिक प्रस्तुतियों (सीन वर्क) में से सिर्फ 3 हो पाईं; आठ महीने में ही कोर्स पूरा होने का ऐलान हो गया तो यह 7-8 राज्यों और नेपाल से आए विद्यालय के ज्यादातर निम्न मध्यमवर्गीय छात्रों के लिए एक सदमे की तरह था. थिएटर की तालीम के दो-तहाई से ज्यादा हिस्से का ताल्लुक मंचीय प्रस्तुति से होने के चलते यह उन्हें अपने साथ अन्याय लगा. उनका एक तबका बकाया रह गए व्यावहारिक प्रशिक्षण की भरपाई की मांग करते हुए अनुरोध प्रदर्शन पर उतर आया. पखवाड़े भर (10 से 25 अगस्त तक) चले इस प्रदर्शन में उसे अप्रत्याशित रूप से दिल्ली स्थित राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय (एनएसडी) के और भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान (एफटीआइआइ), पुणे के छात्र संगठनों के अलावा उत्तर भारत के रंगकर्मियों का भी बड़े पैमाने पर समर्थन हासिल हुआ.

रायता फैलता देख आखिरकार, मध्य प्रदेश संस्कृति महकमे के दो अफसरों ने एमपीएसडी परिसर में छात्रों से मिलकर 10 सितंबर से पहले उनकी मांगों पर फैसला लेने का विश्वास दिलाया. इस पहल की कितनी जरूरत थी, छात्र विनय बाघेला की प्रतिक्रिया से इसे महसूस कर सकते हैं, ''हम सब आज बहुत खुश हैं, कम से कम हमारी बात

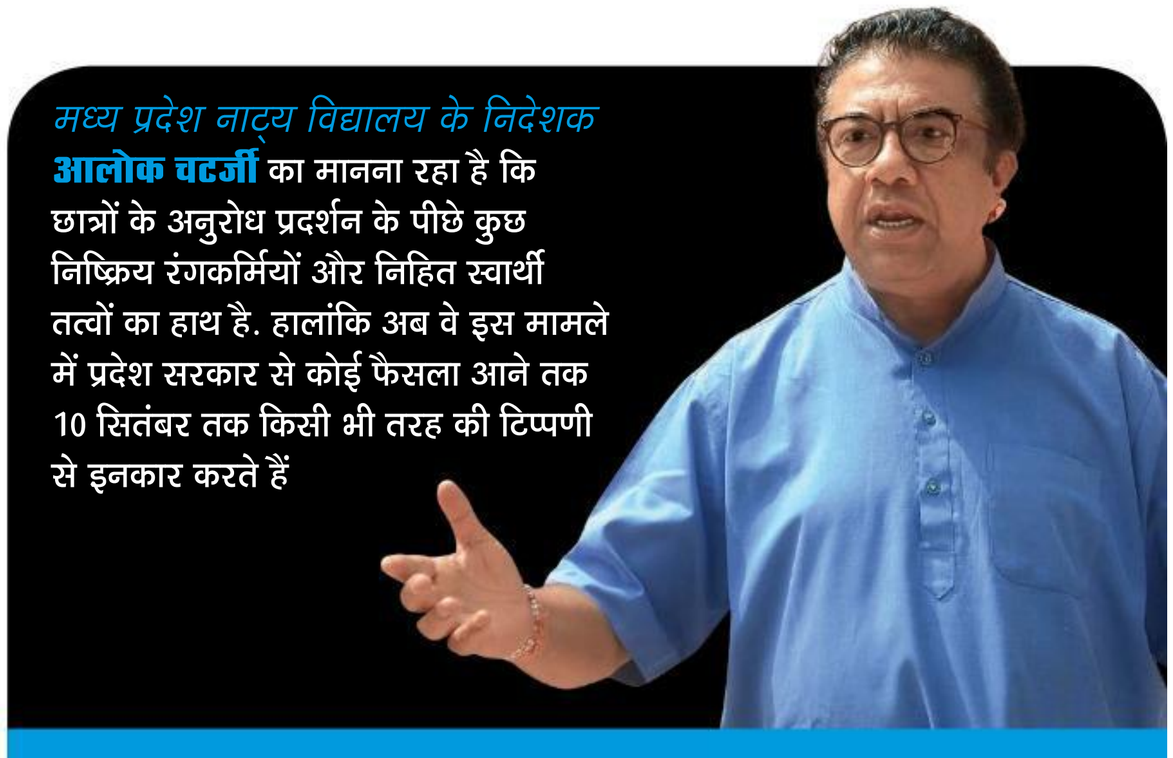

मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय के निदेशक **आलोक चटर्जी** का मानना रहा है कि छात्रों के अनुरोध प्रदर्शन के पीछे कुछ निष्क्रिय रंगकर्मियों और निहित स्वार्थी तत्वों का हाथ है. हालांकि अब वे इस मामले में प्रदेश सरकार से कोई फैसला आने तक 10 सितंबर तक किसी भी तरह की टिप्पणी से इनकार करते हैं

किसी ने संजीदगी से सुनी तो.'' आठ छात्रों को बिना चेतावनी के ही अनुशासनहीनता के आरोप में निकाल देने, फिर उन्हें दो महीने पढ़ाई का अतिरिक्त समय देने, उसके बाद छात्रों के अभिभावकों को पत्र भेज देने से छात्रों और विद्यालय के निदेशक आलोक चटर्जी के बीच अविश्वास खासा गहरा गया था. हालांकि विद्यालय से जुड़ी 'अव्यवस्थाओं' को लेकर छात्रों से उनकी रस्साकशी पहले से ही चली आ रही थी. पिछले बैच के छात्र भी उनकी भाषा/शब्दावली समेत कई मुद्दों को लेकर प्रदर्शन कर चुके थे. चटर्जी का मानना रहा है कि यह कुछ निष्क्रिय रंगकर्मियों और निहित स्वार्थी तत्वों की उनके खिलाफ साजिश का हिस्सा है. वे फिलहाल 10 सितंबर तक टिप्पणी से इनकार करते हैं. पर उनकी यह भी शिकायत रही है कि लोग एनएसडी और बीएनए (भारतेंदु नाट्य अकादमी, लखनऊ) में जो चल रहा है, उस पर तो ध्यान नहीं देते.

तो देखें कि वहां क्या चल रहा है? एनएसडी यानी नाट्य विधा में तीन साल का सघन प्रशिक्षण देने वाला देश का सबसे प्रतिष्ठित संस्थान. 15 मार्च के बाद घर भेज दिए गए यहां के 79 छात्रों में बेचैनी बढ़ रही है. पिछले कुछ दिनों से उनकी ऑनलाइन कक्षाएं शुरू हुई हैं. प्रभारी निदेशक सुरेश शर्मा बताते हैं, ''थ्योरी वाला हिस्सा हम कवर कर रहे हैं. लॉकडाउन खुलने पर हम पूरा समय प्रैक्टिकल पर देंगे तो चीजें काफी हद तक कवर हो जाएंगी. लेकिन इसमें छात्रों को भी सहयोग करना पड़ेगा.'' दरअसल, छात्र ऑनलाइन कक्षाओं से बिल्कुल संतुष्ट नहीं. छात्र संघ अध्यक्ष, तीसरे वर्ष की छात्रा निकिता थुबे स्थिति को बेबाकी और स्पष्टता से रखती हैं, ''छात्रों की राय यही है कि जब भी स्कूल खुले, हमारे तीनों साल के छात्रों का इस अकादमिक सत्र का बचा हुआ सारा कोर्स पूरा कराया जाए.'' छात्र संघ ने ऑनलाइन पढ़ाई के साधनों और उपयुक्त परिवेश को लेकर एक सर्वे करवाया, जिसमें पता चला कि दूरदराज के छात्रों के लिए इंटरनेट की उपलब्धता और घर का माहौल अहम मुद्दा है. निकिता कहती हैं, ''यह इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं है कि किताब लेकर घर के किसी भी कोने में बैठ गए. ऐक्टिंग वाले छात्र के लिए यह सिर्फ एक मोबाइल से पढ़ाई कर लेना कतई मुमकिन नहीं. एनएसडी में देश के हर हिस्से से छात्र आते हैं, और यह मान लेना कि हर किसी के पास अच्छा माहौल और अच्छा इंटरनेट होगा, सब कुछ ठीकठाक चलेगा, यह तो गलत है. हमने इस बारे में विद्यालय को आधिकारिक तौर पर चिट्ठी भी भेज दी है.''

एनएसडी के छात्र बीच के किसी रास्ते के पक्ष में नहीं. विद्यालय प्रशासन के साथ उनकी खतोकिताबत चल रही है. मासिक समीक्षा बैठकों में एक समझौते के तहत वे ऑनलाइन पढ़ाई को तैयार जरूर हो गए लेकिन उन्हें उम्मीद है कि स्कूल खुलने पर, जितना भी समय लगे, उनका कोर्स पूरा कराया जाएगा. द्वितीय वर्ष में तो चार नाटकों में से क्लासिकल और पारसी नाटक ही हो पाए थे. निदेशक शर्मा एक बार फिर अपना पक्ष रखते हैं, ''देखिए, यह असाधारण स्थिति है. हम अपने ही छात्रों का अहित क्यों चाहेंगे? इस तरह की स्थितियां सारे प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स में बनी हैं. सौ फीसद भरपाई तो मुश्किल है पर जैसे किसी नाटक 45 दिन में होता था, अब हम कोशिश करें तो उस पर रोज दो घंटे ज्यादा देकर 30 दिन में कर सकते हैं. लेकिन यह छात्र, शिक्षक और प्रशासन तीनों के आपसी सहयोग से ही संभव हो सकेगा. फिर मुझे यह समझ नहीं आता कि हर कोई एनएसडी को ही विशेष नजरिए से क्यों देखता है? थिएटर के और भी संस्थान हैं. उनमें क्या हो रहा है?''

अ

ब बचा बीएनएए. रुढ़िवादी और यथास्थितिवादी क्षेत्र के इस संस्थान में दो साल के कोर्स में कुल 40 (20+20) छात्र होते हैं. एमपीएसडी प्रकरण ने यहां के छात्रों का भी 'हौसला' बढ़ा दिया है. द्वितीय वर्ष के छात्र बी. कबीर अनुशासनहीनता के आरोप में निकाले जा चुके हैं. यहां के छात्रों ने अकादमिक सत्र ढाई महीने बढ़ाने को चिट्ठी लिखी है. कार्यकारी निदेशक रमेश चंद्र गुप्त बताते हैं, ''हमारे यहां दोनों साल के थ्योरी और प्रैक्टिकल के कोर्स पूरे हो चुके थे. ऐसे में सत्र बढ़ाने का कोई औचित्य बनता नहीं. हम तो ऑनलाइन इम्तहान के बारे में सोच रहे थे, तभी छात्रों की चिट्ठी आ गई. उसका जवाब तैयार कर रहे हैं. लेकिन सत्र बढ़ाया तो नया सत्र शुरू नहीं कर पाएंगे. हमारे पास 40 छात्रों का ही इंतजाम है, 60 को कैसे रखेंगे? फिर भी छात्रों की बात सरकार तक पहुंचा रहे हैं.''

अब दूसरे विश्वविद्यालयों/ कॉलेजों/ उपक्रमों के दर्जन भर से ज्यादा नाट्यकला विभाग भी चौकन्ना होकर 'असंतोष' की स्थिति को भांप रहे हैं. सभी प्रशासकों के लिए यह असहज स्थिति है. हालांकि, कुछ ने सूझबूझ से रास्ता भी निकाला है. दिल्ली के जामिया मिल्लिया इस्लामिया के नाट्यकला विभाग के प्रमुख दानिश इकबाल ने लॉकडाउन लगते ही बीसों छात्रों को भरोसे में लेकर उन्हीं से विकल्प मांगे. ''तय हुआ कि इस बीच हम प्रोडक्शन स्कीम बनवाएंगे, उन्हें अपने ऊपर काम करने को कहेंगे, सोलो नाटक कराएंगे. अब कोई खेत में किसानी करते हुए तो कोई किसी और जगह पर अभिनय करते हुए अपना वीडियो भेज रहा है. विश्वविद्यालय खुलने पर हम आखिरी नाटक भी करवा लेंगे.'' यानी पढ़ाने का उनका रास्ता भी ऑनलाइन का था लेकिन छात्रों को भरोसे में लेने से बात बन गई.

नाट्यकला के बड़े संस्थानों के प्रति सरकारों का रवैया भी बेरुखी वाला रहा है. एनएसडी और बीएनए अगर अरसे से प्रभारी/कार्यकारी निदेशकों के भरोसे चल रहे हैं तो मध्य प्रदेश में सरकारों की अदलाबदली के दौरान नियमों में भारी फेरबदल के चलते एमपीएसडी में भी अव्यवस्था बढ़ी है. उम्मीद करें कि लॉकडाउन खुलने पर इन संस्थानों में भी व्यवस्था सुधरे और छात्रों की पढ़ाई सुचारु हो सके. ■

''सरकार की समिति ने हमारी बात सुनी तो. अभी तक ठीक से कोई हमारी बात ही नहीं सुन रहा था''
विनय बाघेला
छात्र, एमपीएसडी

''देखिए, यह असाधारण स्थिति है. सौ फीसद भरपाई तो मुश्किल है पर हम काफी हद तक चीजें कवर करने की कोशिश करेंगे. लेकिन इसमें छात्रों को भी सहयोग करना होगा''
सुरेश शर्मा
प्रभारी निदेशक, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय

''ऑनलाइन पढ़ाई से छात्र खुश नहीं. यही राय बनी है कि बचा हुआ सारा कोर्स पूरा कराया जाए''
निकिता थुबे
अध्यक्ष, छात्र संघ, एनएसडी

''छात्रों की मांग पर सत्र अगर ढाई महीने बढ़ाया तो नया सत्र हम भला कैसे शुरू कर पाएंगे?''
रमेश चंद्र गुप्त
कार्यकारी निदेशक, बीएनए

सवाल + जवाब

● आपके पिछले उपन्यास *द गर्ल इन रूम 105* की बुनियाद कत्ल पर आधारित थी? आपके अगले उपन्यास का नाम *ऐन अरेंज्ड मर्डर* है. चेतन भगत क्या अपना जॉनर बदल रहे हैं?

कह सकते हैं. भई *ऐन अरेंज्ड मर्डर* है तो चेतन भगत की ही लिखी हुई. इसमें हिंदुस्तानी मिजाज की उलटबासियां, कॉमेडी और एक लव स्टोरी है. यह खांटी थ्रिलर नहीं है. पर बतौर एक लेखक मैं अपराध विधा की ओर बढ़ रहा हूं. आज चीजों से ध्यान बहुत जल्द हट जा रहा है, ऐसे में लड़के के लड़की को पा लेने से ज्यादा उत्तेजक होगा कि लड़के ने लड़की को मारा कैसे.

● कभी आपने राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (एनआरसी) की तुलना अरेन्ज्ड मैरिज से की थी. जब भी आप कोई सियासी रुख अख्तियार करते हैं, आपको अंदेशा होता है कि इससे आपके पाठकों का एक तबका आपसे अलग हो जाएगा?

मैं अब एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गया हूं जहां मैंने खुद को साबित कर दिया है. अगर मुझे लगता है कि कोई जरूरी बात है जिसे कहा जाना चाहिए तो एक ऐसे लेखक के तौर पर जो बड़े पैमाने पर पढ़ा जाता है, मैं वह क्यों न कहूं.

● परिवारवाद/भाई-भतीजावाद और अभिजात तबके का पक्षपात आज राष्ट्रीय चर्चा के विषय हैं लेकिन आप तो इन पर पहले से बोलते आ रहे हैं.

यह मेरा जेहाद है. मुझे लगता है कि बतौर लेखक मैं सामंती ढांचे को तोड़कर भारतीय समाज के लिए अपना योगदान कर सकता हूं. हिंदुस्तानियों को हर चीज एक जातिवादी ढांचे में ढाल देना बहुत भाता है. आप कितने ही कामयाब क्यों न हो जाएं, उस ऊंची ब्राह्मणवादी सतह पर नहीं पहुंच सकते, यह कड़वा सच है. यह सुशांत (सिंह राजपूत) के लिए सच था और यही मेरे लिए भी सच है.

● सोशल मीडिया पर आप अक्सर नफरत का शिकार हो जाते हैं. क्या इसे आप अपनी लोकप्रियता से जोड़कर देखते हैं?

सुशांत की मौत के बाद से मुझे नहीं लगता कि खुद से संवरे लोगों से नफरत करना या उनके काम को खारिज कर देना अब सहज बात रह गई है. अपनी नई किताब को लेकर मैं ट्रोल नहीं हो रहा हूं. संभ्रांत तबका चुप है. सुशांत की मनोदशा का मसला इससे जुड़ा था कि प्रेस में उनके साथ कैसा बर्ताव हुआ.

—श्रीवत्स नेवतिया

शब्दों की बुनियाद कत्ल

चेतन भगत का ताजा उपन्यास अगले महीने आ रहा है. देखें कि इसमें वे प्रेम और नफरत में कैसे संतुलन बिठाने की कोशिश करते हैं

बंदीप सिंह

कम ब्याज दर

5 दिनों में स्वीकृत

कोई प्रोसेसिंग शुल्क नहीं

पांच आकर्षक लाभों के साथ होम लोन!

पीएसबी 59 ऑनलाइन आवेदन की सुविधा

आसान टेकओवर– प्रोसेसिंग शुल्क माफ

आकर्षक शर्तों और न्यूनतम पेपरवर्क के साथ तुरंत होम लोन पाएं

Union Home

- ऑनलाइन लोन आवेदन की सुविधा
- दैनिक कम हो रहे शेष पर ब्याज

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया | Union Bank of India

भारत सरकार का उपक्रम | A Government of India Undertaking

आन्ध्रा Andhra | कार्पोरेशन Corporation

हेल्पलाइन नं.: 1800 208 2244 / 1800 425 1515 / 1800 425 3555 | www.unionbankofindia.co.in

@unionbankofindia @UnionBankTweets UnionBankInsta YouTube UnionBankofIndiaUtube @unionbankofindia

*शर्तें लागू

SBI Home Loans

होम लोन

6.95%* (से शुरू)

अब आपके सपनों का घर

#HoSaktaHai

किसी भी माध्यम से आवेदन करें

योनो में लॉगइन करें

homeloans.sbi देखें

1800112018 पर कॉल करें

एसबीआई की निकटतम शाखा में जाएं

नियम और शर्तें लागू *

प्रतिस्पर्धात्मक ब्याज दर • कम प्रोसेसिंग फीस • कोई गुप्त चार्ज नहीं • कोई प्री–पेमेंट पेनाल्टी नहीं

हमें फॉलो करें

यह प्रोडक्ट निम्न एसडीजी का खाका तैयार करता है और सशक्त भारत की दिशा में योगदान देता है

11 SUSTAINABLE CITIES AND COMMUNITIES

5 GENDER EQUALITY